CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMJK1 User: cci Time: 02-01-2026 23:44 Color:

महानगर > मुंबई > सोमवार, 2 फरवरी 2026 > माघ 13 शक संवत 1947 फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2082 WATCH GOD WATCHDOG वर्ष 77, संख्या 27 > मूल्य ₹5.00 > पेज 14 > आर. एन. आई. पंजीयन नंबर 1613/57 www.nbt.in

NBT
नवभारत टाइम्स

"यह बजट अपार अवसरों का हाइवे है। यह युवा शक्ति का बजट है। इस बजट से युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। - नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर

इनकम टैक्स में बदलाव नहीं, क्योंकि...

2026 के बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर राहत नहीं मिली। वैसे, पिछले साल नई टैक्स रेजीम में 12.75 लाख रु. तक की आय टैक्स फ्री होने और सितंबर में GST सुधारों ने भी गुंजाइश कम कर दी थी। लेकिन...

टैक्स चुकाने में आसानी

टैक्स रिटर्न भरना आसान बनाया गया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का समय और मिलेगा। किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया और टैक्स 10 लाख रुपये तक है तो जेल नहीं होगी। बड़े मामलों में सजा की अवधि भी घटी है।

12.2 लाख करोड़ इन्फ्रा पर खर्च होंगे

वैश्विक अनिश्चितता और तेज आर्थिक विकास को बनाए रखने और लाखों नए रोजगार पैदा करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे पर बजट पिछले साल की तुलना में 9% बढ़ाया है। पिछली बार यह 11.2 लाख करोड़ रुपये था।

न्यू इकॉनमी पर ज़ोर

सेमीकंडक्टर चिप और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे सेक्टरों में चीन, अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में कॉरिडोर बनाने का ऐलान हुआ।

जेनरेशन चेंज बजट

देश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वादा

वो वक्त बदल रहा है, जो बजट का मतलब इनकम टैक्स में बदलाव भर मानता है। सोशल मीडिया पर नई पीढ़ी को समझने की कोशिश करिए। उसे चाहिए, भारत की फ्यूचर प्लानिंग। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी समझती हैं कि पुराने फॉर्म्युले नहीं चलेंगे। इस बार उनके बही-खाते में जेनरेशन चेंज दिखा, जो भारत को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का वादा करता है। नई पीढ़ी पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। उसके लिए शिक्षा, रोजगार और तकनीक की दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। बेहतर जिंदगी की उसकी चाहतों को पूरा करना ही होगा। तभी वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में ही इस बात को साफ कर दिया, यह बजट युवा शक्ति से प्रेरित है।

अंदर के स्पेशल पेजों पर देखें

- F&O पर STT से क्यों बिगड़ा बाजार का मूड?
- यहां और फिन सेक्टरों से बनेगा पैसा?
- इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का सबसे बड़ा दांव
- 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर समेत रेलवे को मिला बहुत कुछ
- MSME सैपिएन, भारत विस्तार, बायोफार्मा से लेकर डिफेंस तक...क्या मिला?
- स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर की त्वरित टिप्पणी पढ़िए
- इनकम टैक्स कानून में क्या है? क्या स्लैब भी बदला है?

इनकम टैक्स में छूट नहीं, लेकिन नियम सरल, विकसित भारत के लिए 'युवा शक्ति' पर ज़ोर

Akhilesh.Singh1@timesofindia.com

■ नई दिल्ली: नॉर्थ ब्लॉक के बनाए नए बने कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला आम बजट रहा। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम में आगामी विधानसभा चुनावों के बावजूद बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किया। पर्सनल इनकम टैक्स में भी कोई छूट नहीं दी, लेकिन आम लोगों से लेकर कंपनियों तक के लिए टैक्स नियमों को आसान बनाने की घोषणा की। पहले के मुकाबले इस बार का बजट कुछ सादा-सा दिखा, लेकिन दुनियाभर में चल रही उथल-पुथल के बीच वित्त मंत्री ने संतुलित राह पर बने रहने का फैसला किया। वहीं 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कई कदम भी उठाए।

सरकार की सोच की झलक वित्त मंत्री के इस जुमले में दिखी, जब उन्होंने कहा कि यह 'युवा शक्ति' को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। यह बात बजट में स्किल डिवेलपमेंट, हायर एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग और AI सहित नई तकनीक पर फोकस में दिखी। इसमें उच्च शिक्षा और कौशल विकास को उद्योगों की जरूरत से जोड़ने पर जोर है। इसके लिए बड़े इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक सेंटर्स के करीब 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात है। 15,000 सेकंडरी स्कूलों में कंटेंट लैब्स बनेंगी। ब्रॉडकास्ट पर फोकस के साथ तीन नए नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ सिनेमैटोग्राफी एजुकेशन ऐंड रिसर्च बनेंगे। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। MSME के हाथ मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड बनाने और ग्रोथ के अगले चरण को रफ्तार देने के लिए MSME चैंपियन बनाने की बात है। इनका देश के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान है और अभी टैरिफ से बने हालात में एक्सपोर्ट के मोर्चे पर चुनौतियां हैं। विदेशी क्लाइंट और टेक दिग्गजों को लंबी अवधि की टैक्स छूट देने से AI, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स और डिजिटल इन्फ्रा के मामले में पकड़ मजबूत होगी। वित्त मंत्री ने कुल 53.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया।

PTI

वित्त मंत्री ने बजट में राजकोषीय घाटे को भी GDP के 4.3% पर लाने का लक्ष्य दिया है।

तेज तरक्की के लिए तीन कर्त्तव्य बताए

वित्त मंत्री ने कहा कि पहला कर्तव्य है उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज करना। दूसरे कर्तव्य के रूप में लोगों की आकांक्षाएं पूरी करनी हैं और उन्हें साझेदार बनाना है, जिससे वे देश की खुशहाली में मजबूत साझेदार बन सकें। तीसरे कर्तव्य में उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास की सोच के अनुसार यह पक्का करना है कि हर परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर को सुविधाएं और अवसर मिलें। पहले कर्तव्य के तहत 7 रणनीतिक सेक्टरों में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर जोर दिया है। दूसरे कर्तव्य में एजुकेशन को रोजगार और उद्योगों से जोड़ने पर फोकस है। तीसरे कर्तव्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने, मेंटल हेल्थ पर जोर है।

5 खास बातें

नई इकॉनमी पर लॉन्ग टर्म फोकस

मोदी की अगुआई वाली NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट को कई तरीकों से देखा गया। मौजूदा चुनौतियों और आर्थिक परिदृश्य के बीच बजट से निकले पांच संकेत और संदेश बता रहे हैं नरेन्द्र नाथ:

1 टेस्ट मैच है, T20 नहीं

भले पूरे देश में अभी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का माहौल बन रहा है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में टेस्ट मैच-सरीखा रुख अपनाया गया। मतलब 'टू द पॉइंट' बजट को धीरे और लॉन्ग टर्म फॉरमेट में देखने-समेटने की कोशिश की गई। मोदी सरकार के पिछले दो कार्यकालों को देखें तो यह सरकार तीसरे साल के बाद चुनावी मोड में जाती है। बजट में खासकर युवा और Gen-Z के नजरिये से भविष्य का विजन और रोडमैप दिखाने की कोशिश की गई।

2 ग्लोबल उठापटक का असर

अभी ग्लोबल स्तर पर आर्थिक और सामरिक हालात बहुत अस्थिर और अनिश्चित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और अन्य मोर्चों पर युद्ध की आशंका से पैदा इन हालात का असर बजट पर भी दिखा। पूरे बजट में बहुत बड़ा जोखिम लेने या नीतिगत स्तर पर आमूलचूल बदलाव की नीयत न दिखाने के पीछे यह बड़ा कारण माना जा सकता है। दरअसल अभी पूरा वैश्विक घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, इस पर कोई एक राय नहीं है।

3 सौगातों की बौछार नहीं दिखी

लोकलुभावन घोषणाओं और सौगातों की बौछार न दिखने की अपेक्षा पहले से थी। वजह यह कि एक साल में केंद्र ने इनकम टैक्स और GST के स्तर पर बहुत बड़ी कटौती की थी। उस कटौती की खुमारी अभी देखी जा रही है। इस बीच केंद्र ने बजट में टैक्स के मोर्चे पर विश्राम करने की मंशा दिखाई है। चूंकि अभी सामने चुनावी चुनौती नहीं है, तो सरकार के लिए यह रुख अपनाना आसान भी रहा।

4 न काहू से दोस्ती, न काहू से बैर

बजट में न तो किसी राज्य को लुभाने की कोशिश की गई, न मिडिल क्लास, महिला, किसान या किसी अन्य तबके को। न किसी पेशे को तरजीह दी गई, न किसी पर बोझ बढ़ाने की मंशा दिखी। STT ने शेयर बाजार का मूड खराब किया, पर जैसे सरकार ने वित्त को दूर करने की कोशिश की, उससे संदेश गया कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी।

5 संतुलन की चुनौती भी दिखी

पहले आर्थिक सर्वे और फिर बजट में आर्थिक स्तर पर मौजूद चुनौतियों का भी संदेश दिया गया। खासकर बढ़ते खर्च और कर्ज के बीच संतुलन बनाने की चुनौती, और राज्यों के बढ़ते खर्च ने जो चिंता बढ़ाई है, उसका असर बजट पर भी दिखा। कहीं न कहीं, बजट में इसके प्रतिकूल असर को रेखांकित करने की कोशिश की गई। पिछले कुछ वर्षों में यह मुद्दा बड़े संकट के रूप में माना जा रहा है।

F&O पर टैक्स बढ़ा | **शेयर बायबैक की कमाई पर कैपिटल गेन का ऐलान भी रास नहीं आया**

शेयर बाज़ार में हाहाकार, सेंसेक्स 1546 अंक गिरा

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई

शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करने वालों पर (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन) टैक्स बढ़ाने और 'शेयर बायबैक' से होने वाली कमाई पर कैपिटल गेन्स के तौर पर टैक्स लगाने का ऐलान हुआ। इन दोनों ही खबरों से शेयर बाजार का मूड बिगड़ गया। सेंसेक्स और निफ्टी करीब 2% तक लुढ़क गए।

सेंसेक्स एक समय 2370 अंक (2.88%) तक गिरकर 80 हजार के अहम स्तर से भी नीचे आ गया था। निफ्टी भी एक समय 749 अंक के करीब यानी 2.95% गिरकर 24,571.75 के निचले स्तर पर आ गया था। बाद में सेंसेक्स कुछ सुधरा और 1,546.84 अंक (1.88%) गिरकर 80,722.94 पर बंद हुआ। लेकिन निवेशकों की पूंजी 9.40 लाख करोड़ रुपये घट गई। निफ्टी भी 495.20 अंक (1.96%) गिरकर 24,825.45 पर बंद हुआ। बजट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है। वहीं, ऑप्शंस प्रीमियम पर इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% करने की बात है।

PTI

सेंसेक्स एक समय 2370 अंक गिरकर 80 हजार से नीचे था। कुछ सुधरकर बंद हुआ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बाद में कहा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग (F&O) में बहुत ज्यादा सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। मकसद यही है कि सेमिक्यूलेटिव ट्रेडिंग से छोटे निवेशक दूरी बनाएं। सरकार डेरिवेटिव ट्रेड के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसमें बड़ा नुकसान उठाने वाले छोटे निवेशक इससे दूर रहें, सरकार यह चाहती है। यह मामूली बढ़ोतरी उन्हें हतोत्साहित करने के लिए की गई है। हम F&O ट्रेड के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन छोटे निवेशकों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में हम कब तक चुप रह सकते हैं? SEBI की स्टडी के मुताबिक, F&O सेगमेंट में 90% से अधिक रिटेल निवेशक नुकसान उठाते हैं।

मोदी सरकार ने 2014 से अब तक कुल 15 केंद्रीय बजट पेश किए हैं, जिनमें 8 बार सेंसेक्स निगेटिव यानी गिरकर बंद हुआ है।

ये चीजें सस्ती

कैंसर की दवाएं...

कैंसर से बचाव की 17 दवाएं, 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं भी ड्यूटी फ्री, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, लेदर, सिंथेटिक जूते, कपड़े, विदेश यात्रा, माइक्रोवेव, फर्मास्ल ड्रमैटेड चीजें, विदेश में पढ़ाई।

ये सामान महंगा

सिगरेट, शराब...

पैटेडियम हाइड्रॉक्साइड समेत कई मिनरल्स, स्कैप, शराब, तेंदू पत्ता, सिगरेट, तंबाकू प्रॉडक्ट, लग्जरी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े, प्रीमियम फुटवियर, कॉफी मशीन, एटीएम या कैश डिस्पेंसर, आयातित सस्ते छाते, विहिकाधार के जानवर, पक्षियों का अचार।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP6 User: cci Time: 02-01-2026 23:05 Color:

बजट ऐसा होना चाहिए जो निवेशकों में भरोसा जगाए और साथ ही गरीबों के हितों की रक्षा करे।

– प्रणव मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति व वित्त मंत्री

नेक इरादे

आज दुनिया जिस जियो-पॉलिटिकल उथल पुथल से गुजर रही है और उससे देश के सामने जो मुश्किलें हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उनसे बाहर निकलने का एक रोडमैप पेश किया। इनमें से सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की है। इस बजट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर जोर दिया गया है। सरकार ने GDP में इसका योगदान 25% तक करने का लक्ष्य रखा है, जबकि अभी तक 20% का लक्ष्य भी हासिल नहीं किया जा सका है।

घरेलू इकॉनमी पर फोकस । इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 6 प्रायॉरिटी क्षेत्रों पर ध्यान दिया। इनमें सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, टेक्सटाइल, MSME और अर्बन इकॉनमिक क्लस्टर्स शामिल हैं। सरकार का फोकस डोमेस्टिक इकॉनमी को और मजबूत करने पर है, ताकि देश को बाहरी झटकों से बचाया जा सके। डेयरी, फिशरीज और एग्रीकल्चर एप्लॉयमेंट को मजबूती देने के लिए भी सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनका पॉजिटिव असर आने वाले वक्त में दिख सकता है।

रोजगार बढ़ाने के उपाय

कैपेक्स पर फोकस । इसके साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का ध्यान बना हुआ है। वित्त वर्ष 2027 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10% की बढ़ोतरी के साथ 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है। पिछले कई वर्षों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तेजी की सरकार की उम्मीद पूरी नहीं हुई है। ऐसे में मजबूत ग्रोथ के लिए वह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर निवेश बढ़ाना जारी रखेगी।

क्रिटिकल सेक्टर । इसके साथ स्ट्रैटिजिक पहलू को ध्यान में रखकर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ जैसे सेगमेंट को बढ़ावा देने की बात भी सरकार ने कही है। कुछ समय पहले जिस तरह से चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई रोक दी थी, उसे देखते हुए यह पहल अहम है। बजट में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, डेटा और क्लाउड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों को लेकर भी ऐलान किए गए हैं, जो तेजी से बदलती दुनिया और जियो-पॉलिटिक्स के लिहाज से अहमियत रखते हैं।

वित्तीय अनुशासन । इस बजट में ग्रोथ की रफ्तार बनाए रखने के साथ सरकार ने फिस्कल डेफिसिट पर निगाहें भी पॉजिटिव घोषणाएं की हैं। वित्त वर्ष 2026 में डेफिसिट जहां GDP का 4.4% रहा, वहीं अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 4.3% का लक्ष्य रखा गया है। भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिहाज से यह आंकड़ा अहम है। रेटिंग मजबूत रहने से घरेलू कंपनियों-संस्थानों की कर्ज जुटाने की लागत कम रहती है।

कंजम्पशन ग्रोथ अहम । भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद कंजम्पशन है। देश की GDP में इसका योगदान 60% के करीब है। पिछले साल के बजट में इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्स माफ कर दिया था। पिछले फेस्टिव सीजन से पहले GST दरों को तर्कसंगत बनाया गया था। साथ ही, रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरों में कटौती के हालिया साइकल में 0.75 बेसिस पॉइंट की कमी की है। इससे भी कंजम्पशन को मजबूती मिलेगी। सरकार के वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की घोषणा के बाद रिजर्व बैंक क्या कदम उठाता है, इस पर एक्सपर्ट्स की नजरें रहेंगी।

अगला लक्ष्य । बजट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लक्ष्य की ओर देख रहा है। वित्त वर्ष 2026 में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की 7.4% की अनुमानित GDP ग्रोथ बड़ी बात कही जा सकती है। वित्त वर्ष 2027 में सरकार ने ग्रोथ के 7% रहने का अनुमान लगाया है, जो दुनिया के बड़े देशों में सबसे अधिक होगी।

मार्केट मायूस । अगर शेयर बाजार की बात करें तो बजट से उसके हाथ मायूसी लगी है। 2014 सितंबर के बाद से विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं। इस बीच, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियों में घरेलू निवेशकों का जो पैसा गया है, उससे मार्केट को सपोर्ट मिला है। लेकिन उनका भरोसा कितने समय तक बना रहेगा, इस पर सवालिया निशान लगा हुआ है। अगर आगे भी घरेलू निवेशकों का पैसा नहीं बनता है तो हो सकता है कि SIP इन्वेस्टमेंट में कमी आए। ऐसा होने पर शेयर बाजार पर प्रेशर बढ़ सकता है। मार्केट के लिए बुरी खबर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर STT की दरों में 150% की बढ़ोतरी भी है। सरकार का इरादा इस कदम के जरिये वेशक लेटेड निवेशकों को वायदा बाजार से दूर रखना है, लेकिन इससे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन घट सकता है।

डील का इंतजार । छोटे निवेशकों को वायदेक पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की घोषणा कर जरूर एक राहत दी गई है, लेकिन इंडिविजुअल प्रमोटर और एंटिटी प्रमोटर के लिए इसकी दरें अलग रखी गई हैं। सवाल है कि कहीं इससे प्रमोटरों की दिलचस्पी वायदेक योजनाएं लाने में कम तो नहीं होगी? मार्केट लंबे समय से अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील का इंतजार कर रहा है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पक्के संकेत नहीं मिले हैं। अगर यह डील होती है तो इससे मार्केट सेंटिमेंट में जरूर बदलाव आएगा। कुल मिलाकर, बजट में भले ही बिग बैंग ऐलान न हुए हों, लेकिन लंबी अवधि के लिए यह पॉजिटिव है। यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट की दिशा सही है।

एकदा

संकलन : दिलीप लाल

पहला बजट

26 नवंबर 1947 की सुबह संसद भवन के बाहर कैमरों की चमक कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। उसी भीड़ के बीच एक लंबे कद का व्यक्ति सलीकेदार सूट में और हाथ में चमड़े का ब्रीफकेस लिए शांत कदमों से संसद में दाखिल हुआ। वह थे आर.के. शन्मुखम चेट्टी, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। जब चेट्टी खड़े हुए तो सदन में सन्नाटा छा गया। संयत आवाज में उन्होंने कहा, 'मैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत कर रहा हूं।'

Subrata Dhar

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विभाजन भले ही राजनीतिक रूप से अनिवार्य रहा हो, पर उसकी आर्थिक कीमत दोनों देशों को चुकानी होगी। भारत-पाकिस्तान के बीच आर्थिक सहयोग की बात भी उन्होंने रखी। यह अंतरिम बजट था। आंकड़े कठिन सवालों को उजागर कर रहे थे- घाटा, सीमित आय और बढ़ता रक्षा खर्च। फिर भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत दिवालिया नहीं है। रक्षा, पुनर्वास और खाद्य सुरक्षा उनकी प्राथमिकताएं थीं। न कोई चकाचौंध, न लोकलुभावन वादे, बस ईमानदारी। यही कारण है कि इतिहास में शन्मुखम चेट्टी उस व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं, जिसने कठिन समय में भारत की आर्थिक नींव को संतुलन और विवेक के साथ रखा।

बजट ने बैलेंस बनाया या फिर छूट गया मौक़ा

खर्च पर लगाम के साथ विकास की राह पर देश की तेज़ रफ्तार

कुमार मंगलम बिड़ला

आज दुनिया के कुछ इलाकों में संघर्ष हो रहे हैं। आर्थिक अनिश्चितताएं भी पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसके बावजूद भारत की ग्रोथ तेज बनी हुई है और अर्थव्यवस्था मजबूत दिख रही है। अगले वित्त वर्ष में भी आर्थिक तरक्की की रफ्तार तेज रहने का अनुमान बजट में लगाया गया है।

वित्तीय अनुशासन । इसके बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए इकॉनमिक ग्रोथ से समझौता किए बगैर राष्ट्रीय हितों के साथ संतुलन बनाए रखना आसान काम नहीं था। लेकिन उन्होंने यह काम बखूबी किया है। वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण का यह नौवां बजट था। इसमें उन्होंने संतुलन और स्थिरता पर ध्यान बनाए रखा। उन्होंने एक तरफ तो आर्थिक ग्रोथ को तेज बनाए रखने के उपायों पर जोर दिया। साथ ही, उनका ध्यान वित्तीय अनुशासन पर भी बना रहा।

डेफिसिट में कमी । सरकार 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। यानी, तब तक उसका इरादा प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से अमीर देशों में जगह बनाने का है। इस साल के बजट को सरकार के इसी लक्ष्य के मद्देनजर देखने की जरूरत है। आज जिस तरह के हालात हैं, वैश्विक व्यापार संबंधी अनिश्चितताएं हैं, उन्हें देखते हुए वित्तीय अनुशासन को ठंडे बस्ते में डालने का प्रलोभन आ सकता है। लेकिन सरकार ने इन परिस्थितियों में भी फिस्कल डेफिसिट में कमी के लक्ष्य को हासिल किया।

विकसित भारत की ओर

- वित्तीय अनुशासन के साथ कैपेक्स में भी होगी बढ़ोतरी
- दुनिया की नजर में बढ़ेगी भारत की विश्वसनीयता
- अनिश्चित दुनिया में भारत काफी तेजी से ग्रो कर रहा

भारत पर भरोसा । वित्त मंत्री ने आगे भी इसे जारी रखने का वादा किया है। इससे क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और वैश्विक निवेशकों के बीच भारत को लेकर भरोसा बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भी उसका आकर्षण बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि GDP के अनुपात में कर्ज में उम्मीद के मुताबिक कमी आ रही है। इस सरकार ने कोविड-19 महामारी के बाद से जो कदम बढ़ाया था, वह जारी है।

नियमित सुधार । सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। सरकार ने आर्थिक सुधारों को जारी रखने के साथ फिस्कल कंसॉलिडेशन पर ध्यान बनाए रखा है। इस बजट में भी रूल्स और रेगुलेशंस में सुधार का सिलसिला जारी रहा। साथ ही, कंप्लायंस बोझ में भी कमी लाने की पहल की गई। एक और बात गौर करने की है- सरकार कभी-कभार सुधारों की दिशा में कदम नहीं बढ़ा रही है बल्कि उसने इसमें नियमितता बनाए रखी है।

कैपेक्स में बढ़ोतरी । मुझे सबसे बड़ी बात यह लग रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से समझौता किए बगैर वित्तीय अनुशासन बना हुआ है। सच तो यह है कि महामारी के बाद सरकार ने कैपेक्स में बढ़ोतरी की जो रफ्तार रखी, उसी से आर्थिक ग्रोथ तेज बनी हुई है। अब अगर प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू हो तो ग्रोथ में और तेजी आएगी। बजट में ग्रेट कॉरिडोर, वॉटरवेज में भारी निवेश का ऐलान किया गया। देश के महत्वपूर्ण शहरों को हाई स्पीड ट्रेन के जरिये कनेक्ट करने से तरक्की और तेज होगी। यह सिर्फ दिखावे के प्रोजेक्ट नहीं हैं।

शहरों की भूमिका । इस बजट में सिटी इकॉनमिक रीजन्स पर ध्यान देने की बात कही गई है। किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिहाज से शहरों में एक्टिविटी की काफी अहमियत है। पिछले कुछ दशकों में देश के महानगरों में ऐसा दिखा भी है। अब आर्थिक रफ्तार को गति देने के लिए टियर टू और टियर थ्री शहरों पर ध्यान देने की जरूरत है। तभी विकास का फायदा देश के अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। इस बजट में यही किया भी गया है।

MSME पर ध्यान । भारत में कई छोटे कदम उठाए गए हैं, जिनसे उद्यमों को फायदा होगा। इनकी मदद से युवा उद्यमी राष्ट्रनिर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेंगे। सात स्ट्रैटिजिक और टूरिजम जैसे सर्विस सेक्टर को लेकर जो घोषणाएं हुई हैं, उनसे रोजगार के मौके बनेंगे। चैंपियन MSME से भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के मिडल सेगमेंट को मजबूत बनाया जा सकेगा।

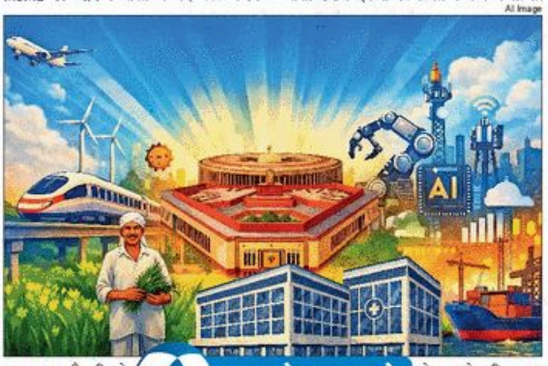

AI Image

सनराइज इंडस्ट्रीज । वित्त मंत्री ने बजट में छोटे-बड़े पारंपरिक उद्योगों के लिए आसान कर्ज, लोअर कंप्लायंस और प्रफेशनल सपोर्ट के उपाय तो किए ही हैं, उन्होंने सनराइज इंडस्ट्रीज पर भी जरूरी ध्यान दिया है। सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और नए एनर्जी सेक्टर पर फोकस से भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का मजबूत हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। उन्होंने डेटा और एडवांस्ड फार्मा में भारत के उभार के उपाय भी किए हैं। कुल मिलाकर, इस बजट से भारत को मजबूत इकॉनमी बनने में मदद मिलेगी।

(लेखक आदित्य बिड़ला ग्रुप के चेयरमैन हैं)

शेयर बाज़ार को मायूसी मिली, लेकिन इसकी वजह केवल STT ही नहीं

टी के अरुण

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद के बजट भाषणों से यह उम्मीद बंधती रही कि भारत में जल्द ही टैक्स की दरें स्थिर हो जाएंगी। खर्च का अंदाजा लगाना आसान होगा और बजट बोरिंग हो जाएगा। शायद यह पहला साल है, जब यह बात सच साबित होती हुई लगी। इस बजट के बारे में यही सबसे अच्छी बात भी है।

वर्ल्ड ऑर्डर में दरार । शेयर बाजार को बजट बोरिंग नहीं मायूसी वाला लगा। इसकी वजह STT दरों में बढ़ोतरी है। इससे अधिक मायूसी इस बात से हुई, जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वैश्विक व्यवस्था में आई दरार कहा है। यह दरार आर्थिक भी है और राजनीतिक भी। बजट में उन चुनौतियों से निपटने के बारे में कुछ नहीं कहा गया। भारत हाल के वर्षों में चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका के भरोसे था। चीन चाहता है कि भारत दक्षिण एशिया की शक्ति के रूप में संप्रभु हो या बजट से बाहर की। इन क्षेत्रों में बजट से किसी अजेंडा का संकेत नहीं मिलता।

प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सुस्त । दूसरी ओर, इस बजट से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जरूर खुश होंगी क्योंकि वित्त वर्ष 2026 में फिस्कल डेफिसिट GDP का 4.4% रहा है और अगले साल इसे 4.3% रखने का वादा किया गया है। 2026 में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में करीब 25000 करोड़ की कटौती की। आज कॉरपोरेट वर्ल्ड की मुनाफे में बढ़ोतरी धीमी पड़ गई है। प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सुस्त बना हुआ है।

MSME को क्या चाहिए । बजट में MSME के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। लेकिन उन्हें सस्ते और आसान कर्ज की अधिक जरूरत है। इन कंपनियों को खासतौर पर NBFC से कर्ज मिलता है। ऐसे में NBFC के लिए बॉन्ड मार्केट से अधिक कर्ज जुटाने का रास्ता साफ करने की जरूरत है। अभी NBFC जो बॉन्ड जारी करती हैं, उन्हें अच्छी रेटिंग वाला नहीं माना जाता।

कॉमन बॉन्ड मार्केट । देश में कॉरपोरेट डेट मार्केट तभी मजबूत हो सकता है, जब सेबी की देखरेख में सरकारी और प्राइवेट बॉन्ड का कॉमन मार्केट बनाया जाए। साथ ही, ऐसे डेरिवेटिव्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे मुद्रा, ब्याज दरों और क्रेडिट रिस्क की हेजिंग की जा सके। इस लिहाज से STT दरों में भारी बढ़ोतरी बुरी है। बजट स्पीच में पशुपालन को बढ़ावा देने पर काफी बातें हुईं। पर आज महंगे मक्के की वजह से पॉल्ट्री इंडस्ट्री के सामने संकट है। इसका कारण एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर सरकारी जुनून है।

कहां होना चाहिए था ध्यान

- वैश्विक व्यवस्था की चुनौतियों से निपटने पर चाहिए फोकस
- MSME को जरूरत है सस्ते और आसान कर्ज की
- रणनीतिक स्वायत्तता के मामले में खुद करनी होगी पहल

आमने-सामने

रणनीतिक स्वायत्तता । इस रणनीतिक लड़ाई में भारत, अमेरिका और क्वॉड के जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहस्य देशों के साथ युद्धाभ्यास करता आया है। लेकिन डॉनल्ड ट्रंप ने इस सहमति को हिला डाला है। उन्होंने न सिर्फ भारत पर भारी-भरकम टैरिफ लगाए बल्कि पाकिस्तान से करीबियां भी बढ़ाईं। भारत आज अपने भरोसे है। उसे अपना रणनीतिक सामर्थ्य खुद बढ़ाना है। साथ ही, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में उसे अपनी ताकत भी बढ़ानी है। तभी वह रणनीतिक स्वायत्तता हासिल कर पाएगा।

पुराना ढर्रा तोड़ना होगा । इसके लिए उसे रक्षा, रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट पर खर्च बढ़ाना होगा। सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। अहम क्षेत्रों में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल करनी होगी। इसके लिए संसाधन जुटाने की खातिर उसे पुराने ढर्रे को तोड़ना होगा। चाहे बात बजट की **खजाने का हाल** । GST की वजह से बेहतर ऑडिट सिस्टम के बनने के कारण सरकार का कुल टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, जबकि GDP की तुलना में वित्त वर्ष 2027 में इससे पिछले दो वर्षों की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आ सकती है। आज पर्सनल इनकम टैक्स से सरकारी खजाने में कॉरपोरेट इनकम टैक्स की तुलना में 20% अधिक पैसा आ रहा है। यह हाल तब है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स देने वालों की संख्या कुल रिटर्न फाइल करने वालों में 6.5% के करीब ही है। दूसरी तरफ, इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ देश के सभी नागरिकों पर है, जिसमें सर्वाधिक गरीब लोग भी शामिल हैं।

राज्यों की फिक्र हो । वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मानने का ऐलान किया और कहा कि वह अपनी 41% आमदनी राज्यों के साथ बांटेगी। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश भी यही थी, लेकिन केंद्र की ओर से राज्यों को इसके तहत 34% रकम ही दी गई, जिसे वित्त वर्ष 2027 में 34.6% करने का वादा किया गया है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

कैंसर के आंकड़ों में चेतावनी, इलाज से उम्मीद

डेटा Window

4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। भारत में असमय होने वाली मौतों का चौथा सबसे बड़ा कारण है कैंसर। 2024 में इसके 15.33 लाख नए मरीज मिले। अच्छी खबर है कि इलाज के नए तरीके भी आ रहे हैं।

36% मरीज बड़े पिछले 10 साल में

70% मरीज ग्रामीण इलाकों से आते हैं

100 कैंसर पीड़ित प्रति 1 लाख पर

1.43 लाख मरीज हर साल ओरल कैंसर के

48% ब्रेस्ट कैंसर पीड़ित महिलाएं 50 से कम की

80 हजार मरीज हर साल आते हैं लंग्स कैंसर के

AI Image

सरकारी मदद, सुविधाएं बढ़ी

287 से अधिक राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड

19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट

20 टर्शियरी केयर कैंसर सेंटर

36 जरूरी दवाएं ड्यूटी फ्री हैं

5-15 लाख रुपये सरकार मदद

2028 तक हर जिले में डे केयर सेंटर

2024 में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने क्वॉड कैंसर मूनशॉट पहल की। इसका उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर को खत्म करना है।

साल दर	1891	1940	1960	1990	1997	2000	2017
साल बड़ी तकनीकें	इम्यूनोथेरपी	कीमोथेरपी	टैमोक्सिफेन	पहला टीका	एंटीबॉडी थेरपी	रोबोटिक सर्जरी	CAR T-सेल

जनता जंक्शन इरफान

ख़ास लोगों पर फिर सरकार ने दिखाई मेहरबानी

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने पिछले दिनों भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में निराशा जाहिर करते हुए कहा था कि सिर्फ विकास दर पर फोकस रखने से बात नहीं बनती। गौर से देखें तो इस साल का बजट भी इसी समस्या का शिकार हो गया है। विकास के नाम पर सामाजिक क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। सामाजिक क्षेत्र पर हो रहे वास्तविक खर्च में लगातार कमी आई है और उसकी भरपाई करने के बदले आवंटन भी कम कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति से लेकर आवास पर कम खर्च करने का मतलब है लोगों के जीवन स्तर को रुसाई रूप से नीचे जाने पर बाध्य करना।

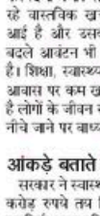

अनिल सिन्हा

आंकड़े बताते हैं दावों का सच

सरकार ने स्वास्थ्य के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपये तय किए हैं। यह GDP का सिर्फ आधा प्रतिशत है। सरकार खुद कई बार कह चुकी है कि इस खर्च को 2.5% ले जाने की जरूरत है। नैशनल हेल्थ पॉलिसी में भी यही कहा गया है। स्वास्थ्य पर भारत का खर्च पड़ोसी देशों से भी कम है, विकसित देशों की बात ही छोड़ दीजिए। यही हाल शिक्षा का भी है, जिस पर GDP का महज 0.6% खर्च रखा गया है। नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि शिक्षा पर हमें 6% खर्च करना चाहिए।

बजट के आंकड़ों से यह भी साफ होता है कि सरकार जितना दावा करती है, वास्तव में उतना खर्च करती नहीं। कुछ को छोड़कर उसने सामाजिक कल्याण की ज्यादातर स्कीमों में यही किया है। जलजीवन मिशन का हाल तो इतना खराब रहा कि उसने पिछले साल 67,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था और सिर्फ 17,000 करोड़ ही खर्च कर पाई। यही हाल शहरी और ग्रामीण आवास योजनाओं का रहा। यह प्रशासनिक और वित्तीय, दोनों स्तर की विफलता को दर्शाता है।

सामाजिक क्षेत्रों की अनदेखी को टैक्स ढांचे से जोड़कर देखने पर अंदाजा हो जाएगा कि मोदी सरकार का झुकाव किस ओर है। सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा आम व्यक्तियों से मिले इनकम टैक्स से आता है। यह राजस्व का 21% है। वहीं, कॉरपोरेट से आमदनी केवल 18% है। सरकार आम लोगों से टैक्स वसूलती है, लेकिन उनके लिए खर्च करने में कतराती है। कॉरपोरेट टैक्स के लगातार घटने और इनकम टैक्स बढ़ने से आमदनी की असमानता काफी बढ़ी है।

विश्व असमानता रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, भारत के 10% लोग देश की कुल आमदनी का 58% ले लेते हैं, जबकि देश की 50% आबादी के हिस्से सिर्फ 15% आता है। यह दूरी ज्यादा कमाने वालों पर टैक्स लगाने से मिट सकती है, लेकिन बजट को देख कर लगता है कि सरकार इस ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं।

रोजगार सेक्टर पर कम खर्च

रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर सरकार कम खर्च कर रही। कृषि पर देश की 46% आबादी निर्भर करती है, पर पिछले साल के मुकाबले इस बार सरकार ने केवल 628 करोड़ रुपये ही ज्यादा दिए हैं। महंगाई को देखें, तो वास्तविक खर्च पहले से कम ही हो जाएगा। कृषि अनुसंधान पर भी खर्च पहले के बराबर है। विश्व प्रतिस्पर्धा और कृषि क्षेत्र को बाहरी देशों के लिए खोलने के दबाव को देखते हुए बजट निराश करता है। रोजगार पर घटते फोकस का अंदाजा इस बात से लगता है कि मनरेगा को गारंटी वाली योजना से सरकारी योजना में बदल दिया गया। बदली योजना पर आवंटन पहले से घटा नहीं है, लेकिन उसे प्रशासनिक फैसलों पर जरूर छोड़ दिया गया है, जिससे उद्यमी को फायदा होगा।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

प्रकृति के पास है सफलता का सटीक फॉर्म्युला

सलिल पाण्डेय

इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। इंसान चाहता है कि उसके पास अपार धन हो, सभी सुख-सुविधाएं हों और हर जगह उसका मान-सम्मान हो। लेकिन, वह अक्सर भूल जाता है कि बड़ी उपलब्धियां अचानक नहीं मिलतीं। इच्छा रखना गलत नहीं, पर उसे पूरा करने के लिए सही योजना और अनुशासित प्रयास जरूरी है।

यदि कोई व्यक्ति स्पष्ट योजना बनाकर धैर्य के साथ उस पर काम करे, तो सफलता मिलना तय है। रेलगाड़ी जब स्टेशन से चलती है, तो धीरे-धीरे गति पकड़ती है। हवाई जहाज भी रन-वे पर कुछ दूरी तय करने के बाद ही आकाश में उड़ता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, अनुभव से सीखना भी आवश्यक है। आज जो भी समृद्ध है, वे संघर्ष के रास्ते से होकर ही वहां तक पहुंचे हैं। उन्होंने धूप, गर्मी, बारिश और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। उनके भीतर यह दृढ़ निश्चय रहा कि जब तक सफलता नहीं मिलेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। यही लगन उन्हें सफल बनाती है।

यदि इसे प्रकृति से समझें, तो वृक्ष का उदाहरण सामने आता है। बीज को पहले समतल भूमि में बोया जाता है, फिर नियमित रूप से पानी दिया जाता है। अंकुर निकलने पर उसकी रक्षा के लिए घेराबंदी की जाती है। वर्षों के परिश्रम के बाद वही वृक्ष फल, छाया, लकड़ी और प्राणवायु देता है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP7 User: cci Time: 02-01-2026 23:17 Color:

फटाफट खबरें

निर्माणाधीन इमारत से गिरा मजदूर, हुई मौत

■ NBT न्यूज,वसई : वसई में मधुबन इलाके में रोशनी नगरी निर्माणाधीन इमारत दूसरी मंजिल से गिरकर मध्यप्रदेश के दिंडोरी गांव निवासी मजदूर की मौत हो गई। शुक्रवार की रात काम के दौरान दूसरी मंजिल से दीपक शिवचरण कुशराम (22) का संतुलन बिगड़ने से वह नीचे आ गिरे। सिर पर जख्म होने से उनकी मौत हो गई। दीपक का शव जमीन पर लहूलुहान देख साथी मजदूरों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच जारी है।

पलक को तीरंदाजी स्पर्धा में सफलता

■ NBT न्यूज, भिवंडी : भिवंडी तालुका के अंबाडी की छात्रा पलक पाटील ने अपनी स्कूली टीम के साथ अलीबाग में 22 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय फील्ड आर्चरी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक (सिल्वर मेडल) जीता है। पलक वाडा स्थित "सिटिल एंजल्स इंग्लिश मीडियम स्कूल" की छात्रा हैं। उनकी टीम ने प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस स्कूल के छात्रों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लेकर स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए हैं।

महिला पर किया कोयता से हमला

■ NBT न्यूज, नालासोपारा : आचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अलकापुरी इलाके में एक युवक ने मामूली बात को लेकर पड़ोस की एक महिला पर कोयता से हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी महिला का एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

पॉलिश के बहाने लूट लिए थे गहने

■ NBT न्यूज, पालघर : बोईसर पुलिस ने ऐसे दो महाठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 13 जनवरी को एक वृद्धा से पॉलिश करने के बहाने उनके साढ़े तीन लाख की जूलरी लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने उनके पास से सारी जूलरी बरामद कर ली है। आरोपियों के खिलाफ मुंबई के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कई अपराधिक मामले दर्ज हैं।

नवी मुंबई में BJP और शिंदे सेना आए आमने-सामने

महापौर-उपमहापौर पद के लिए महायुति के दलों ने भरा नामांकन | अब 5 फरवरी को महासभा में दोनों पदों के लिए चुनाव होगा

■ पुरुषोत्तम कनौजिया, नवी मुंबई

नवी मुंबई मनपा चुनाव परिणामों के बाद रविवार को महापौर और उपमहापौर पद के लिए BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) की तरफ से उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर दिया। BJP की तरफ से सुजाता सूरज पाटील ने महापौर और दशरथ भोजराम भगत ने उपमहापौर पद के लिए नामांकन भरा, तो वहीं शिवसेना की तरफ से सरोज रोहिदास पाटील ने महापौर और आकाश मढवी ने उपमहापौर पद के लिए नामांकन भरा। दोनों पार्टियों की तरफ से नामांकन पत्र आने के कारण अब 5 फरवरी को आयोजित महासभा में दोनों पदों के लिए चुनाव करवाया जाएगा।

नवी मुंबई मनपा चुनाव में 111 सीटों में से BJP को 65 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 42 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव रिजल्ट के बाद ऐसा लग रहा था कि BJP निर्विरोध महापौर बनाने में सफल हो जाएगी, लेकिन शिवसेना ने उसके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। ज्यादातर मनपा चुनावों में BJP और शिवसेना (शिंदे गुट) एकसाथ चुनाव लड़े थे, कुछ जगहों पर अगल-अलग भी लड़े, लेकिन चुनाव बाद एकसाथ आ गए थे।

उल्हासनगर में शिवसेना एकनाथ शिंदे अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी उसके बावजूद BJP को उपमहापौर का पद दे दिया था, उसी तरह कल्याण-डोंबिवली में भी शिवसेना अपने दम पर बहुमत तक पहुंच गई थी, फिर भी BJP को उपमहापौर का पद दे दिया, जिससे वहां भी महापौर और उपमहापौर का चुनाव निर्विरोध हो गया था। नवी मुंबई में भी उम्मीद थी कि जहां BJP को स्पष्ट बहुमत मिलने पर भी मना जा रहा था BJP शिवसेना (शिंदे गुट) को साथ लेते हुए उन्हें उपमहापौर का पद दिया जाएगा। लेकिन इसके उलट फैसला करते हुए वहां BJP ने उम्मीदवारों का नामांकन भरवा दिया और शिवसेना (शिंदे गुट) से चर्चा तक नहीं की।

BJP द्वारा नॉमिनेशन भरने के बाद शिंदे की शिवसेना ने भी वहां दोनों पदों सभी को झटका दे दिया। सुजाता पाटील के पति सूरज पाटील को गणेश नाईक परिवार का एक वफादार नगरसेवक माना जाता है। सुजाता पाटील लगातार दूसरी बार नगरसेविका बनी हैं। जबकि दो बार से अधिक नगरसेविका नेत्रा शिर्के, शुभांगी पाटील, माधुरी सुतार, रेखा म्हात्रे को नगरअध्यक्ष कर दिया गया।

अचानक आगे आया सुजाता का नाम

(महापौर और उपमहापौर) पर नामांकन भरवाकर चुनौती पेश कर दी है। यहां राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि BJP ने बड़ा दिल दिखाया होता और शिवसेना को उपमहापौर पद दिया होता, तो यहां भी दोनों एकसाथ आ सकते थे। नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के बाद नवी मुंबई में शिवसेना (शिंदे गुट) के उपनेता विजय चौगुले ने कहा कि राज्य में महायुति की सरकार है, इसलिए हमने नामांकन भरा है और आगे चुनाव तक इंतजार करेंगे।

स्ट्रीट डॉग का कहर, मासूम की मौत

12 वर्षीय हामिद की गई जान, मनपा पर उठे सवाल

■ विजयकुमार सिंह, भिवंडी: भिवंडी शहर में स्ट्रीट डॉग का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदिरा इलाके में स्ट्रीट डॉग के काटने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद मनपा सफाई की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह घटना न केवल शहर में बढ़ती स्ट्रीट डॉग समस्या को उजागर करती है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाओं और इलाज की कमी को भी सामने लाती है।

मृतक बच्चे की पहचान हामिद साहम खान के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, 10 जनवरी की सुबह इंदिरा मोहल्ले में एक स्ट्रीट डॉग ने अचानक हामिद पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर गंभीर जख्म कर दिए। घायल बच्चे को तुरंत भिवंडी के आईजीएम उपनिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के तहत एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और टिटनेस (टीटी) इंजेक्शन दिए गए।

हालांकि अस्पताल में एंटी-रेबीज सीरम (एआरएस) उपलब्ध नहीं था। इसके चलते डॉक्टरों ने बच्चे को आगे के इलाज के लिए ठाणे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया। ठाणे सिविल अस्पताल में एआरएस इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को वहीं भर्ती करने की सलाह दी। लेकिन आर्थिक तंगी और रोजना ठाणे आने-जाने में असमर्थता के चलते परिजनों ने इलाज भिवंडी के आईजीएम अस्पताल में ही जारी रखने का अनुरोध किया।

अस्पताल पर लापरवाही का आरोप

घटना के बाद परिजनों ने आईजीएम उपजिला अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के फूफा नवाज का कहना है कि आईजीएम अस्पताल अब इलाज का केंद्र नहीं, बल्कि सिर्फ रेफर करने का केंद्र बनकर रह गया है। समय पर समुचित इलाज मिलता तो शायद बच्चे की जान बचाई जा सकती थी।

इस बीच 30 जनवरी को भी एक और मामला सामने आया, जिसमें अबुल कलाम (42) को स्ट्रीट डॉग ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। श्रेणी-3 के इस मामले में भी एआरएस इंजेक्शन के लिए मरीज को आईजीएम अस्पताल से ठाणे सिविल अस्पताल रेफर किया गया, जिससे शहरवासियों में भारी रोष है।

इसके बाद हामिद को दोबारा आईजीएम उपनिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे एंटी-रेबीज वैक्सीन की तीन अतिरिक्त डोज दी गईं। आईजीएम की सुपरिंटेंडेंट डॉ. माधवी पंढारे के अनुसार, बच्चे को सभी जरूरी उपचार समय पर दिए गए थे। कि 27 जनवरी को हामिद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे फिर आईजीएम अस्पताल लेकर आए, जहां से हालत को देखते हुए पहले ठाणे सिविल अस्पताल और फिर मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान शुक्रवार उसकी मौत हो गई।

चेहरे पर गंभीर जख्म

- IGM अस्पताल में एआरएस इंजेक्शन नहीं
- इलाज के लिए ठाणे और मुंबई रेफर
- परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप
- IGM बना सिर्फ रेफर सेंटर

भयावह आंकड़ें

आंकड़े भी हालात की गंभीरता बयां करते हैं। जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक भिवंडी में 11,037 लोग स्ट्रीट डॉग के हमले का शिकार हुए। वहीं जनवरी 2026 में ही 1,062 लोग घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद मनपा द्वारा स्ट्रीट डॉग की संख्या नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

बंद पड़ी पानी की टंकी में मानव खोपड़ी से सनसनी

■ NBT न्यूज, वसई : माणिकपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र नौपाडा इलाके में शनिवार रात को एक बंद पड़ी पानी की टंकी में मानव खोपड़ी व हड्डियां मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने सभी हड्डियों को बरामद कर उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है।

वसई (वेस्ट) के नौपाडा स्थित बारकुलपा नामक दो मंजिला चॉल में बनी पानी की टंकी लंबे समय से उपयोग में नहीं थी। इन दिनों इमारत की मरम्मत का कार्य चल रहा था। शनिवार रात मजदूरों ने जब टंकी को तोड़ा, तो अंदर से मानव खोपड़ी और हड्डियां दिखाई दीं, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। माणिकपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। जांच में केवल खोपड़ी और हड्डियां मिली थीं। रविवार को चलाए गए सर्च ऑपरेशन में भी मानव अवशेष बरामद हुए। इसके साथ ही एक पैंट और शर्ट भी मिले।

घटनास्थल पर डीसीपी सुहास बावचे व माणिकपुर पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। सभी अवशेषों को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है और मृतक की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

आजाद मैदान में सजी ब्रजधाम की दिव्य यात्रा

सोशल कनेक्ट धर्म। कर्म। समाज

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : जिस ब्रजभूमि की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु जीवनभर प्रतीक्षा करते हैं, वही ब्रज मानो मुंबई में साकार हो गया है। आजाद मैदान में इन दिनों ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, जैसे श्रद्धालु मथुरा-वृंदावन की गलियों में प्रवेश कर गया हो। श्री ब्रज मंडल मुंबई की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्वर्ण जयंती महोत्सव की झांकी में मथुरा जन्मभूमि से लेकर वृंदावन की कुंज गलियों, नंदगांव, बरसाना, राधाकुंड-श्यामकुंड, गोवर्धन पर्वत और कुसुम सरोवर तक की यात्रा प्रस्तुत की गई। इसी दिव्य वातावरण में ध्वजपीठ से पुंडरीक गोस्वामी महाराज की अमृतवाणी श्रद्धालुओं को ब्रज भक्ति के गूढ़ रहस्यों से परिचित करा रही है। उन्होंने कहा, 'ध्वजपीठ मांगने की नहीं, बांटने की गद्दी है। यहां से ज्ञान, भक्ति और संस्कार का वितरण होना चाहिए।' महाराज ने स्पष्ट किया कि बांके बिहारी की शरण में आने के बाद किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ठाकुर जी अकिंचन भक्तों पर भी कृपा करते हैं। कथा के दौरान नरसिंह अवतार, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन अवतार, राम-कृष्ण जन्मोत्सव और बाल लीलाओं के प्रसंगों ने भाव-विभोर कर दिया। गिरिराज पूजन और कालिया मर्दन के प्रसंग पर श्रद्धालु झूम उठे। संस्था के अध्यक्ष **सुरेश अग्रवाल** ने कहा, 'श्री ब्रज मंडल मुंबई की स्वर्ण जयंती पर हमारा उद्देश्य केवल एक आयोजन करना नहीं, बल्कि हर श्रद्धालु को ब्रज की अनुभूति कराना है। जो लोग जीवन में 84 कोस ब्रज परिक्रमा नहीं कर पाते, वे यहां उसी भाव और श्रद्धा के साथ दर्शन कर सकें, यही हमारी साधना है। झांकी ब्रज भक्ति, संस्कृति और संस्कारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास है'। इस अवसर पर योगेश अग्रवाल, नीना अग्रवाल, कान्हाबिहारी अग्रवाल, पवन अग्रवाल, गौरव शर्मा, सुरेश मिश्र, भुवनेश अग्रवाल आदि मौजूद थे।

श्रद्धालुओं को मिल रहा 84 कोस ब्रज परिक्रमा का साक्षात दर्शन

लकड़ी के कारखाने में लगी आग

■ NBT न्यूज, नवी मुंबई : अडवली-भूतवली स्थित लोलाधर नाईक कंपाउंड में रविवार शाम करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। आग सबसे पहले यहां मौजूद लकड़ी के कारखाने में लगी और कुछ ही मिनटों में पास के गते के गोदाम तक फैल गई। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट के कारण लगने की आशंका जताई है। फायर ब्रिगेड के अनुसार सूचना मिलते ही नेरुल एमआईडीसी, टीबोआई और नवी मुंबई मनपा की दमकल टोमी मौके पर पहुंचीं। साल से आठ दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया, कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को फैलने से रोका गया। बताया गया है कि जिस गोदाम में आग लगी, वह अवैध रूप से संचालित था। फिलहाल, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

-फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई

पुलिस लॉक-अप से आरोपी फरार

■ NBT न्यूज, मीरा-भाईंदर : भाईंदर पूर्व स्थित नवघर रोड पुलिस स्टेशन के लॉकअप से चोरी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के फरार होने की घटना से हड़कंप मच गया है। घटना रविवार सुबह उस समय हुई, जब लॉक-अप की सफाई की जा रही थी। फरार आरोपी अब्दुल जानिदी मनियार को हाल ही में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार कर लॉक-अप में रखा गया था। आरोपी मौके का फायदा उठाकर लॉक-अप से निकला, फिर सिढ़ियों से कूदकर पुलिस स्टेशन परिसर में पहुंचा और वहां से सीढ़ियों के सहारे पहली मंजिल से नीचे छलांग लगकर फरार हो गया। मीरा-भाईंदर-वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले छह पुलिस स्टेशनों की क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी भी कर दी गई है।

घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया

उल्हासनगर मनपा में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद पर सस्पेंस

शिंदे सेना के वफादार को पद दिए जाने की मांग हुई तेज

■ NBT न्यूज, उल्हासनगर: उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स के अलावा दूसरी पार्टियों के भी कॉर्पोरेटर्स के सत्ता में होने से अब अलग-अलग पद पाने की होड़ दिखाई दे रही है। उल्हासनगर मनपा में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पद के लिए टॉप लेवल पर लॉबिंग शुरू होने की चर्चा है। मेयर का पद कालानी खेमे के पास जाना तय होने से अब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पद शिंदे सेना के किसी वफादार को दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

उल्हासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में BJP बनाम शिंदे सेना, साईं और ओमी टीम महागठबंधन एक-दूसरे के खिलाफ लड़े। पिछले 15 दिनों से दोनों पार्टियों के कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पावर बैलेंस के लिए एक-दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे। असल में, BJP और शिंदे सेना महागठबंधन सत्ता बनाने के समय एक साथ आए थे। मेयर का पद शिंदे सेना की ओमी टीम के अश्विनी निकम को मिलना तय माना जा रहा है, जबकि डिप्टी मेयर का पद BJP के खाते में जाना तय है। दोनों पार्टी के लिए एक-एक आवेदन मिलने के कारण, मेयर और डिप्टी मेयर पदों की औपचारिक घोषणा 3 फरवरी को की जाएगी। इस बीच, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पद को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

किस पार्टी के दावे की चर्चा?

BJP के जमनदास पुरसवानी, प्रकाश मलीजा, महेश सुखरामानी, राम चार्ली परवानी BJP छोड़कर अपने समर्थकों के साथ ओमी टीम में शामिल हो गए। कहा जा रहा है कि पुरसवानी, मलीजा की पत्नी जया मलीजा और सुखरामानी नगरसेवक चुने गए हैं। इनमें जया मलीजा के साथ-साथ शिंदे सेना के सिनियर नगरसेवक राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र सिंह भुल्लर और अरुण आशान का नाम स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पद के लिए बताया जा रहा है। भले ही शिंदे सेना के पास बहुमत है, लेकिन जब से BJP सरकार में शामिल हुई है, BJP भी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन की पोस्ट पर दावा कर सकती है।

नालासोपारा में फर्जी ऑटो वालों का राज

■ NBT न्यूज, नालासोपारा: नालासोपारा पूर्व के मोरगांव, प्रगति नगर, विजय नगर, ओसवाल नगरी सहित कई इलाकों में सैकड़ों फर्जी ऑटोरिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ट्रैफिक विभाग के संज्ञान में मामला होने के बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। फर्जी रिक्शा चालकों ने जगह-जगह सड़कों पर कब्जा कर अवैध रिक्शा स्टैंड बना लिए हैं, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ व्यापारियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

वैध रिक्शा चालकों को भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रिक्शा यूनियन लीडर प्रदीप मिश्रा के अनुसार, नालासोपारा में 40 प्रतिशत रिक्शा फर्जी हैं। सबसे ज्यादा मोरगांव और प्रगति नगर इलाके में हैं। शाम सात बजे से सुबह 10 बजे तक चलते रहते हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आरटीओ और ट्रैफिक विभाग को मंथली हप्ता मिलने के कारण कार्रवाई से बचा जा रहा है। फर्जी रिक्शा चालकों के पास न वर्दी होती है, न लाइसेंस और न ही बैज।

> इस विषय को लेकर वहां के सीनियर पीआई से बातचीत कर फर्जी ऑटो चालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
> - अशोक विरकर, डीसीपी, ट्रैफिक विभाग

संत रविदास जयंती मनाई गई

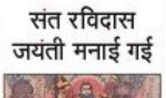

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : मुंबई में विभिन्न जगहों पर संत गुरु रविदास महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कुर्ला पश्चिम के कमानी, सुंदरबाग में संत रविदास के अनुयाइयों ने कार्यक्रम आयोजित कर संत की स्मृति को नमन किया। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक अर्जुन पवार ने कहा कि वर्तमान में संत रविदास महाराज के विचारों पर चलने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने मानवता का संदेश दिया है। कार्यक्रम में मौजूद अशोक ने कहा कि संत रविदास ने लोगों को सच्चाई की राह दिखाई है। इस राह पर चलते हुए लोग अपने-अपने व्यवसाय करते हुए ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। इस अवसर पर संत रविदास के दोहे बजाए गए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने संत रविदास महाराज के महान संदेशों को याद किया।

व्रत त्योहार - 2 से 8 फरवरी 2026 तक

2 फरवरी, सोमवार
फाल्गुन मासारंभ: हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास का शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही पश्चिम दिशा में शुक्रोदय भी हो चुका है। शुक्र के उदय होने के कारण हिंदू समाज में विवाह एवं अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो गई है।

4 फरवरी, बुधवार
शुक्र बालत्व निवृत्ति: हिंदू पंचांग एवं शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार शुक्र उदय के बाद प्रारंभ के तीन दिन बालक अवस्था में रहता है। तीसरे दिन से शुक्र बालत्व से निवृत्त हो जाता है। इस दिन शुक्र बालत्व निवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, अतः विवाह सहित सभी शुभ और मांगलिक कार्य निर्बाध रूप से किए जा सकेंगे।

5 फरवरी, गुरुवार
संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। चंद्रोदय रात्रि 9:10 बजे होगा। चंद्र दर्शन के पश्चात भगवान गणेश का पूजन विशेष फलदायी माना गया है।

8 फरवरी, रविवार
भानु सप्तमी व्रत: हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। संयोगवश, इस दिनरविवार होने के कारण यह व्रत भानु सप्तमी कहलाएगा। इस दिन सूर्य देव की विधिवत पूजा और सप्तमी व्रत करने से विशेष पुण्य और लाभ की प्राप्ति मानी जाती है।

-आचार्य बाल कृष्ण मिश्रा

सोसायटी में औद्योगिक कार्य पर की शिकायत

■ NBT न्यूज, नवी मुंबई : सीबीडी बेलापुर के सेक्टर-11 स्थित रॉयल सोसायटी में औद्योगिक कार्य किए जाने का खुलासा हुआ है। वातावरण में बढ़ते कार्बन से लोगों को तकलीफ हुई, तो शिकायत बढ़ी। इसके बाद सोसायटी ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया। अब मामला मनपा तक पहुंचा है, अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई की बात कही है।

सोसायटी निवासी बंसल कुमार ने बताया कि पहले यहां फोटोकॉपी मशीनें बेचने की दुकानें शुरू हुई थीं। कुछ दिन बाद फोटोकॉपी मशीनों की रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया। रिपेयरिंग में जिस क्लीअर मशीन का उपयोग होता है, उससे नॉइज पल्यूशन बढ़ता है। साथ ही, फोटोकॉपी मशीनों से निकलने वाले कार्बन से भी तकलीफ बढ़ रही है। लोगों को 24 घंटे झिल्लिकार्य बंद रखनी पड़ रही है।

शिकायत पर सोसायटी की तरफ से नोटिस दिया गया। आरोप है कि नोटिस का कुछ असर नहीं हुआ। जब कोई व्यक्तिगत तौर पर अथवा तीन चार के ग्रुप में जाकर शिकायत करता है, तो दुकानदार झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। पीड़ितों ने मनपा के कार्यालय में शिकायत की।

> सोसायटी के नियमों के तहत हम यहां 20 साल से काम कर रहे हैं। अब अचानक इन्होंने विरोध जताया है।
> - सुरेश गोस्वामी, दुकानदार

> हमें इस बारे में उचित कदम उठाएंगे।
> - प्रशांत नेरकर, विभाग अधिकारी (बेलापुर)

नवनिर्वाचित नगरसेवक के घर चोरी की वारदात

■ NBT न्यूज, भिवंडी : भिवंडी मनपा के नवनिर्वाचित नगरसेवक संदीप मोहेर के घर में बिल्डिंग के वॉचमैन और उसके साथियों ने मिलकर चोरी की। घटना शहर के कामशर इलाके की है। संदीप प्रभाग क्रमांक-21 से विजयी हुए। 30 जनवरी मंगे की सुबह में पूरा परिवार शामिल हुआ था। चोरी ने घंटनबाग के भारत कॉलोनी स्थित 'हीरा कॉम्प्लेक्स' की पहली मंजिल वाले उनके फ्लैट के बाथरूम की ग्रिल तोड़ घर में प्रवेश किया। बेडरूम की अलमारी से $.50 लाख रुपये नकद और 13.275 तोले सोने के आभूषण, कुल मिलाकर 26.59 लाख रुपये का कीमती सामान चोरी कर लिया। घर लौटने पर परिवार ने तुरंत वॉचमैन और उसकी पत्नी की तलाश कर उसे कल्याण में पकड़ लिया और नारपोली पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

रेडियोलॉजिस्ट न होने से सोनोग्राफी ठप

नायगांव के सरकारी अस्पतालों में कर्मियों की कमी से बुरा हाल

■ सुरेंद्र नेगी, वसई : वसई-विरार के सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी की व्यवस्था है, लेकिन यहां की सोनोग्राफी मशीनें पिछले एक साल से बंद पड़ी हैं। चिकित्सा विभाग का कहना है कि रेडियोलॉजिस्ट और कर्मचारियों की कमी के कारण यह समस्या हो रही है।

प्राइवेट अस्पतालों में अधिक शुल्क देकर कराना पड़ रही सोनोग्राफी

सोनोग्राफी बंद होने की वजह से गर्भवती महिलाओं व अन्य मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अधिक शुल्क देकर सोनोग्राफी करानी पड़ती है। मामला नायगांव के जुचंद्र स्थित माता बाल स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां मशीन तो लगी है, लेकिन उसे चलाने वाले रेडियोलॉजिस्ट व कर्मचारी नहीं हैं। इस समस्या को लेकर बविआ के नवनिर्वाचित नगरसेवक कन्हैया मोहेर ने मनपा आयुक्त को पत्र लिखकर जल्द से जल्द रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने की मांग की है। बता दें कि लगभग 30 लाख आबादी वाले वसई-विरार में निम्न वर्ग के लोगों की जनसंख्या अधिक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है। वह सरकारी सेंटरों पर ही निर्भर रहते हैं। वहीं, नायगांव की आबादी लगभग 3 लाख से अधिक है। यहां के जुचन्द्र गांव में एकमात्र बाल-माता संगोपन केंद्र है। यहां आने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए लगाई गई सोनोग्राफी मशीन पिछले एक साल से बंद पड़ी है। इससे गर्भवती महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वसई विरार मनपा के पास 5 बाल-माता बाल संगोपन केंद्र है, जिनमें रोजाना सैकड़ों गर्भवती महिलाएं आती हैं। केंद्र में सोनोग्राफी व खून की जांच करने की सुविधा नहीं है। मजबूरन महिलाओं को प्राइवेट अस्पतालों में सोनोग्राफी के लिए भेजा जाता है, जहां अधिक शुल्क देना पड़ता है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, माता बाल संगोपन केंद्र में गर्भवती महिलाओं की प्रसूति व उनकी चिकित्सा सेवाएं मुफ्त में होनी चाहिए, लेकिन यहां चिकित्सा विभाग की लापरवाही से आम जनता को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है।

आयुक्त ने दिया आश्वासन

चिकित्सा विभाग का कहना है कि मशीन तो है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण वह बंद पड़ी है। महिलाओं को हो रही परेशानियों को लेकर बविआ के नवनिर्वाचित नगरसेवक कन्हैया बेटा मोहेर ने मनपा आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी से मुलाकात की और जल्द से जल्द डॉक्टरों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की मांग की है। आयुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्द ही चिकित्सा विभाग के मुख्य अधिकारी से बातचीत कर सोनोग्राफी शुरू की जाएगी।

उल्हासनगर: राशन अनाज की कालाबाजारी

■ NBT न्यूज, उल्हासनगर: विठ्ठलवाड़ी पुलिस ने सरकारी राशन के अनाज की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने सरकारी अनाज का स्टॉक जब्त किया है और इस संबंध में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और एक पर मामला दर्ज है। राशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर ज्योति तांबेकर के साथ टीम को सूचना मिली थी कि उल्हासनगर कैंप नंबर 4 के सेक्टर 28 इलाके में गैर-कानूनी तरीके से सरकारी अनाज स्टोर करके बेचा जा रहा है। इसके मुताबिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर ज्योति तांबेकर ने अपनी टीम के साथ आरोपियों के घर पर रेड मारी। उस समय संजय सुंदरलाल रोहेड़ा और संतोष संजय रोहेड़ा (28) को एक बोलेरो पिकअप गाड़ी में सरकारी अनाज के बैग बटलकर ब्लैक मार्केट में बेचने की तैयारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP8 User: cci Time: 02-01-2026 23:02 Color:

रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले में पुलिस की 12 टीमें कर रही हैं छानबीन

FIR दर्ज, खंगाले जा रहे CCTV फुटेज, केस क्राइम ब्रांच और जोनल पुलिस के हवाले

Manish.Jha@timesofindia.com

■ मुंबई: मुंबई के जुहू इलाके में मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर फायरिंग की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:40 बजे अज्ञात हमलावरों ने बिल्डिंग के बाहर 4 से 5 राउंड तक फायरिंग की। फायरिंग में शेट्टी के घर की बालकनी की दीवार, ग्लास और अन्य जगहों पर गोलियां लगीं। फायरिंग की घटना के बाद गोलियों के निशान कई जगहों पर दिखाई दिए। वहीं, इस घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। सूचना मिलते ही जोनल पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें घटनास्थल पर पहुंचीं और जांच शुरू की गई। हालांकि, अब तक इस फायरिंग में किसी गिरोह या संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने कहा है कि बिल्डिंग की दिशा में फायरिंग की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज कर ली गई है और जांच के लिए 12 विशेष टीमें गठित की गई हैं। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल जुटाए हैं। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। आवासीय परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिनसे संदिग्ध हमलावरों के बारे में सुराग जुटाए जा रहे हैं।

Uma Kadam

जुहू में रोहित शेट्टी के निवास पर रविवार को जांच करती मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम।

रोहित शेट्टी को सोशल मीडिया पर धमकी

रोहित शेट्टी को सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है। एक फेसबुक पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए धोतरवे ने दी गई है कि फायरिंग सिर्फ ट्रेलर था और अगले इससे भी बड़ा हमला किया जा सकता है। पोस्ट में लिखा गया है कि रोहित शेट्टी को पहले भी कई बार संदेश भेजकर उनके काम में दखल न देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। धमकी में कहा गया है कि यदि उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला, तो उनकी हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी और उन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यह धमकी कथित तौर पर लोणकर नाम के अकाउंट से पोस्ट की गई है। पोस्ट के नीचे लोणकर के साथ आरजो बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हर्मन शाहू जैसे नाम भी दर्ज हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने लिया जायजा

फायरिंग की घटना की सूचना मिलते ही देर रात से ही घटनास्थल पर आला अधिकारियों का आना-जाना लगा हुआ है। डीसीपी क्राइम ब्रांच विशाल ठाकुर और जोनल डीसीपी दीक्षित गेडाम समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। सूत्रों के अनुसार, इन अधिकारियों ने रोहित शेट्टी से भी मुलाकात की है। पुलिस लॉरेंस बिश्नोई द्वारा पूर्व में बॉलीवुड सितारों को दी गई कथित धमकियों के मद्देनजर भी जांच कर रही है। क्योंकि टेड देखे तो फायरिंग की घटनाएं अब तक सलमान खान के करीबियों पर हुई हैं।

■ सीसीटीवी में कैद हुआ था संदिग्ध
■ रोहित शेट्टी, उनके गार्ड और ऑटो चालक के बयान दर्ज

ऑटो चालक से मिला सुराग !

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई

बेहद शांत जुहू का महमूद चौक इलाका शनिवार रात करीब 12.45 बजे गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस पॉश इलाके के शेट्टी टॉवर की पहली मंजिल पर रहने वाले निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास की ओर निशाना बनाकर अचानक 5 राउंड फायरिंग की गई।

जुहू पुलिस ने बताया कि शेट्टी के तीन गार्ड्स में से एक गार्ड ने सबसे पहले फायरिंग की घटना देखी। शनिवार रात ते गार्ड बिल्डिंग के अंदर ड्यूटी दे रहे थे, जबकि फायरिंग के समय तीसरा गार्ड टॉयलेट गया था। गार्ड से शेट्टी को घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। हाई-प्रोफाइल केस होने के कारण जोनल डीसीपी और क्राइम डीसीपी मौके पर पहुंच केस की छानबीन में जुट गए। जुहू पुलिस ने बीएनएस की धारा 109 (हत्या की कोशिश) और आर्म्स ऐक्ट के तहत केस दर्ज कर इसे आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने रोहित शेट्टी, उनके गार्ड और ऑटो चालक का बयान दर्ज किया है।

जुहू पुलिस की गिरफ्त में पुणे पुलिस की मदद से गिरफ्तार किए गए फायरिंग के आरोपी।

> आमतौर पर एक्सटॉर्शन के मामलों में टारगेट को ऐसी हरकतों से पहले धमकी भरे या पैसे मांगने वाले कॉल आते हैं। इस मामले में रोहित शेट्टी को ऐसी कोई कॉल नहीं की गई थी। इससे लगता है कि शेट्टी को डराने के लिए फायरिंग की गई है।
>
> -एक वरिष्ठ अधिकारी, मुंबई क्राइम ब्रांच

हथियार की हो रही जांच, कोई हताहत नहीं

पुलिस ने बताया वारदात में कोई घायल नहीं हुआ है। फॉरेंसिक टीमें प्रोजेक्टाइल इकट्ठा कर बैलिस्टिक टेस्ट की मदद से हथियार और बुलेट्स की जांच कर रही है। दावा है कि फायर आर्म्स अच्छी क्वालिटी का है, इसलिए निरपत में आए आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस मामले की तह तक पहुंच रही है। किसके इशारे पर फायरिंग हुई, इसका पता लगाया जा रहा है।

फायरिंग का मकसद अस्पष्ट, लॉरेंस गैंग पर शक

क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि घटना का मकसद साफ नहीं है। सभी आरोपी पुणे के रहने वाले हैं, इसलिए शक है ये हमलावर लॉरेंस गैंग से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पुणे से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर शुभम लोणकर तालुका रखता है। अकोला निवासी शुभम का संबंध बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। पुणे से ही इस गैंग ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रची थी।

सीसीटीवी में सिगरेट पीते दिखा आरोपी

फायरिंग से पहले एक आरोपी सिगरेट पी रहा था। सीसीटीवी में यह कैद हो गया, जिससे उसकी पहचान हुई। एक ऑटो चालक ने पुलिस को बताया कि एक संदिग्ध ने उससे पूछा था कि कल्याण जाओगे? चालक ने कहा कि कल्याण दूर है, लेकिन वह उसे नजदीकी स्टेशन छोड़ सकता है। इससे आरोपियों के पुणे भागने की टिप मिली और पुणे पुलिस को अलर्ट किया गया।

BJP-शिंदे सेनाः आज नगरसेवकों का रजिस्ट्रेशन

रजिस्ट्रेशन से पहले चुना जाएगा ग्रुप लीडर

■ NBT रिपोर्ट , मुंबई : बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नगरसेवक सोमवार को एक साथ रजिस्ट्रेशन कराएंगे। मिली जानकारी के अनुसार, दोनों ही पार्टियों के नगरसेवकों को सुबह 10 बजे तक बीएमसी मुख्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने दिए हैं। बीजेपी के एक नगरसेवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभी नगरसेवक पहले बीएमसी मुख्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद दोनों ही पार्टियों के नगरसेवक एक साथ कोकण भवन जाकर जीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन से पहले एक ग्रुप लीडर का चुनाव किया जाएगा, जो दोनों ही पार्टियों का ग्रुप लीडर होगा। इस बीच, एनसीपी ने शिंदे सेना को समर्थन देने की घोषणा की है।

बता दें कि 16 जनवरी को बीएमसी चुनाव के नतीजों की घोषणा की गई थी। इसमें बीजेपी ने 89, एकनाथ शिंदे सेना ने 29, उद्धव सेना ने 65, कांग्रेस ने 24 और एआईएमआईएम ने 8, एमएनएस ने 6, एनसीपी ने 3 और एनसीपी (SP) ने एक सीट पर जीत हासिल की। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद 15 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी और शिंदे सेना के नगरसेवकों ने अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया है। इस वजह से मुंबई के महापौर का चुनाव नहीं हो पाया है। रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही मुंबई के महापौर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। बीएमसी के कमिश्नर भूषण गगरानी, निनकी टेकरेवू में मुंबई महापौर का चुनाव होना है, उन्होंने बताया कि एक बार पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाए, तो 7 दिनों के भीतर हम मुंबई महापौर का चुनाव भी संपन्न करा लेंगे।

दोनों ही पार्टियों के नगरसेवकों को BMC मुख्यालय में उपस्थित रहने का है निर्देश

NCP के विलय पर अजित पवार ने कभी कोई बात नहीं की थीः CM फडणवीस

CM ने रखी शर्त, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले BJP से सलाह ले NCP

■ NBT रिपोर्ट , मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार गुट के नेताओं के उस दावे को एक तरह से खारिज करते हुए कहा है कि एनसीपी के साथ विलय को लेकर अजित पवार ने उनको कोई चर्चा नहीं की थी। रविवार को उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कुछ होता तो अजित पवार उनसे जरूर इस विषय में बात करते। फडणवीस ने कहा कि उन्हें अजित पवार की शरद पवार के साथ हुई बातचीत की जानकारी नहीं है और उन्हें 12 फरवरी को एनसीपी के विलय की तारीख के बारे में भी नहीं पता है। भविष्य में दोनों एनसीपी के विलय पर एक तरह से शर्त लगाते हुए फडणवीस ने कहा है कि यदि एनसीपी अजित गुट विलय का निर्णय लेती है तो उससे पहले बीजेपी से चर्चा करे। फडणवीस के इस बयान ने एक बार फिर एनसीपी के संभावित विलय को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। फडणवीस ने कहा कि अगर एनसीपी के विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में होतीं, तो अजित पवार ने उन्हें इसके बारे में जरूर बताया होता। क्योंकि वह सभी तरह की जानकारी उनके साथ साझा करते थे। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या एनसीपी के विलय की बातचीत हमारी जानकारी के बिना अंतिम रूप ले सकती है। हमें 12 फरवरी की उस तारीख की जानकारी नहीं है, जिसे विलय की औपचारिक घोषणा की तारीख बताया जा रहा है। एनसीपी एक स्वतंत्र पार्टी है, जो अपने फैसले खुद लेती है। लेकिन बीजेपी की सहयोगी होने के नाते, उससे आगे बढ़ने से पहले हमसे परामर्श करने की उम्मीद की जाती है।

बीजेपी और मेन एनसीपी के दोनों गुटों के विलय का विरोध किए जाने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी ने किसी का विरोध नहीं किया है। अगर पूर्व उप सीएम अजित पवार विलय के उद्देश्य पर काम कर रहे थे, तो क्या वह बीजेपी को विश्वास में लिए बिना ऐसा करते थे? क्या वह एनडीए छोड़ने की तैयारी कर रहे थे? वह जो मुझसे सभी जानकारियां साझा करते थे।

वित्त विभाग पर बजट के बाद निर्णयः सीएम

राज्य के वित्त विभाग को अपने पास रखने के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि उन्होंने इस बारे में एनसीपी नेताओं से बात की थी। मैं राज्य का बजट पेश करूंगा। बजट डेडल भाषण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई विभागीय बैठकें शामिल होती हैं। सुनेत्रा पवार के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुरत उठाना संभव नहीं था और उनसे इसकी अपेक्षा करना गलत है। हम बजट सत्र के बाद (वित्त विभाग पर) निर्णय लेंगे। फडणवीस ने सुनेत्रा पवार को आबकारी, खेल, अल्पसंख्यक विकास और वक्फ विभाग दिए हैं। हालांकि उन्हें वित्त और योजना विभाग नहीं दिए गए, जो अजित पवार के पास थे।

अमोल मिटकरी ने राज ठाकरे को सुनाई खरी-खरी

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: एनसीपी (एपी) के नेता अमोल मिटकरी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए साफ कहा कि उनकी पार्टी ने राज ठाकरे से कोई सलाह नहीं मांगी है। बेहतर होगा कि राज ठाकरे अपनी सलाह और सुझाव अपने तक ही सीमित रखें।

दरअसल, राज ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर लिखा था कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जैसी मराठी-केंद्रित पार्टी का अध्यक्ष मराठी होना चाहिए और वह पाटील होना चाहिए, न कि पटेल। अमोल मिटकरी ने इस पर कहा कि इस संवेदनशील समय में ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे भी एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं और अगर उनकी पार्टी में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती और एनसीपी की ओर से ऐसी टिप्पणी की जाती, तो वही लोग कहते कि हममें ईमानदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीपी में सभी समुदायों और सामाजिक वर्गों के लोग शामिल हैं और सभी की राय से ही सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री और ग्रुप लीडर बनाए जाने का निर्णय लिया गया।

संजय शिरसाट पर भी साधा निशाना

सुनेत्रा पवार का राजनीतिक अनुभव मजबूत रहा है और राजनीति उनके लिए कोई नई बात नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं को पूरा भरोसा है कि अगर कोई अजित पवार की जिम्मेदारी संभाल सकता है तो वह सुनेत्रा पवार ही है। संजय शिरसाट पर निशाना साधते हुए मिटकरी ने कहा कि उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कहा कि एनसीपी कराता जवाब देने में सक्षम है, लेकिन फिलहाल पार्टी गहरे सदमे से उबर रही है।

नवभारत टाइम्स

Enterटेनमेंट masalamix

'आज का सिस्टम भाई-भतीजावाद, ग्रुपिज्म का है'

अमाल मलिक ने कहा कि अगर इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो एआर रहमान ने जो बात कही, वे काफी हद तक सही हैं पर मैं इसके साम्प्रदायिक पक्ष से सहमत नहीं हूं। आज का सिस्टम भाई-भतीजावाद या गुपिज्म का है। कई कंपनियां अपने 'कंटाग्रेट' कलाकारों को प्रमोट करती हैं।

अपरा मेहता

'माधवन हैरान थे कि सबको मेरे साथ फोटो लेनी थी'

Upma.Singh@timesofindia.com

Q आपको अभिनय की दुनिया में 50 साल हो गए। क्या चीज आपको एंटेटेन करते रहने के लिए प्रेरित करती है?

पैलेन: इस प्रेजेंशन की यही खूबी है कि एक ऐक्टर कभी ये नहीं कह सकता कि उसे सब आता है। मेरे नए शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बीदणी की ही बात लीजिए, इस रोल में ढलने के लिए मैंने काफी स्ट्रगल किया क्योंकि इसमें मारवाड़ी टोन डाल कितदार है, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। असल में मेरी हिंदी, ओरीनी, गुजराती, मराठी चारों भाषाएं साफ हैं तो इसमें मारे-बारे वाली भाषा पकड़ने में मुश्किल हुई। ऐसे ही, जब ओटीटी के लिए वेब सीरीज की, तो यहां बहुत नैचरल ऐक्टिंग करनी होती है। वो असल पैलेन है क्योंकि मेरे लाइन पर जोर देने की आदत पड़ जाती है। ओटीटी पर फास्ट बोलना होता है, ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं होते। टीवी में ओवर द टॉप होता है तो ये जो नए-नए पैलेन हैं, वो मुझे हमेशा उत्साहित रखते हैं।

पांच दशक से अपने अभिनय की छाप छोड़ने वाली अपरा मेहता आज भी सक्रिय हैं। पिछले साल सीरीज ऊप्स अब क्या और अपने सुपरहिट शो 'क्योंकि सास भी...' के सीक्वल के लिए चर्चा में रही अपरा इन दिनों टीवी शो प्रथाओं की ओढ़े चुनरी: बीदणी में नजर आ रही हैं। हमने की उनसे खास बातचीत:

Q आप देवदास, तीस मार खां, चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी बेहद चर्चित फिल्में कीं हैं। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार जैसे स्टार के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

अच्छा अनुभव रहा क्योंकि चाहे शाहरुख हों, माधुरी हों या अक्षय, ये सब मुझे अच्छे से जानते थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी इतना बड़ा शो था कि सब मुझे पहचानते थे। जब मैं माधवन के साथ डीकपलड कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि आपने बहुत काम किया है, तो मैंने कहा कि हां, क्योंकि हम जब दिल्ली में शूट कर रहे थे तो हर कोई मेरे साथ फोटो लेना चाहता था। हर जगह मेरे साथ यही होता था तो सबको मेरे काम का पता था। फिर, मैंने जो फिल्मों की, वो सभी ब्लॉकबस्टर मुझे लेना चाहते थे। देवदास के लिए संजय लीला भंसाली ने मुझे फोन किया। जस्ट मैरेड मैंने मेघना गुलजार के लिए की थी। तीस मार खां में फराह लेना चाहती थीं। ओटीटी में भी डायरेक्टर मुझे चाहते थे। मुझे लगता है कि उन्हें इसके लिए लड़ना भी पड़ा होगा कि वे एक टीवी ऐक्टर को लेना चाहते हैं क्योंकि ओटीटी में यह सोच काफी है ओह, ये टीवी का चेहरा है या ओवर एक्सपोज्ड है, लाउड ऐक्टर है। जबकि ये गलत है। मैं जोर देकर कहूंगी कि टीवी के ऐक्टर बहुत अनुभवी होते हैं और हमें लोग बहुत ज्यादा पहचानते हैं, तो इसमें उनका ही फायदा है।

Q कोई सामाजिक प्रथा है, जो आपको नामंजूर लगती है?

मुझे तो वहीं से दिक्कत होती है कि क्यों एक लड़की को ही शादी के बाद अपना घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है? क्यों उसे पति का सरनेम जोड़ना पड़ता है? मैंने इतने साल पहले भी जब शादी की थी तो अपना सरनेम नहीं बदला था। मैंने अपना सरनेम ही रखा। मैं अपने पैरेंट्स की इकलौती बच्ची हूं तो मैं उनका नाम आगे लेकर जाना चाहती थी और मुझसे कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि क्यों मैं अपना सरनेम नहीं बदल रही हूं। इसी तरह, हम एक कपल के तौर पर एक ही बच्चा चाहते थे, वह भी एक बेटी। हमें वो मिली भी तो हमने उसके बाद दूसरे बच्चे का कभी सोचा नहीं। मैं खुद अपने पैरेंट्स की इकलौती बेटी हूं। उन्होंने मुझे एक इंसान के तौर पर बड़ा किया, एक लड़की के तौर पर नहीं। कई बार लोग बोलते हैं न, ओह पापा बेटी का बड़ा अच्छा ख्याल रख रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वो उसका भी तो बच्चा है, उसे ख्याल रखना ही चाहिए तो मुझे इन सारी रूढ़िवादी बातों से दिक्कत होती है।

Q इस शो में आप रूढ़िवादी प्रथाओं की समर्थक हैं। निजी जीवन में कभी आपको ऐसी प्रथाओं का सामना करना पड़ा?

नहीं, मुझे कभी ऐसी किसी चीज का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दोनों (मायका-ससुराल) ही तरफ से बहुत ही प्रोग्रेसिव परिवार से हूं। मैं मुंबई की गुजराती हूं। हमारी नागर कम्युनिटी है, जो मातृसत्तात्मक है। हमारे यहां औरतें कल करती हूं। वो बहुत पढ़ी-लिखी होती हैं। हमारे यहां बेटी का जन्म बेटे से ज्यादा शुभ माना जाता है तो मैंने कभी ऐसा कुछ में नहीं झेला है। काम के दौरान भी थिएटर, टीवी और जो फिल्में मैंने कीं, वहां भी कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ लेकिन मैं दूसरों के साथ ये सब होते देखती हूं।

उदयपुर के सिटी पैलेस में होगी रश्मिका-विजय देवरकोंडा की शादी?

साउथ के फेमस कलाकार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को लेकर जेरसोर से चर्चा हो रही है। अभी तक उन्होंने या साउथ एक्टर विजय देवरकोंडा ने वेडिंग पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन रिपोर्ट्स में लगातार दावा किया जा रहा है कि वे फरवरी 2026 में सात फेरे लेंगे। अब एक सोशल मीडिया यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया है और दावा किया है कि उदयपुर के सिटी पैलेस में रश्मिका और विजय 2 फरवरी को शादी करेंगे, जिसके लिए पूरे वेन्यू को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। एक इंस्टाग्राम यूजर ने एक वीडियो पोस्ट किया।

उन्होंने बताया कि वो उदयपुर के सिटी पैलेस में हैं और वहां पर लगातार डेकोरेशन चल रहा है और पता चला है कि रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी है। वो कहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं और वहां की एक-एक सजावट भी दिखाते हैं। इसमें दिखाया गया है कि पैलेस के अंदर लाल रंग के बड़े पर्दों से सजावट की जा रही है। बड़े-बड़े झूमर जमीन पर रखे हुए हैं। वेन्यू को देखकर ऐसा लग रहा कि किसी फिल्म का सेट है। खाने-पीने के मेहतर जैसे बर्तनों की भी झलक देखने को मिल रही है। इस वीडियो पर कई यूजर्स के रिएक्शन हैं। एक ने कहा कि काश ये खबर सच हो जाए। दूसरे ने कहा, 'क्या यह प्रोडेसी का उल्लंघन नहीं है?' एक ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वेडिंग की डेट पता करो। तीसरे ने बोला, 'अगर ये सच भी है तो आप जानकारी क्यों लीक कर रही हैं।' अक्टूबर 2025 में खबर आई कि रश्मिका और विजय ने गुपचुप तरीके से हैदराबाद में सगाई कर ली है। रश्मिका और विजय ने 'गीता गोविंदम' (2018) फिल्म में साथ काम किया था, जिसके बाद उनकी डेटिंग की अफवाह उड़ने लगी थीं, मगर इस बात की भी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई थी।

@charanpeddiconda

रामचरण और उपासना बने जुड़वा बच्चों के पैरेंट्स

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर राम चरण और उनकी पत्नी उपासना कोनिदेला अब तीन बच्चों के माता-पिता बन गए हैं। कपल ने जुड़वां बच्चों - एक लड़का और एक लड़की का स्वागत किया है। चिरंजीवी ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की कि राम और उपासना जुड़वां बच्चों के माता-पिता बन गए हैं।

उन्होंने लिखा, 'अत्यंत खुशी और कृतज्ञता से भरे दिल के साथ, हम यह शेयर करते हुए खुश हैं कि राम चरण और उपासना को जुड़वां बच्चों - एक बेटा और एक बेटी का आशीर्वाद मिला है। दोनों बच्चे और मां स्वस्थ हैं। इन नन्हे-मुन्नों का अपने परिवार में स्वागत करना हमारे लिए दादा-दादी के रूप में अत्यंत आनंद और ईश्वरीय आशीर्वाद का पल है। हम सभी के प्रार्थनाओं, प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए तहे दिल से आभारी हैं - चिरंजीवी और सुरेखा।' बता दें कि राम चरण और उपासना ने 2012 में शादी की थी। इन्होंने शादी के 11 साल बाद 2023 में बेटी क्लिन कारा का स्वागत किया था।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP9 User: cci Time: 02-01-2026 23:11 Color:

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के बाद घर लौटने पर मैंने किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया। नए साल के शुरू से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू किया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। - सूर्यकुमार यादव, कप्तान, टीम इंडिया

सबसे कम उम्र में पूरा किया करियर ग्रैंडस्लैम

अल्काराज

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: रोड लेवर एरिना में ऐतिहासिक रात के दौरान कार्लोस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल्स खिताब जीतकर करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। वर्ल्ड नंबर-1 अल्काराज ने 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच को खिताबी मैच में 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। तीन घंटे दो मिनट तक चले मुकाबले में जीत के साथ 22 वर्षीय अल्काराज ने डॉन बज की 1938 रोलां गैरों के दौरान बनाई गई उपलब्धि को पीछे छोड़ दिया। वह अमेरिकी खिलाड़ी ने अपने 23वें जन्मदिन से ठीक पहले (22 साल और 363 दिन) करियर ग्रैंडस्लैम पूरा किया था। अल्काराज ओपन एरा में सात ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं, उन्होंने 23 साल की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले ब्योर्न बोर्ग का रेकॉर्ड तोड़ा।

फाइनल में जोकोविच की पहली हार: अल्काराज करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले सिर्फ नौवें खिलाड़ी हैं और ऐसा ऑस्ट्रेलियन ओपन में करने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि मेलबर्न में इससे पहले जोकोविच को फाइनल में कोई भी हरा नहीं पाया था। जोकोविच ने इससे पहले 10 के 10 फाइनल में खिताबी जीत हासिल की थी। फाइनलिस्ट की सिल्वर ट्रॉफी पहली बार थाम रहे जोकोविच ने भी अपने युवा प्रतिद्वंद्वी की ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की। उन्होंने कहा, 'आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है, इसलिए बधाई। मैं आपके शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं।'

फिटनेस और जबर्दस्त स्टेमिना: दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबर्दस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बढ़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक पॉइंट्स में से पांच का फायदा उठाया, जबकि जोकोविच छह ब्रेक पॉइंट्स में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके। साल 2023 यूएस ओपन के बाद पहला मेजर जीतने की तलाश में लगे जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युग में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज प्लेयर बनने की राह पर थे।

6.03
करोड़ अमेरिकी डॉलर अब तक प्राइज मनी के तौर पर जीत चुके है कार्लोस अल्काराज। वह ऑलटाइम लिस्ट मे पांचवें नंबर पर है

22
साल और 272 दिन की उम्र में सभी चार ग्रैंडस्लैम में सिंगल्स खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के मैंस खिलाड़ी बने अल्काराज

AO ऑस्ट्रेलियन ओपन

कोई नही जानता कि मै यह ट्रॉफी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैने इस पल का बहुत पीछा किया। मुझे आपको (जोकोविच) खेलते देखना बहुत पसंद है, आपके साथ लॉकर रूम और कोर्ट साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप जो कर रहे है उसके लिए बहुत धन्यवाद, यह सच मे प्रेरणादायक है। - कार्लोस अल्काराज

NBT Lens खबरों के अंदर की बात

'सोलह' साल का दिलचस्प आंकड़ा

इस मुकाबले मे जोकोविच और कार्लोस की उम्र मे 16 साल का आंतर, ओपन एरा के मैंस सिंगल्स ग्रैंडस्लैम फाइनल्स मे दूसरा सबसे बड़ा था। 22 बार के ग्रैंडस्लैम चैंपियन राफेल नडाल भी फाइनल मे मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि साल 2010 मे नोवाक को ही चार सेट तक चले फाइनल मे शिकस्त देते हुए नडाल ओपन एरा मे सबसे कम उम्र मे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने का रेकॉर्ड बनाया था। अब करीब 16 साल बाद अल्काराज ने जब यह उपलब्धि अपने नाम की तब भी उनके सामने भी नोवाक ही खड़े थे और यह चार सेट तक चला।

मुकाबला भी

250

रन से अधिक का स्कोर चार टी20 इंटरनैशनल मैचों में बनाया है भारतीय टीम ने। यह एक रेकॉर्ड है

स्पोर्ट्स QUIZ

इस पेज पर छपी खबरों में ही इन सवालों का जवाब है।

1. कार्लोस अल्काराज अब तक कुल कितने ग्रैंडस्लैम सिंगल्स खिताब जीत चुके है?
A) पांच B) सात C) दस D) छह
2. शटलर देविका सिहाग के सामने वाइल्ड मास्टर्स के फाइनल मे किस देश की प्लेयर थीं?
A) चीन B) साउथ कोरिया C) इंडोनेशिया D) मलयेशिया

कल के जवाब
1. C) 2 2.A) बेन हवरशुइस

लकी WINNER

1. बलविंदर सिंह, नीता कॉलोनी, दिल्ली
2. नीलामी सिंहल, गाजियाबाद, यूपी
3. दिनेश पी वर्मा, जोगेश्वरी ईस्ट, मुंबई

आप अपने जवाब हमें 9319282367 पर अपने नाम, तस्वीर और शहर/गांव के नाम के साथ वॉट्सऐप करें। एक 'लकी विनर' का नाम और तस्वीर हम कल के अंक में छापेंगे। दो अन्य विजेताओं के नाम भी प्रकाशित होंगे।

फटाफट खबरें

भारत-बांग्लादेश भिड़ंत

■ पोचेफस्ट्रूम: भारतीय टीम सीनियर अंडर-19 विमिंस फुटबॉल चैंपियनशिप के अपने दूसरे मुकाबले मे सोमवार को पोचेफ्स्ट्रूम स्टेडियम में मजबूत बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी। भारत की कोशिश एक मैच शेष रहते फाइनल मे जगह पक्की करने की होगी। भारतीय टीम अगर इस मैच को जीतने मे सफल रही तो फाइनल के लिए उसका दावा लगभग पक्का हो जाएगा।

पंजाब का दबदबा

■ नई दिल्ली: पंजाब के हरवीराज सिंह, हरजीत सिंह अटवाल और नुरफतेह सिंह सांधू ने क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल कर रविवार को शटलर राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स एक और दो मे जूनियर पुरुष स्कीट टी2 के फाइनल मे क्वीन स्वीप किया। अनवजीत सिंह नरूका ने पुरुष वर्ग के ट्रायल दो फाइनल में 36 में से 36 का परफेक्ट स्कोर कर ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया को एक अंक से पछाड़ते हुए खिताब पर कब्जा जमाया।

वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मुकाबले से हट गया पाकिस्तान

भारत-पाक तनातनी

■ एजेंसियां, लाहौर: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ICC टी20 वर्ल्ड कप के अपने हाई प्रोफाइल ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की सदे को औपचारिक घोषणा कर दी। हालांकि, सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों मे राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को इस वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किए जाने के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अपने मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग की थी लेकिन ICC ने उसे ठुकरा दिया था।

सोशल मीडिया पर घोषणा: पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान मे कहा, 'इसलामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।' इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है।

पॉइंट के लिए भारत को जाना होगा कोलंबो: यदि पाकिस्तान मैच नहीं खेलता है तो वॉकओवर के जरिए पूरे अंक भारत को मिल जाएंगे। हालांकि, इसके लिए भारतीय टीम को मैच के लिए कोलंबो में मौजूद रहना होगा। यदि दोनों ही टीमें मैदान पर नहीं जाएंगी तो मैच को रद्द घोषित कर अंक दोनों में बराबर बांट दिए जाएंगे। पाकिस्तान को 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करनी है।

अंडर-19 टीम इंडिया ने पाक को पटकनी देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली

वेदांत त्रिपाठी ने बनाए सर्वाधिक 68 रन

बुलवायो: वनिष्क चौहान के हरफनमौला प्रदर्शन (35 रन, 30 रन पर 1 विकेट) से भारत ने सुपर-6 मैच मे पाकिस्तान को 58 रन से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई, जहां उसका मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। भारत ने 49.5 ओवर में 252 रन बनाए जिसमे वेदांत त्रिपाठी ने सर्वाधिक 68 रन जोड़े। पाकिस्तान को बेहतर रन-रेट के आधार पर सेमीफाइनल मे पहुंचने के लिए 33.3 ओवर्स मे 253 रन बनाने थे। टीम 33.3 ओवर्स मे चार विकेट पर 167 रन ही बना सकी और अंततः 46.2 ओवर्स में 194 रन पर ऑलआउट हो गई। वनिष्क ने 40 रॉट बॉल खेलते हुए पाक की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। विपनर खिलन पटेल ने 9.2 ओवर्स मे 35 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि उसान आयुष म्हात्रे ने भी 3 विकेट झटके।

अनाहत ने जीता मुकाबला खिताबी मैच में जगह बनाई

■ एजेंसियां, नई दिल्ली: भारत की अनाहत सिंह ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए वॉशिंगटन में चल रहे स्कवैश ऑन फायर ओपन में अमेरिका की सबरीना सोमी को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वह पहली बार पीएसए ब्रॉन्ज लेवल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची। वर्ल्ड रैंकिंग्स में 31वें स्थान पर काबिज और इस टूर्नामेंट में सातवीं वरीयता प्राप्त अनाहत ने सेमीफाइनल में वर्ल्ड रैंकिंग्स में 23वें स्थान पर काबिज सबरीना को 11-9, 11-3, 9-11, 11-5 से हराया। फाइनल में अनाहत का सामना इंग्लैंड की शीर्ष वरीयता प्राप्त और वर्ल्ड रैंकिंग्स में 10वें स्थान पर काबिज जॉर्जीना कैनेडी से होगा।

स्क्वैश टूर्नामेंट

अनाहत सिंह

दिल्ली-मुंबई मैच ड्रॉ, अंतिम-8 के मैच तय

■ एजेंसियां, मुंबई: कप्तान अजुष टोमेना की 159* रन की पारी की बदौलत दिल्ली ने रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप-डी में तालिका में शीर्ष पर काबिज मुंबई के खिलाफ मुकाबला ड्रॉ करा लिया। इसी ग्रुप मे जम्मू-कश्मीर ने भी 42 बार की चैंपियन मुंबई के साथ क्वार्टर फाइनल फाइनल में जगह बनाई। टोमेना ने एमसीए-बीकेसी ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में 230 गेंदों में 11 फोर और दो सिक्स की मदद से 159* रन बनाए और मुंबई को जीत से दूर रखा। दोनों टीमों ने टी-ब्रेक से करीब आधा घंटा पहले मुकाबला बराबरी पर समाप्त करने पर सहमति जता दी। दिल्ली ने दूसरी पारी छह विकेट पर 407 रन बनाकर घोषित की। उस समय उसकी कुल बढ़त 311 रन की थी। दिल्ली आठ टीमों की ग्रुप तालिका में सातवें स्थान पर रही।

सनत सांगवान रहे प्लेयर ऑफ द मैच

विदर्भ, आंध्र भी बढ़े: नागपुर में खेले गए मैच में गत चैंपियन विदर्भ ने उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप-ए से आंध्र के साथ टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप-ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। यूपी के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ ने 58.2 ओवर मे लक्ष्य हासिल कर लिया।

पडिक्कल की सेंचुरी से कर्नाटक जीता: मोहाली मे कप्तान देवदत्त पडिक्कल की 85 गेंद में 120 रन की पारी से कर्नाटक ने ग्रुप-बी के अपने आखिरी मैच में पंजाब को पांच विकेट से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। पडिक्कल की आठवीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी की बदौलत कर्नाटक ने 27.5 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। ग्रुप-बी से कर्नाटक (27 अंक) और मध्य प्रदेश (28 अंक) ने नॉकआउट में जगह बनाई।

क्वॉर्टर फाइनल लाइन अप
रणजी का रण
पहला- झारखंड Vs उत्तराखंड
दूसरा- एमपी Vs जम्मू-कश्मीर
तीसरा- बंगाल Vs आंध्र प्रदेश
चौथा- मुंबई Vs कर्नाटक
(सभी मैच 6 से 10 फरवरी के बीच खेले जाएंगे)

वर्ल्ड कप में दिन के मैच चुनौती: सैटनर

■ एजेंसियां, तिरुवनंतपुरम: न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर ने कहा कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हथ्थाहीन में अपने पिछले अनुभव और विभिन्न परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की अपनी क्षमता पर भरोसा करेगी। सैटनर ने कहा, 'दिन का खेल थोड़ा अलग होने वाला है। खिलाड़ियों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। उन्हें थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश करनी होगी। लेकिन फिर भी यह हमारे लिए एक नई चुनौती है। हम लाल मिट्टी की पिच पर एक मैच खेलने के लिए अहमदाबाद जाएंगे और फिर हम काली मिट्टी की पिच पर खेलने के लिए चेन्नै जाएंगे। इसलिए यह थोड़ा अलग होगा।'

रिएक्शंस

मिचेल सैटनर

केंद्रीय बजट में रखा खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव

■ एजेंसियां, नई दिल्ली: वित्तवर्ष 2026-27 के बजट मे देश में खेलों के विकास के लिए किए गए कुछ अहम प्रावधान-

- 'खेलो इंडिया मिशन' शुरू करने का प्रस्ताव। इससे जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज के लिए सरकार के प्रमुख 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा।
- खेलों के सामान के लिए डेडिकेटेड पहल का प्रस्ताव जिसमें उपकरण डिजाइन, सामग्री विज्ञान में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा।
- युवा मामले और खेल मंत्रालय के आवंटन मे 1000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि की गई। खेल सामग्री निर्माण क्षेत्र को पहली बार 500 करोड़ का आवंटन मिला।
- खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन 4479.55 करोड़ रुपये है जो 2025-26 के संशोधित आवंटन 3346.54 करोड़ रुपये से 1133.34 करोड़ रुपये अधिक है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के लिए आवंटित राशि को $80 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 917.38 करोड़ रुपये किया गया।

देविका ने जीता करियर का सबसे बड़ा खिताब

■ एजेंसियां, बैंकॉक: भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने 250,000 डॉलर इनामी वाइल्ड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के विमिंस सिंगल्स का खिताब जीता। फाइनल में मलयेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद देविका ने अपना पहला सुपर-300 खिताब हासिल किया। हरियाणा की 20 वर्षीय देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब दो बार की वर्ल्ड जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मैच से हटने का फैसला किया। इससे देविका अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रहीं। वह सुपर-300 विमिंस सिंगल्स खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय है। देविका से पहले पद्म उपलब्धि केवल पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने ही हासिल की थी।

वाईल्ड मास्टर्स बैडमिंटन

देविका सिहाग

प्रग्नानंदा और गुकेश की बाजी रही ड्रॉ

■ एजेंसियां, विज्क आन जी: वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें राउंड में हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने मैथियस ब्लुबाउम पर जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ाए। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रग्नानंद के खिलाफ नॉकिम नहीं लिया, जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वह हमवतन अब्दुसत्तोरोव से आधा अंक पीछे है। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक राउंड का खेल बचा है और उन्कोविकास ने ये दोनों खिलाड़ी शीर्ष दो स्थान पर काबिज हैं।

टाटा मास्टर्स चेस टूर्नामेंट

आर प्रग्नानंद

12 राशियां और आपका दिन

ARIES 21 Mar - 19 Apr
राशि स्वामी मंगल, मकर राशि पर अ चंद्रमा है। चंद्रमा आज चतुर्थ भाव मे होने से गृहोपयोगी वस्तुओं मे वृद्धि होगी। अर्थिक्क कार्यकी या किसी रिश्तेदार के कारण खर्च मिल सकता है। रुपए पैसे के लेन-देन मे सावधानी रखें। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। वहन प्रयोग मे सावधानी रखें।

TAURUS 20 Apr - 19 May
राशि का स्वामी शुक्र नवम भाव मे और राहु कुंभ राशि का होकर दशम राज्य भाव मे होने से जीविका के क्षेत्र मे चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। राजनीतिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें। वाणी पर संयम रखें। रिश्तेमें फासले होंगे। मित्रों से सहयोग हासिल होता रहेगा।

GEMINI 21 May - 21 Jun
आज राशि से द्वितीय भाव मे चंद्रमा मन को संतोष देने वाला है। अष्टम भाव मे बुध से व्यवसायिक परिस्थिति बढ़ेगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से अपने स्वभाव एवं कर्तव्य में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। मैत्री संबंध मधुर होंगे।

CANCER 22 Jun - 22 July
आज राशि स्वामी चंद्र द्वितीय भाव मे होकर कोष वृद्धि का संकेत दे रहा है। उत्तरार्ध जीवन सुखमय होगा। धन, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक व मानसिक उन्नति मिल सकता है। परीक्षा की दिशा में किया गया श्रम सफलता होगा। रिश्तेमें फासले होंगे। हनुमान मंदिर के दर्शन करें या सुंदरकांड का पाठ करें।

LEO 23 July - 22 Aug
प्रथम भाव का चंद्रमा और स्वामी गुरु मे कुंभ राशि का राहु आज प्रभाव प्रदान को बढ़ाने वाला है, रोजी रोजगार की दिशा मे सफलता मिलेगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। दूसरों के सहयोग लेने मे सफल होंगे। यात्रा देवालय की रिश्तों सुखद व लाभप्रद होगी। प्रियजनों से भेंट संभव है।

VIRGO 23 Aug - 22 Sep
द्वादश भाव मे चंद्रमा शुभ प्रदान, वीर्य के वृद्धिकारक है। व्यावसायिक दिशा मे सफलता मिलेगी। खान-पान मे संयम रखें। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तेमें का फासला होगा। रोजी रोजगार मे सफलता मिलेगी। पानी के परिवर से लाभ मिल सकता है।

LIBRA 23 Sep - 22 Oct
राशि स्वामी शुक्र-मंगल राशि का होकर चौथे भाव मे और मकरराशि भाव मे चंद्रमा के प्रभाव से राजनैतिक दिशा मे किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी अभिन्न मित्र से मिलने की संभावना है। अर्थ और व्यय मे संतुलन बनाकर रखें। आज के दिन मित्रों का सहयोग बना रहेगा। मुंह-फलोस मे न पड़े, इससे परेशानी हो सकती है।

SCORPIO 23 Oct - 21 Nov
राशि स्वामी के मंगल राशि पर होने और तृतीय भाव मे चंद्रमा होने से पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। रुका हुआ कार्य संपन्न होगा। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने से चौंकी की संभावना है। झगड़ों से दूरी बनी रहेगी। सुख साधन, वाहन, मकान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अपने और नई मे अकारण शत्रुपीड़ा होकर उनका मान मर्दन भी हो जाएगा। इस वर्ष जून, जुलाई, अगस्त में किसी मांगलिक कार्य का अनुष्ठान अथवा प्रतिष्ठात्मक कार्य भी अपके परिवार मे होंगे। सिंतबर से अक्टूबर में रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी और निकट संबंधी अपके इर्द-गिर्द घूमेंगे। नवंबर से दिसंबर में वर्ष की भागदौड़ में रचाई व आधाई व्यापार का विस्तार एवं धार्मिक स्थानों पर पर्यटन का योग है। जनवरी 2027 से फरवरी तक ग्रहयोग अपके पुरुषार्थ को उजागर करेगा। -आचार्य कृष्ण दत्त शर्मा

SAGITTARIUS 22 Nov - 21 Dec
द्वादश स्थानपति राशि पर और चंद्रमा नाम प्रमुख त्रिकोण स्थान मे चल रहे हैं। इसके चलते आर्थिक दिशा मे सफलता मिलेगी। वाणी की सौम्यता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। खान-पान मे संयम बरतें। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग बन रहे है।

CAPRICORN 22 Dec - 19 Jan
आपकी राशि से द्वितीय राहु और राशि का स्वामी शनि पराक्रम स्थान तृतीय मे होने के कारण व्यवसायिक योजना को बल मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र मे परिवर्तन के सामान करना पड़ सकता है। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। रिश्तेमें फासले होंगे। शत्रु को भूलने जाने का योग बन सकता है।

AQUARIUS 20 Jan - 18 Feb
आज स्वामी प्रमुख केंद्र, पानी भाव मे सिंह राशि का चंद्रमा होने के फलस्वरूप कौटुम्बिक व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। आर्थिक दिशा मे किए प्रयास सफल होंगे। खान-पान पर संयम रखें। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। किसी भी तरह के झगड़े और विवाद से बचें।

PISCES 19 Feb - 20 Mar
राशि स्वामी बृहस्पति पंचम सुख मित्र भाव मे राज्य मान-प्रतिष्ठा वृद्धि प्रदान है। रोजगार के क्षेत्र मे चल रहे प्रयास फलीभूत होंगे। राजनैतिक सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति उदासीन न रहें। अधनस्थ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। हर्षातिर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। वाणी पर संयम रखें। रिश्तेमें मधुरता आएगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

जन्मदिन की शुभकामनाएं

यह वर्ष चांदी के पद से प्रवेश कर रहा है। वर्ष का स्वामी मंगल बुध बन रहे है। मंगल भूमि का स्वामी, युद्ध प्रिय, सहसही, अक्रमी, सुव्यवस्थापक यह है। जिसकी बुध का सानिध्य बौद्धिक गुणों वाला, कुशल व्यापारी भी बना देता है। फरवरी शेष से मार्च तक खेलूं सुख साधन, वाहन, मकान प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अप्रैल और मई मे अकारण शत्रुपीड़ा होकर उनका मान मर्दन भी हो जाएगा। इस वर्ष जून, जुलाई, अगस्त में किसी मांगलिक कार्य का अनुष्ठान अथवा प्रतिष्ठात्मक कार्य भी अपके परिवार मे होंगे। सितंबर से अक्टूबर में रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी और निकट संबंधी अपके इर्द-गिर्द घूमेंगे। नवंबर से दिसंबर में वर्ष की भागदौड़ में रचाई व आधाई व्यापार का विस्तार एवं धार्मिक स्थानों पर पर्यटन का योग है। जनवरी 2027 से फरवरी तक ग्रहयोग अपके पुरुषार्थ को उजागर करेगा। -आचार्य कृष्ण दत्त शर्मा

कल का पंचांग (मंगलवार, 3 फरवरी 2026)

राष्ट्रीय तिथि शक 14, शक संवत 1947, फाल्गुनी कृष्ण द्वितीय मंगलवार, विक्रम संवत 2082। सौर मास माघ प्रविष्टे 21, हज्जाज 14, हिजरी 1447 (मुहर्रम) तद अनुसार अंग्रेजी तारीख 3 फरवरी 2026 है। सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल, शिशिर ऋतु। राहु काल अपराह्न 3 बजे से 4 बजकर 30 मिनट तक। द्वितीया तिथि अंग्रेजीकाल 12 बजकर 41 मिनट तक के बाद तृतीया तिथि का आरंभ। मघा नक्षत्र रात 10 बजकर 15 मिनट तक के बाद पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र का आरंभ। वैशिल करण अपराह्न 1 बजकर 17 मिनट तक के बाद वणिज करण का आरंभ।

सुडोकू

		4	3		6	5		
		6				7		
2	3						8	1
	4		5		3		2	
		2				3		
	7		8		1		5	
4	9						7	3
		8				9		
		1	7		5	8		

TELEVISION

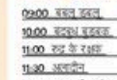

big magic

09:00 बड़ा इंडल
10:00 बड़ाध बड़बड़
11:00 रुद के रहस्य
11:30 अजाजील
12:00 शहादती अंतेश कृष्णा
13:30 म से भड़े
14:30 हम पाप
15:00 अजब देश की गजब कहानी
16:30 प्यार मोहब्बत हैप्पी लवली
18:30 रुद के रहस्य
21:00 पीरुस

देश-विदेश

मोदी का पंजाब दौरा, एयरपोर्ट का नाम संत रविदास के नाम पर रखा

■ भाषा, जालंधर

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को पंजाब दौरे पर रहे। वे जालंधर में देरा सचखंड बल्लां गए। वहां उन्होंने समाज सुधारक और कवि के रूप मे याद किए जाने वाले संत गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

संप्रदाय के प्रमुख संत निरंजन दास को 25 जनवरी को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी। इसके कुछ दिन बाद मोदी ने यह यात्रा की। जालंधर के बल्लां मे स्थित देरा सचखंड, राज्य मे रविदासिया समुदाय का सबसे बड़ा डेरा है। मोदी ने कहा, मैं पंजाब की इस धरती को नमन करता हूं। मतलब मैं पंजाब की धरती को नमन करता हूं। मोदी ने रविवार को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर किया और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी दिन में लगभग तीन बजे आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे। राघवोट रायबाड़े के अड्डे का नाम हलवारा से भारतीय वायु सेना अड्डे पर विकसित इस टर्मिनल से क्षेत्र में हवाई संपर्क में सुधार होने और इंडस्ट्रियल और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हम गुरु रविदास से प्रेरणा लेते है। संत रविदास के आशीर्वाद से, मुझे विश्वास है कि हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

पीएन संप्रदाय के प्रमुख संत निरंजन दास से भी मिले।

दीपथून केस के जज पर टिप्पणी: केस दर्ज

■ पीटीआई, नई दिल्ली : तमिलनाडु के डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ कथित जाति और धर्म के आधार पर की गई टिप्पणियों के मामले में संबंधित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर 'कार्तिगई दीपम' जलाने की इजाजत से जुड़े आदेश के बाद जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ ये टिप्पणियां की गई थीं। डीजीपी जी. वेंकटरमण ने कहा कि राज्य के सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसी किसी चीज को प्रकाशित न होने दें, जिससे जज की छवि को धूमिल करने वाला कंटेंट हो।

फलस्तीनियों के लिए रफाह क्रॉसिंग खोलने का ऐलान

■ एपी, काहिरा: इसराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवाजाही के मद्देनजर गाजा की इंक्लेव के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गई। क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इसराइल-हमास सीजफायर के आगे बढ़ने की दिशा मे एक अहम कदम माना जा रहा है। इसराइल ने घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। इसराइली सैन्य एजेंसी ने एक बयान मे कहा कि क्रॉसिंग को पूरी तरह खोलने के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है और तैयारियां पूरी होने के बाद गाजा के निवासी वहां से आ और जा सकेंगे। इंक्लेव के एक अधिकारी ने बताया कि फलस्तीनी सुरक्षा अधिकारी इंक्लेव वाले गेट से होकर क्रॉसिंग में दाखिल हुए और फलस्तीनी गेट की ओर बढ़े, जहां वे एक यूरोपीय मोब मिशन के साथ जुड़ेंगे, जो एंट्री और निकास की निगरानी करेगा।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP10 User: cci Time: 02-01-2026 23:29 Color:

NBT AI टाइम मशीन

जब वेटलैंड्स को बचाने का संकल्प लिया

आज वर्ल्ड वेटलैंड (Wetland) डे है। आज ही के दिन 1971 में ईरान के रामसर शहर में इन जल-क्षेत्रों को बचाने का संकल्प लिया गया था। वेटलैंड्स यानी वह जमीन जो पानी से ढकी रहती है। इन्हें 'धरती का स्पंज' कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ का पानी सोखते हैं और प्रदूषण साफ कर हमें साफ पानी देते हैं। आज डेटलैंड्स जंगलों से भी तीन गुना तेजी से खत्म हो रहे हैं, जो दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है।

NBT

Front Page-2

नवभारत टाइम्स। मुंबई रविवार, 2 फरवरी 2026, पेज 10

वेटलैंड्स के संरक्षण में AI होगा अहम

ChatGPT के अनुसार, भविष्य में वेटलैंड्स का संरक्षण तकनीक के जरिए और मजबूत होगा। AI, सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर की मदद से जलस्तर, प्रदूषण, अतिक्रमण और जैव-विविधता पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी। अर्ली वॉर्निंग सिस्टम और डेटा-आधारित नीतियां संरक्षण को मजबूती देंगी। हालांकि, केवल तकनीक काफी नहीं होगी। अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति, सख्त कानून और समाज की सक्रिय भागीदारी नहीं हुई, तो वेटलैंड्स धीरे-धीरे खत्म भी हो सकते हैं।

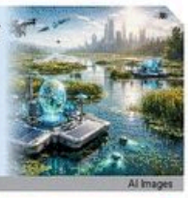

AI Images

ईरान से नहीं, वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा भारत: ट्रंप

■ पीटीआई, न्यू यॉर्क(अमेरिका)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने यह टिप्पणी शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान की। ट्रंप यह जवाब उस सवाल पर दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल सप्लाई के जरिए करेगा। उन्होंने कहा, चीन का स्वागत है, वह तेल पर अच्छा सौदा कर सकता है। हमने पहले ही एक डील कर ली है। भारत भी आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। यह सौदा पहले ही तय हो चुका है।

हालांकि, ट्रंप के इस बयान पर भारत की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरान से तेल का बड़ा खरीदार रहा था, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने के बाद इसमें भारी कटौती की गई थी।

ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उन्होंने ईरान से व्यापार पर भारी मैक्सिमम लगाए हैं और ईरान-अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। साल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई है, जिससे रूस उसके सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर कुल 50% प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं, जिनमें रूसी तेल की खरीद को लेकर 25% टैरिफ भी शामिल है।

ट्रंप के दावे पर भारत की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई

चीन का स्वागत है, वह तेल पर अच्छा सौदा कर सकता है। हमने पहले ही एक डील की है। भारत भी आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा – *ट्रंप, राष्ट्रपति, US*

'भारत ने क्या किया ये ट्रंप बताते हैं'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के भारत के वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले बयान के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार इसकी जानकारी देते आ रहे हैं कि भारत सरकार ने क्या किया है या आगे क्या करने जा रही है।

रमेश ने ट्रंप के इस बयान का ऑडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया। मुख्य विपक्षी दल के नेता ने लिखा, ट्रंप ने हमें बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया है। उन्होंने ही बाद में बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। और अब यह बयान आया है। रमेश ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप लगातार हमें यह जानकारी देते रहते हैं कि हमारी अपनी सरकार ने क्या किया है या क्या करने जा रही है।

SPEED News

US ने 7 साल बाद वेनेजुएला में राजदूत भेजा है।

राजदूत लौरा डोगु शनिवार को काराकास पहुंची। US का राजनयिक मिशन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की।

फ्रांस की टेक्नॉलजी कंपनी कैपजेमिनी

ने अमेरिकी सबसिडियरी को बेचने का फैसला लिया है। कंपनी इमीग्रेशन और कस्टम्स इंफोर्समेंट एजेंसी के साथ विवादों में थी।

रूस ने कहा कि यूक्रेन में कई मानकों

पर जीत पहले ही साफ दिख रही है। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने रविवार को ये बात कही।

टियर-2 और 3 शहरों पर बड़ा दांव

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए हाउसिंग और अर्बन डिवेलपमेंट मंत्रालय का बजट $5,522.39 करोड़ रुपये तय किया है। यह रकम पिछले साल के शुरुआती आवंटन के मुकाबले करीब 11,254 करोड़ रुपये कम है। इस तरह मंत्रालय के बजट में $.59% की कटौती की गई है। हालांकि बजट में कमी के बावजूद सरकार ने साफ किया है कि शहरी विकास की दिशा अब तेजी से टियर-2 और टियर-3 शहरों की ओर बढ़ेगी।

ईरान ने US को चेताया, हमले से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है

■ एपी, दुबई: ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने रविवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने हमला किया, तो इससे पश्चिम एशिया में एक 'क्षेत्रीय युद्ध' छिड़ सकता है और तनाव और अधिक बढ़ जाएगा। खामेनेई की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि ट्रंप वास्तव में बल प्रयोग का फैसला करेंगे या नहीं।

अमेरिका से तनाव के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई का यह बयान आया है

ईरान के सरकारी टेलीविजन ने खामेनेई के हवाले से कहा, 'अमेरिकियों को यह जान लेना चाहिए कि अगर वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा।' उनके इस बयान को अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। खामेनेई ने कहा, ईरान उकसाने की नीति नहीं अपनाता, लेकिन उन्होंने साफ किया कि ईरानी राष्ट्र पर अगर कोई हमला या उत्पीड़न किया गया, तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है।

'तनाव के बीच युद्धाभ्यास का ऐलान'

ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से अहम होर्मुज स्ट्रेट में सैन्य अभ्यास करने की योजना की भी घोषणा की है। ग्लोबल तेल व्यापार का लगभग पांचवा हिस्सा इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। कालिबाफ ने यह घोषणा संसद में उस वक्त की, जब वह और अन्य सांसद रिवोल्यूशनरी गार्ड ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को जवाबदेह है।

मुस्लिम दुकानदार के सपोर्ट में आए थे

उत्तराखंड: दीपक बोले, हंगामे ने अंदर से झकझोर दिया है

■ NBT रिपोर्ट, देहरादून

मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आए दीपक के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन और हंगामे ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया है। दीपक पौड़ी जिले के कोटद्वार में दुकानदार के समर्थन में आए थे। शनिवार शाम हरिद्वार और देहरादून से आए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दीपक के जिम का घेराव कर नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाने का दावा किया और देहरादून से आए कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया।

दीपक कुमार कश्यप, जो पेशे से जिम ट्रेनर हैं, 26 जनवरी को चर्चा में आए थे, जब उन्होंने कोटद्वार के पटेल रोड स्थित एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में आवाज उठाई थी। उस समय बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता 'बाबा' स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर' नाम की दुकान से 'बाबा' शब्द हटाने का दबाव बना रहे थे। इसके बाद से तनाव बना हुआ था, जो 31 जनवरी को बढ़ गया। वहीं, पौड़ी जिले के एसएसपी सर्वेश पंवार ने बताया कि माहौल बिगड़ने की कोशिश के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है।

दीपक कुमार कश्यप

प्रशासन पर भी सवाल उठाया

दीपक का आरोप है कि सैकड़ों कार्यकर्ता उनके जिम पहुंचे, गाली-गलौज की और उनके परिवार को भी अपशब्द कहे। उन्होंने प्रशासन पर एकतरफा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें एहतियातन थाने में बैठा दिया गया, जबकि प्रदर्शनकारियों को घंटों हंगामा करने दिया गया। दीपक ने कहा कि इसानियत के नाते बुजुर्ग दुकानदार का साथ देने की कीमत उन्हें मानसिक पीड़ा और परिवार की सुरक्षा की चिंता के रूप में चुकानी पड़ी। इस बीच, प्रदेश कांग्रेस ने दीपक को सुरक्षा देने और राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं।

दुकान के बोर्ड में 'बाबा' शब्द पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था

आम बजट में चुनावी राज्यों को जो मिला उससे खुश नहीं विपक्षी दलों की सरकारें

बंगाल सरकार ने कहा- बजट में हमारे राज्य के लिए कुछ भी नहीं है

Poonam.Pandey
@timesofindia.com

■ नई दिल्ली : चार राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के विधानसभा चुनाव से पहले आए केंद्रीय बजट में इन चुनावी राज्यों के लिए किए गए ऐलान से विपक्ष खुश नजर नहीं आ रहा है। जहां केरल सरकार ने बजट को लेकर निराशा जताई है, वहीं बंगाल सरकार ने यहां तक कह दिया कि केंद्रीय बजट में उनके राज्य के लिए कुछ भी नहीं है।

पुडुचेरी सहित तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। असम और पुडुचेरी में जहां बीजेपी सत्ता में है, वहीं केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए इंटर मोडल टानकुनी से वेस्ट में सूरत तक एक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया। उन्होंने पांच पूर्वोत्तर राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के विकास का प्रस्ताव रखा और 4000 ई-बसों के लिए प्रावधान करने की बात कही। सीतारमण ने दुर्गापुर में एक नोड बनाते हुए एकीकृत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास की भी घोषणा की।

वित्त मंत्री ने खनिज-समृद्ध राज्यों ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आम खनिज सुविधाएं स्थापित करने के लिए सपोर्ट देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2025 में रेयर-अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी। अब सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में मदद करेगी। वित्त मंत्री ने सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की भी घोषणा की।

केंद्रीय बजट निर्देशहीन और दृष्टिहीन है। इसमें आम आदमी और पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं है।

-ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल

बौद्ध सर्किट के विकास का प्रस्ताव

बजट में अगले 5 वर्षों में टियर-2 और 3 शहरों में बुनियादी ढांचे मजबूत करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की घोषणा की गई, इसमें असम भी शामिल है। वित्त मंत्री ने NIMHANS- 2 की स्थापना और राची और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करने की भी घोषणा की। उत्तर-पूर्व के छह राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा।

केरल को भी थी ज्यादा की उम्मीद

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को निर्देशहीन और दृष्टिहीन बताया। वहीं, आम बजट में राजिक को ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में कछुओं के प्रमुख अंडे देने वाले स्थलों पर टर्टल ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा की गई। साथ ही रेयर अर्थ कॉरिडोर के लिए भी केरल का नाम है। हालांकि, केरल को इससे ज्यादा की उम्मीद थी। केरल की सत्ताधारी पार्टी एलडीएफ ने और वहां के विपक्ष यूडीएफ ने बजट को लेकर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि केरल के लिए कम से कम दो बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी। एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और दूसरा एम्स को मंजूरी। लेकिन इन दोनों में से केरल को कुछ भी नहीं मिला। बजट स्पीच के बाद केरल के सांसदों ने सवाल उठाया- मैडम, केरल को एम्स का क्या?

बजट में हैं अवसरों की अपार संभावनाएं: PM

■ भाषा, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक बताते हुए रविवार को कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है।

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद टेलीविजन पर प्रसारित अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है। यह सुधारों की यात्रा को मजबूती देता है और विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। उन्होंने कहा कि सीतारमण ने लगातार नौवें बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

यह बजट भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत करेगा: अमित शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बजट भारत को वैश्विक मंच पर पारंपरिक से लेकर नये तौर के विभिन्न क्षेत्रों में सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने की रफ्तार को तेज करेगा। शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'विनिर्माण से लेकर बुनियादी ढांचे तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, खेल से लेकर तीर्थ स्थलों तक, विकसित भारत बजट एक ऐसा बजट है जो हर गांव, हर कस्बे और हर शहर के युवाओं, महिलाओं, किसानों के सपनों को सशक्त बनाता है।'

- मोदी ने कहा, यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है।
- खेले- भारत खबरों तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है, वह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहता है।

सरकार के पास कोई नीति नहीं: खरगे

■ भाषा, नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए रविवार को कहा कि इस सरकार के पास नीति, दृष्टि, समाधान और राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं है। उन्होंने यह दावा भी किया कि उचित वर्गों के लिए कोई सहायता नहीं दी गई। किसानों की भी उपेक्षा हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो लोगों को लोहे पर पीतल चढ़ाकर गहने पहनने पड़ेंगे।

15 पाक सैनिक, 92 विद्रोही मारे गए

■ पीटीआई, इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सेना ने रविवार को बताया कि अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के कई अभियानों में कम से कम 15 पाकिस्तानी सैनिक और 92 विद्रोही मारे गए हैं। सेना ने एक बयान में कहा कि ये अभियान शनिवार को जातीय बलूच समूहों के हमलों के बाद शुरू किए गए। बयान में कहा गया है कि सतर्क सुरक्षा बलों एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए विद्रोहियों की शांति भंग करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया। इस बीच, भारत ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में शांति भंग करने में उसकी भूमिका होने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया और इसे पाकिस्तान की 'आंतरिक विफलताओं' से ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने पाकिस्तान के दमन, बर्बरता और मानवाधिकार उल्लंघनों के रेकॉर्ड की ओर भी ध्यान दिलाया।

G RAM G योजना के लिए आम बजट में 95,692 करोड़ रुपये

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

मनरेगा की जगह लेने जा रही विकसित भारत-G RAM G योजना के लिए आम बजट में 95692.31 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं, MGNREGA के लिए 30000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। पिछले वित्त वर्ष में इसके लिए 86000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।

ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रूरल डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट का कुल बजट करीब 21% बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को जोड़कर देखें तो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब 4 लाख 35 हजार 779 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।

उन्होंने मनरेगा के बारे में कहा, 'पिछली बार ओवरऑल मनरेगा बजट लगभग 86,000 करोड़ रुपये था। इस बार अकेले केंद्र का हिस्सा 95692 करोड़ रुपये से ज्यादा रखा गया है। राज्यों के हिस्से को जोड़ने पर यह राशि 151000 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।' मनरेगा योजना विकसित भारत-G RAM G योजना के लागू होने तक चलती रहेगी और इसके लंबित कार्य पूरे किए जाएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए इसका रिवाइज्ड एस्टिमेट 88000 करोड़ रुपये का था।

SHE मार्ट: बजट में सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशन 'SHE-मार्ट' की व्यवस्था की गई है। हर जिले में महिलाओं के बनाए उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी-ओनर्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे। इससे स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पादों को नया बाजार मिलेगा।

पंचायतों को सहायता: 16वें वित्त आयोग के ताजा निर्णय के अनुसार पंचायतों को सीधे 55900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जाएगी।

इराक में राष्ट्रपति का चुनाव फिर टला

■ एएफपी, बगदाद: इराक की संसद ने देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव को फिर टाल दिया है। संसद के मीडिया ऑफिस ने कहा कि स्वीकार अब राजनीतिक दलों और सरकारों के नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की आखिरी तारीख तय करेंगे। यह दूसरी बार है जब संसद ने राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित किया है। इससे पहले यह मतदान पिछले हफ्ते होना था। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि प्रमुख राष्ट्रपति उम्मेदवार अल मलिकी को चुना गया तो अमेरिका इराक को मिलने वाली मदद बंद कर देगा।

सांप्रदायिक संतुलन अहम

■ इराक की सत्ता में परंपरागत रूप से प्रमुख पदों का बंटवारा सांप्रदायिक संतुलन के आधार पर होता है। आम तौर पर शक्तिशाली प्रधानमंत्री पद शिया मुस्लिम के पास होता है, संसद अध्यक्ष सुन्नी समुदाय से होता है, जबकि आमतौर पर राष्ट्रपति का औपचारिक पद कुर्द समुदाय को दिया जाता है।

संघ से जुड़े मजदूर संगठन ने कहा, यह बजट सबसे निराशाजनक

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने कहा कि यूनियन बजट 2026-27 सबसे निराशाजनक बजट है। प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बीएमएस ने कहा कि ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, औद्योगिक विकास और कैपेसिटी निर्माण के माध्यम से आर्थिक वृद्धि पर केंद्रित है लेकिन यह श्रमिकों की आजीविका, वेतन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज करता है। बीएमएस ने कहा कि यह बजट रोजगारोन्मुख, मजदूर पालन, एमएसएमई, पर्यटन, स्वास्थ्य, आयुष, पशुपालन और रचनात्मक जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना दिखाता है, लेकिन सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के बिना रोजगार को समावेशी विकास नहीं कहा जा सकता।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMJK2 User: cci Time: 02-01-2026 22:36 Color:

वर्कफोर्स में Gen Z

देश मे वर्कफोर्स का करीब 25% हिस्सा Gen Z का, साल 2030 तक 36% होने का अनुमान।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

UNION BUDGET 2026-27

38 करोड़ है आबादी

1997-2012 के बीच जन्म लेने वालो को Gen Z कहा जाता है। आबादी करीब 38 करोड़ है।

सवाल-जवाब से जानें, क्या-क्या बदल जाएगा

सीए अनिल जैन, इनकम टैक्स एक्सपर्ट

टैक्स स्लैब मे भले ही राहत न दी गई हो लेकिन वित्त मंत्री ने बजट मे कई ऐसे प्रस्ताव रखे हैं जिनसे आम आदमी को आसानी होगी और उसका फायदा होगा।

AI Image

रिटर्न फाइल करने के प्रॉसेस को कैसे आसान बनाया?

सरकार ने टैक्स रिटर्न प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई प्रस्ताव दिए है। रिवाइज्ड रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव है। अतिरिक्त तीन महीनों का लाभ लेने पर फीस देनी होगी- पांच लाख से अधिक आय पर 5,000 रुपये और पांच लाख या उससे कम आय पर 1,000 रुपये। नॉन-ऑडिट केस, जैसे छोटे बिजनेस और ट्रस्ट के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त की गई है, जबकि सैलरीड वर्ग के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-2 की तारीख 31 जुलाई ही रहेगी।

विदेश टूर पैकेज पर टैक्स कितना कम?

विदेशी यात्रा के टूर पैकेज पर TCS (Tax Collected at Source) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों पर खर्चा कम होगा। पहले विदेशी टूर पैकेज पर 10 लाख रुपये तक 5% TCS और 10 लाख से अधिक पर 20% TCS लगता था। अब सरकार ने इसे सिर्फ 2% TCS कर दिया है, चाहे पैकेज की कीमत कितनी भी हो। 10 लाख रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट भी हटा दी गई है। यानी अब सभी विदेशी टूर पैकेज पर केवल 2% TCS ही लागू होगा। जमा किया गया TCS रिफंडेबल है और आईटीआर फाइल करते समय रिफंड लिया जा सकता है।

विदेश पैसा भेजने पर कितना टैक्स लगेगा?

पढ़ाई या इलाज के लिए विदेश पैसा भेजने पर अब कम टैक्स लगेगा। अभी जब कोई व्यक्ति पढ़ाई या इलाज के लिए फॉरेन रेमिटेंस करता था तो उस पर 5% टीसीएस लगता था। शिक्षा और मेडिकल के अलावा किसी और काम के लिए पैसा भेजने पर 20% टीसीएस अप्लाई होता है। सरकार ने शिक्षा और मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए टीसीएस रेट को 2% करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा किसी और मकसद के लिए टीसीएस 20% ही रहेगा। अगर पैसा एजुकेशन के लिए लोन के जरिए भेजा जा रहा है तो इस पर टीसीएस रेट अब भी 0.5% ही रहेगा जैसा पहले था।

फॉरेन असेट घोषित करने के लिए क्या स्कीम आई है?

सरकार ने टैक्सपेयर्स के फायदे के लिए फॉरेन असेट्स ऑफ स्मॉल टैक्सपेयर्स डिक्लेयरेंस स्कीम 2026 पेश की है। इसका उद्देश्य उन ईमानदार टैक्सपेयर्स को मौका देना है जिनके पास सीमित मूल्य की विदेश संपत्ति या आय है और जो रिपोर्टिंग में चूक गए। इस स्कीम में 31 मार्च 2026 को एक करोड़ रुपये तक की वैल्यू वाली फॉरेन असेट या इनकम शामिल होगी। अगर असेट का स्रोत साफ है लेकिन रिपोर्ट मिस हुई है, तो लिमिट पांच करोड़ रुपये तक होगी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम घोषित करने पर 30% टैक्स और 30% अतिरिक्त देना होगा, यानी कुल 60%।

ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा पर क्या नियम बदले?

सरकार ने ऑडिट रिपोर्ट देर से जमा करने पर लगने वाले जुर्माने के नियमों में बदलाव किया है। पहले अधिकतम पेनल्टी 1,50,000 रुपये तक थी, जिसे अब घटाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है। नए प्रावधान के अनुसार, यदि ऑडिट रिपोर्ट देरी से लेकिन एक महीने के भीतर जमा कर दी जाती है, तो 75,000 रुपये शुल्क देना होगा। एक महीने के बाद जमा करने पर 1,50,000 रुपये का शुल्क लागू रहेगा। इस राशि को अब 'पेनल्टी' की जगह 'फीस' माना जाएगा, जिससे कारोबारी इसे खर्च के रूप में दिखाकर टैक्स में कटौती का लाभ ले सकेंगे।

कोऑपरेटिव सोसायटी, मेंबर्स के लिए क्या फायदा?

सहकारी समितियां भी कंपनियों या अन्य सहकारी समितियों में निवेश कर डिविडेंड प्राप्त करती हैं। मौजूदा नियमों में कंपनी से मिला डिविडेंड संबंधित सहकारी समिति के हाथ में टैक्सेबल माना जाता है, जबकि दूसरी सहकारी समिति से मिला डिविडेंड विशेष कटौती के लिए पात्र होता है। अब तक यह कटौती केवल ओल्ड टैक्स रेजीम चुनने वाली समितियों को मिलती थी। प्रस्ताव है कि यह लाभ न्यू टैक्स रेजीम में भी मिलेगा, बशर्ते प्राप्त डिविडेंड आगे सदस्यों में वितरित किया जाए। यह बदलाव समितियों और उनके सदस्यों, दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

टीडीएस को लेकर कौन से बदलाव हुए हैं?

इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 के तहत कम या निल टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए अब प्रक्रिया आसान होगी। पहले टैक्सपेयर को असेसिंग अफसर के पास आवेदन देना पड़ता था, जो संतुष्टि पर सर्टिफिकेट जारी करता था। अब आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा और प्राधिकरण डिजिटल जांच कर निर्णय लेगा। पात्रता और प्राधिकरण को सीबीडीटी नोटिफाई करेगी। यह बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। म्यूचुअल फ्रॉपंडों खरीद में भी राहत है। नॉन-रेजिडेंट विक्रेता के मामलों में टीडीएस के लिए TAN की अनिवार्यता हटेगी। अब खरीदार केवल PAN के आधार पर टीडीएस काट सकेगा।

कारोबार आसान बनाने और मुकदमेबाज़ी कम करने पर वित्त मंत्री का फोकस

इनकम टैक्स स्लैब जस का तस, नया ऐक्ट 1 अप्रैल से ही, नियम-फॉर्म जल्द

एक्सपर्ट व्यू

सीए सुशील अग्रवाल, इनकम टैक्स एक्सपर्ट

नए इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 का उद्देश्य नियम सरल बनाना है। आयकर स्लैब वही रहेंगे, कोई नई छूट नहीं। कानून में सुधार, पेनल्टी सरल, शेयर और TCS नियम बदलकर कारोबार आसान बनाने की कोशिश की गई है।

नया इनकम टैक्स ऐक्ट 2025 एक अप्रैल से लागू होगा। अभी यह ऐक्ट पार्लियामेंट से पास हो चुका है और नोटिफाई भी हो चुका है, लेकिन कोई भी ऐक्ट तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक उससे जुड़े रूल्स-रेग्युलेशन और फॉर्म्स को भी जारी किया नहीं जाता। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया है कि यह रूल्स और फॉर्म्स जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे और नए ऐक्ट के लागू होने की तिथि को नहीं बढ़ाया जाएगा। नहीं तक इसके लागू होने से पड़ने वाले फर्क की बात करें तो इससे इनकम टैक्स के प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं आएगा।

नए ऐक्ट में सभी प्रावधानों को सलीके से पेश किया गया है। पहले यह कई सेक्शनों में अलग-अलग बिखरे हुए थे, अब एक बात को पूरी तरह से एक जगह पर ही कर दिया गया है। इससे सेक्शन कम हो गए। इसके अलावा भाषा को भी सरल किया गया है। ऐसा अनुमान है कि रूल्स और फॉर्म्स को भी आसान रखा जाएगा ताकि मुकदमेबाजी ना हो।

इस बार के बजट में सामान्य व्यक्ति (साधारण करदाता) को टैक्स छूट के रूप में कोई नई राहत नहीं दी गई है। आयकर के जो स्लैब पिछले वर्ष तक लागू थे, वही आगामी वर्ष में भी लागू रहेंगे। वास्तव में, किसी को अतिरिक्त छूट की विशेष उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि पिछले वर्ष ही नए टैक्स रेजीम में 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी राहत थी। इसलिए इस वर्ष किसी और बड़ी राहत की अपेक्षा करना उचित नहीं माना जा सकता।

हालांकि, कई सुझाव और प्रयास किए जा रहे थे, जैसे- नए टैक्स रेजीम में हाउसिंग लोन के ब्याज पर छूट दी जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि बढ़ाई जाए, शेयरों पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाए, पति और पत्नी की जॉइंट इनकम पर टैक्स लगाने से संबंधित प्रावधान लाए जाएं आदि। लेकिन इस बार के बजट में इनमें से कोई भी प्रावधान शामिल नहीं किया गया।

इस बजट का मुख्य उद्देश्य कोर्ट-कचहरी के मामलों को कम करना और कारोबार करना आसान बनाना है। सरकार कई नियमों को सरल बना रही है। छोटे-मोटे अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माना बनाया जाएगा। कुछ पेनल्टी अब फीस की तरह ली जाएंगी। शेयर बाय-बैक के नियम बदले जाएंगे। TCS नियमों में राहत दी गई है, जबकि शेयर बाजार लेनदेन पर STT थोड़ा बढ़ाया गया है। इससे बिजनेस माहौल बेहतर करने की कोशिश है।

वहीं, बजट 2026 में क्रिप्टो एसेट लेनदेन की गलत या अधूरी रिपोर्टिंग पर सख्ती का प्रस्ताव है। एक्सचेंज, मार्केटप्लेस जैसे संस्थानों को तय विवरण देना होगा। स्टेटमेंट न देने पर 200 प्रतिदिन जुर्माना लगेगा। गलत जानकारी देने और सुधार न करने पर 50,000 की पेनल्टी प्रस्तावित है। इसका मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और गैर-अनुपालन रोकना है।

AI Image

इस तरह होगी टैक्स की गणना

मौजूदा समय में इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए ओल्ड और न्यू दो टैक्स रेजीम हैं। इनके स्लैब जस के तस रखे गए हैं। आप जिस भी रेजीम को फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से टैक्स की गणना अब भी पहले की तरह ही होती रहेगा। यहां पेश है दोनों रेजीम के टैक्स स्लैब।

न्यू टैक्स रेजीम

नया टैक्स स्लैब	टैक्स रेट
0-4 लाख रुपये	Nil
4-8 लाख रुपये*	5%
8-12 लाख रुपये*	10%
12-16 लाख रुपये	15%
16-20 लाख रुपये	20%
20-24 लाख रुपये	25%
24 लाख रुपये उपर	30%

*नोट: *न्यू टैक्स रेजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है।*

ओल्ड टैक्स रेजीम

टैक्स स्लैब	टैक्स रेट
2.5 लाख तक	Nil
2.5 से 5 लाख तक	5%
5 से 10 लाख तक	20%
10 लाख से अधिक	30%

4 टैक्स स्लैब, 30% तक टैक्स

SITUATIONSHIP सिचुएशनशिप

न कमिटमेंट और ना दूरी

सिचुएशनशिप (Situationship) असल में एक अनौपचारिक रिश्ता होता है, ना पूरी तरह कमिटमेंट, ना पूरी तरह दूरी। यानी साथ भी है, लेकिन साफ नहीं कि किस हैसियत से। रिश्तों के संदर्भ में:

- बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड जैसा व्यवहार, लेकिन कोई स्पष्ट स्टेटस नहीं
- भविष्य को लेकर अनिश्चितता, सुविधा है, पर जिम्मेदारी नहीं।
- फायदे हैं, लेकिन वादे नहीं।

Gen-Z की भाषा

इकॉनमी का 'बीच का खेल'

इकॉनमी में यह शब्द रूपक (metaphor) की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रोथ और मंदी के बीच की हालत यानी जब इकॉनमी मंदी में भी नहीं, तेज विकास में भी नहीं तो कहा जा सकता है: Economy is in a situationship with growth। इसका अर्थ संभावनाएं है, पर भरोसा नहीं। इकॉनमी में situationship का मतलब है ऐसी स्थिति जहां उम्मीद, अनिश्चितता साथ-साथ चल रही हो।

BENCHING बेंचिंग

खेल नहीं, रिश्तों की नई भाषा

बेंचिंग शब्द भी आजकल रिश्तों से लेकर इकॉनमी तक एक तेज और अर्थपूर्ण रूपक बन चुका है। चलिए इसे उसी अंदाज में समझते हैं।

किसी को पूरी तरह छोड़ा नहीं, लेकिन प्राथमिकता भी नहीं। यानी Backup option बनाकर रखना

- ना साथ, ना विदाई = Emotional benching

वैसे Benching की जड़ खेल (क्रिकेट/फुटबॉल) से है। खिलाड़ी टीम में है, मैदान पर नहीं और जरूरत पड़ने पर उतारा जा सकता है। यानी रिजर्व में रखना।

सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड पर क्या बदला?

सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) पर कैपिटल गेन टैक्स छूट के नियम स्पष्ट और सीमित करने का फैसला किया है। आरबीआई द्वारा जारी इन बॉण्ड्स पर पहले मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर रिडेम्पशन गेन टैक्स फ्री रहता था। अब स्पष्ट किया गया है कि यह छूट केवल उन्हीं निवेशकों को मिलेगी जिन्होंने SGB को मूल इश्यू के समय सब्सक्राइब किया और मैच्योरिटी तक होल्ड किया। सेकंडरी मार्केट से खरीदे गए SGB पर मैच्योरिटी के समय यह टैक्स छूट उपलब्ध नहीं होगी। इससे नियमों में स्पष्टता आएगी।

Skill है, Demand नहीं

मिसाल के तौर पर स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध है लेकिन demand कमजोर है या टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन चल रहा है। यानी Talent है, लेकिन उपयोग नहीं = Benched economy

- इसी तरह कंपनियों के पास पैसा है, बैलेंस शीट मजबूत है, लेकिन निवेश टाल रही है
- यानी पैसा मैदान में नहीं उतर रहा= Capital on the bench
- वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई चेंज ना करके यह संदेश देने की कोशिश की है कि ये बदलाव इस साल उनकी प्राथमिकता में नहीं थे।

राहत आयकर कानून में बड़ा सुधार, टैक्सपेयर्स की आसानी मकसद

सज़ा की अवधि में कटौती, कई मामले अपराध की कैटिगरी से बाहर

एक्सपर्ट व्यू

सीए लक्ष्य शर्मा, इनकम टैक्स एक्सपर्ट

■ सरकार ने आयकर कानून के तहत दंड प्रावधानों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। पहले जहां कुछ मामलों में सात साल तक की कैद का प्रावधान था, उसे अब घटाकर अधिकतम दो साल कर दिया गया है। नए नियमों के अनुसार, अगर टैक्स की राशि 10 लाख रुपये तक है तो किसी प्रकार की कैद नहीं होगी। वहीं 10 लाख से 50 लाख रुपये तक के मामलों में अधिकतम छह महीने की सजा का प्रावधान रखा गया है और इससे अधिक राशि पर दो साल तक की कैद हो सकती है।

इसके अलावा टीडीएस का भुगतान न करने पर भी अब अधिकतम सजा दो साल तक सीमित कर दी गई है। सरकार ने कुछ अपराधों को पूरी तरह से क्रिमिनलाइज मी कर दिया है, जैसे ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स से होने वाली जीत पर टीडीएस काटना मूल जोड़ने पर पहले सात साल तक की सजा थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। यह कदम कर व्यवस्था को सरल और व्यावसायिक अनुकूल बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

AI Image

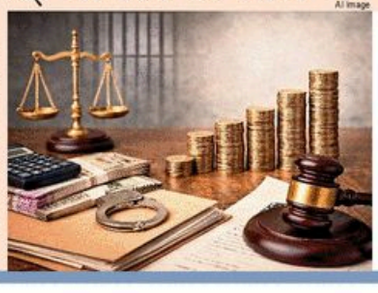

ईपीएफ से जुड़े मामलों में मुकदमेबाज़ी पर क्या असर होगा?

कर्मचारियों से काटा गया ईपीएफ एम्प्लॉयर को ईपीएफ खाते में जमा करना होता है। अगर उह समय पर जमा नहीं करता तो उह इनकम में जोड़ना पड़ता है। जमा करने की ड्यू डेट ईपीएफ के प्रावधानों से ली जाती थी। अगर जमा करने में एक दिन की भी देरी होती थी तो टैक्स देना पड़ता था। इनकम टैक्स के दूसरे प्रावधानों में किसी भी सरकारी ड्यू को रिटर्न भरने की डेट से पहले जमा कर देने पर उसे इनकम में नहीं जोड़ा जाता था। इस विषय को लेकर काफी मुकदमेबाजी होती थी। अब यह फैसला लिया गया है कि ड्यू डेट रिटर्न भरने की डेट मानी जाएगी। इससे मुकदमेबाजी खत्म होगी।

एक्सिडेंट क्लेम मुआवज़े पर ब्याज भी टैक्स फ्री

बजट में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) से जुड़े पीड़ितों को इनकम टैक्स में राहत दी गई है। ट्रिब्यूनल के अवॉर्ड से मिलने वाली मूल मुआवजा राशि पहले से ही टैक्स फ्री थी, लेकिन जब राशि देर से मिलती थी और उस पर कुछ ब्याज मिलता था तो उस ब्याज को अन्य स्रोतों से आय मानकर टैक्स लगाया जाता था। उस ब्याज पर टीडीएस भी काटा जाता था। नए प्रावधान के तहत सरकार ने इस ब्याज को पूरी तरह आयकर से मुक्त कर दिया है। इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा। MACT द्वारा दिए गए मुआवजे के ब्याज पर टीडीएस लागू हो या नहीं? यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावे में 50,000 से अधिक मुआवजे के ब्याज पर टीडीएस लागू करने के मामले में केंद्र सरकार से विचार मांगे थे।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMJK3 User: cci Time: 02-01-2026 23:21 Color:

फिल्म की कमाई...

Gen Z के दौर की पहली सुपरहिट बॉलिवुड फिल्म सैयारा की कमाई करीब 500 करोड़ रुपये।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

UNION BUDGET 2026-27

860 बिलियन डॉलर

2025 में देश में वस्तुओं के कंजम्पशन में Gen Z का हिस्सा 860 बिलियन डॉलर।

हम चुप नहीं रह सकते

बढ़ोतरी सट्टेबाजी को कम करने और लोगों को दूर रखने के लिए की गई है। हम F&O ट्रेड के खिलाफ नहीं है। छोटे निवेशकों को नुकसान हो रहा है, तो हम चुप कैसे रह सकते हैं? –सीतारमण, वित्त मंत्री

फ्यूचर्स एक रिस्क मैनेज करने वाला प्रोडक्ट है, यह सट्टेबाजी का मुख्य जरिया नहीं है। ऐसे में टैक्स बढ़ाने से सट्टा रुकेगा या सिर्फ बाजार में लोगों की भागीदारी कम हो जाएगी, यह बड़ा सवाल है।
–प्रणव हरिदासन, एक्सिस सिक्योरिटीज, CEO

STT में इजाफा!

कितना इजाफा

F&O सेगमेंट में सट्टेबाजी को कम करने के लिए STT (टैक्स) में भारी इजाफा।

फ्यूचर्स STT:	ऑप्शंस STT:	बायबैक पर टैक्स:
0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया (150% की वृद्धि)।	0.1% / 0.125% से बढ़ाकर 0.15% किया गया (करीब 50% की वृद्धि)।	अब बायबैक से होने वाले मुनाफे को 'कैपिटल गेन्स' माना जाएगा।

असर: F&O में ट्रेड करना पहले से महंगा होगा।

शेयर बाजार पर असर

सेंसेक्स की गिरावट

1.88% 1,546.84 अंक

निफ्टी की गिरावट

1.96% 495.20 अंक

₹11 लाख करोड़ करीब मार्केट कैप लॉस

■ 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से अब तक कुल 15 बार बजट पेश किया जा चुका है। 15 बजट वाले दिनों में से 8 बार सेंसेक्स गिरावट के साथ बंद हुआ है।

फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव

F&O पर लगने वाला टैक्स दोगुना से भी ज्यादा, सेंसेक्स में भारी गिरावट

एक्सपर्ट व्यू

सीएम निखिल गुप्ता, टैक्स एक्सपर्ट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को डेरिवेटिव्स (F&O) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस कदम का मकसद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सेगमेंट में होने वाली हद से ज्यादा सट्टेबाजी पर लगाम लगाना है।

■ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा डेरिवेटिव्स (F&O) पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने के प्रस्ताव के बाद रविवार को शेयर बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2 प्रतिशत की भारी गिरावट आई। शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए सेंसेक्स दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक (2.88%) तक टूट गया। वित्त मंत्री द्वारा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने के ऐलान के बाद सेंसेक्स 80,000 के स्तर से नीचे गिरकर 79,899.42 पर आ गया। बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 1,546.84 अंक (1.88%) की गिरावट के साथ 80,722.94 पर रहा।

अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर STT को 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत किया जाएगा। उन्होंने कहा, ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस एक्सरसाइज पर लगने वाले टैक्स को भी मौजूदा 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, सीतारमण ने घोषणा की कि अब सभी तरह के शेयरधारकों के लिए 'शेयर बायबैक' से मिलने वाले पैसे पर 'कैपिटल गेन्स' के तौर पर टैक्स लगेगा।

शेयर बाजारों में रविवार को 'बनट डे' का विशेष ट्रेडिंग सेशन रखा गया था। इस घोषणा के बाद शेयर बाजार बुरी तरह हिल गया। सेंसेक्स 1,546.84 अंक (1.88%) की गिरावट के साथ 80,722.94 पर आ गया। वहीं, निफ्टी 495.20 अंक (1.96%) गिरकर 24,825.45 पर बंद हुआ।

रिटेल निवेशकों के लिए कदम: FM

■ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि F&O पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) बढ़ाने का मकसद नेग्निम मरी सट्टेबाजी को रोकना है। उन्होंने कहा कि सरकार उन भोले-भाले निवेशकों को बचाना चाहती है, जो डेरिवेटिव मार्केट (F&O) में भारी पैसा गंवा रहे हैं। बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार डेरिवेटिव कारोबार के खिलाफ नहीं है। लेकिन वह चाहती है कि बढ़ा घाटा उठाने वाले छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले F&O बाजार से दूर रहें। सीतारमण ने कहा, टैक्स में यह मामूली बढ़ोतरी सिर्फ सट्टेबाजी को कम करने और लोगों को इससे दूर रखने के लिए की गई है।

■ **निवेशकों की सुरक्षा:** सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज्यादा रिटेल निवेशकों को F&O में घाटा होता है, सरकार उन्हें इससे बचाना चाहती है।

■ **कैश मार्केट पर नहीं:** टैक्स यह की बढ़त केवल F&O पर है। सीधे शेयर खरीदने-बेचने (कैश मार्केट) पर इसका कोई असर नहीं होगा।

बढ़ोतरी से ब्रोकरेज कंपनियों की बढ़ी टेंशन

■ बाजार के दिग्गजों ने चेतावनी दी है कि STT बढ़ाने का कदम उल्टा पड़ सकता है। इससे बाजार में नकदी की कमी हो सकती है और विदेशी निवेशक भारत छोड़कर एशिया के दूसरे बाजारों की तरफ भाग सकते हैं।

जानकारों का कहना है कि जब डेरिवेटिव्स (F&O) पर टैक्स बढ़ता है, तो वहां ट्रेडिंग कम हो जाती है। इसका सीधा असर कैश मार्केट (शेयरों की खरीद-बिक्री) पर भी पड़ता है। जब बाजार में पैसा कम घूमता है, तो विदेशी निवेशक (FIIs) ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और अपना पैसा दूसरे देशों में ले जाते हैं।

SAMCO ग्रुप के फाउंडर और सीईओ निमेश मेहता ने कहा कि जब भारत को विदेशी पैसा चाहिए, तब ट्रेडिंग की लागत बढ़ाना गलत संदेश देता है। डेरिवेटिव मार्केट सिर्फ सट्टा लगाने की जगह नहीं है, यह बाजार का इंजन है जो कीमतों को सही रखने में मदद करता है।

ब्रोकरेज शेयरों में हड़कंप: टैक्स बढ़ने की खबर से ब्रोकरेज और एक्सचेंज कंपनियों (BSE, Angel One) के शेयर 9% तक टूट गए।

लिक्विडिटी का संकट: टैक्स बढ़ने से बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम घटेगा, जिससे नकदी की कमी हो सकती है।

बदलाव का प्रस्ताव

शेयर बायबैक पर 'कैपिटल गेन्स' टैक्स

■ **छोटे निवेशकों** के हितों की रक्षा करने और प्रमोटर्स द्वारा टैक्स बचाने के खेल (टैक्स आर्बिट्रेज) को रोकने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को शेयर बायबैक के टैक्स नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा है। बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि अब सभी तरह के शेयरधारकों के लिए बायबैक से होने वाली कमाई पर 'कैपिटल गेन्स' के तौर पर टैक्स लगेगा। टैक्स चोरी या हेराफेरी को रोकने के लिए प्रमोटर्स पर अलग से 'बायबैक टैक्स' लगाने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद कॉरपोरेट प्रमोटर्स (कंपनियों) के लिए प्रभावी टैक्स दर बढ़कर 22 प्रतिशत और नॉन-कॉरपोरेट प्रमोटर्स के लिए 30 प्रतिशत हो जाएगी। सीतारमण ने कहा, बायबैक टैक्स के नियमों में यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि प्रमोटर्स बायबैक के रास्ते का गलत इस्तेमाल न कर सकें। जानकारों का कहना है कि जब कोई कंपनी अपने ही शेयर शेयरधारकों से वापस खरीदती है, इसे Buy Back of Shares कहते हैं।

(प्रस्तुति : सान्या मिश्रा)

अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर रहेगी नजर

शेयर मार्केट में अब कहां से बनेगा पैसा?

■ मृत्युंजय राय

नई दिल्ली : पिछले डेढ़ साल से भारतीय शेयर बाजार विदेशी निवेशकों की बिकवाली की वजह से दबाव में है। जब तक कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिलता, तब तक इसकी वही हालत रहेगी। बजट में अगर विदेशी निवेशकों के लिए खास ऐलान किए गए होते तो वह एक ट्रिगर का काम कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नया ट्रिगर अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के ऐलान की शक्ल में आ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका संकेत कई बार दे चुके हैं, लेकिन बीच-बीच में कई नकारात्मक बातें भी उनकी सरकार की ओर से होती रही हैं, जिससे इस समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

मार्केट के लिए बजट में सबसे बड़ा नेगेटिव फ्यूचर्स ऐंड ऑप्शंस पर STT में 150% की बढ़ोतरी है। इससे हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में कमी आएगी, जिसका बाजार के वॉल्यूम पर बुरा असर पड़ेगा। छोटे निवेशकों के लिए राहत की एक खबर बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगने का ऐलान है, लेकिन उसमें भी इंडिविजुल प्रमोटर्स और प्रमोटर एंटिटी के लिए टैक्स दरें अलग रखी गई हैं। इससे कंपनियों के प्रमोटरों में निराशा है।

बाजार के लिए अच्छी बात मजबूत मैक्रो-इकॉनमी है। वित्त वर्ष 2027 में सरकार ने ग्रोथ के 7% रहने का अनुमान लगाया है। फिस्कल डेफिसिट में कमी का वादा भी उन्होंने पूरा किया है। साथ ही, सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में इसे GDP के 4.3% तक रखने की बात कही है। हालांकि, रुपये की हालत कमजोर बनी हुई है। भारतीय इकॉनमी की एक बड़ी दिक्कत काफी समय से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी रही है। इसलिए ग्रोथ की जिम्मेदारी सरकारी खर्च बढ़ाकर ही की जा सकती थी। सरकार ने बजट में इसका ख्याल रखा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की रकम को करीब 10% बढ़ाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस पर अमल होगा? इस पर संदेह बना हुआ है। भारतीय इकॉनमी की ताकत कंसम्पशन है, लेकिन इसकी ग्रोथ बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बनने से जुड़ी है। कंजम्पशन में बढ़ोतरी हो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी इनाफा होगा। इधर, मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए कई सेक्टर्स में परफॉर्मेंस लिंक्ड इनीशिएटिव जैसी योजनाओं पर सरकार का जोर रहा है, जिसे इस बजट में भी बढ़ाया गया है। कई देशों से व्यापार समझौते से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मजबूती के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

150% *की बढ़ोतरी है मार्केट के लिए बजट में सबसे बड़ा नेगेटिव फ्यूचर्स ऐंड ऑप्शंस पर STT में*

DELULU IS THE SOLULU ख़याली दुनिया

हकीकत नहीं, तो कल्पना सहारा

■ Delulu = Delusional (ख़याली दुनिया) और Solulu = Solution (हल)। मतलब अगर हकीकत मदद नहीं कर रही, तो कल्पना सहारा है।

यह जुमला कहता है:
- खुद पर अति-विश्वास
- पॉजिटिव भ्रम
- Manifest कर लो, हो जाएगा

Reality से भागना नहीं, Reality को ignore करके motivate होना।

Gen-Z की भाषा

हर हाल में भरोसा बनाए रखना

उम्मीद के सहारे भरोसा बनाए रखना = Delulu-driven confidence.

■ कई बार सेटिमेंट चलता है, डेटा बाद में आता है।

■ सुधारों के नतीजे समय लेते हैं, जनता को धैर्य चाहिए। यानी Optimism sell किया जाता है = Narrative management

लेकिन यह तब खतरनाक हो जाता है जब जब: ■ Delulu, data को replace कर दे

■ Narrative, reality से कट जाए तब Solulu illusion बन जाता है

GHOSTING गोस्टिंग

न संकेत, न उम्मीद, बस सन्नाटा

यह इस सीरीज का सबसे सबसे सख्त और सबसे खामोश शब्द है–जहां न संकेत, न उम्मीद, बस सन्नाटा।

■ Ghosting = भूत बन जाना
- अचानक जवाब बंद
- कॉल, मैसेज, सब गायब
- यानी ना हां, ना ना – सीधा अदृश्य

डिमांड गायब हो जाए

उपभोक्ता और बाजार के संदर्भ में अगर अचानक डिमांड गायब हो जाए, सेटिमेंट पलट जाए और फुटफॉल सूख जाए तो यह किसी कंपनी के लिए कंस्यूमर घोस्टिंग वाले हालात हो जाएंगे।

■ इसी तरह सरकार और योजनाएं के संदर्भ में देखें तो अगर योजना की घोषणा हो और शुरुआती चर्चा के बाद फिर जिक्र तक नहीं हो तो लगेगा कि योजना तो सिर्फ कागजों पर ही मौजूद है, इसे पॉलिसी घोस्टिंग कहेंगे।

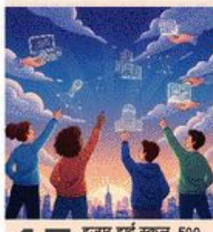

ऑरेंज इकॉनमी | इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नॉलजी (मुंबई) करेगा मदद

20 लाख जॉब का टारगेट

Bhupender.Sharma@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली:** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक लगभग 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नॉलजी (मुंबई) देश में 15 हजार हाई स्कूल और 500 कॉलेजों में एडवांस्ड कंटेंट क्रिएटर लैब (सीसीएल) स्थापित करने में सहयोग करने में मदद करेगा।

इस प्रोजेक्ट का मकसद AVGC सेक्टर के लिए दो मिलियन प्रफेशनल्स तैयार करना है।

बजट 2026 में वित्त मंत्री के बजट भाषण से यह स्पष्ट है कि 'ऑरेंज इकोनॉमी' को भारत की नई आर्थिक शक्ति के रूप में पहचान दी है।

15 हजार हाई स्कूल, 500 कॉलेजों में सीसीएल स्थापित करने में मदद

जहाज खरीदने पर छूट की अवधि में इजाफा

■ भारतीयों को जहाज खरीदने और उनका रजिस्ट्रेशन भारत में ही कराने के लिए, सीतारमण ने फिस्ट सिटी (IFSC) की इकाइयों के लिए टैक्स छूट की अवधि 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है। इसके बाद इन पर 15 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

सेमीकंडक्टर में ऊंची छलांग | **दक्षिण भारत में बनेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर**

40 हजार करोड़ का बूस्टर और सेमीकंडक्टर मिशन से बदलेगी देश की सूरत

Alpyu.Singh@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** भारत सेमीकंडक्टर के सेक्टर में दुनिया के चार टॉप देशों में आने के लिए कई कोशिशें कर रहा है। इस बजट में सरकार का ये रोडमैप दिखता है। रविवार को वित्तमंत्री ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 (ISM) के लॉन्च की घोषणा की है। 2021 में लॉन्च की गई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को भी बड़ा प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई। अपने संबोधन में वित्तमंत्री ने कहा कि ISM 1.0 की कामयाबी के आधार पर ही ISM 2.0 शुरू किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में दो बड़े ऐलान हुए हैं जो इंडिया स्टैक और IP से जुड़े मसलों को बेहतर बनाएंगे।

दक्षिणी राज्यों पर फोकस

इलेक्ट्रॉनिक्स और **रिन्यूएबल एनर्जी** में इस्तेमाल होने वाले रेयर अर्थ के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार ने बजट में अहम कदम बढ़ाया है। सरकार ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिजों से भरपूर राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी। इसमें खनन, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग का काम शामिल होगा।

आईटी सर्विसेज, टैक्स हॉलिडे

■ बजट में IT इंडस्ट्री के लिए वित्तमंत्री सीतारमण ने उन कंपनियों के लिए साल 2047 तक टैक्स हॉलिडे का प्रस्ताव रखा है, जो क्लॉउड सेवाएं देती हैं। सरकार का मानना है कि लंबी अवधि में टैक्स में राहत देने से निवेश में मदद मिलेगी।

AI से बड़े बदलाव की तैयारी

Hemwati.Rajaura1@timesofindia.com

■ **नई दिल्ली :** बजट में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए AI मिशन और नैशनल क्वांटम मिशन का जिक्र किया गया। सरकार ने इसके लिए साझा कंप्यूटर प्लैटफॉर्म तैयार किया है। इसके तहत महंगे जीपीयू (कंप्यूटर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) लोगों को सिर्फ 65 प्रति घंटे में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बजट में भाश-विस्तार नामक मल्टीलिंग्वल एआई टूल का जिक्र किया गया। इसका मकसद है कि एआई सेवाओं का फायदा हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में आम लोगों तक पहुंचे। एआई को एग्री स्टैक पोर्टल और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के कृषि फैक्ट से जोड़ा जाएगा। एआई से इसके जोड़ने पर किसानों को सरकारी सलाह, मौसम, मिट्टी और फसल की सही जानकारी कस्टमाइज तरीके से मिल सकेगी, पैदावार बढ़ेगी और खेती और स्मार्ट बनेगी। एआई आधारित डिजाइन और श्री टी तकनीकें दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण को ज्यादा सटीक, आरामदायक और व्यक्तिगत बनाएंगी।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMJK4 User: cci Time: 02-01-2026 23:01 Color:

Gen Z का फैशन

फैशन कैटिगरी में Gen Z का आधा कंजम्पशन, 65% Gen Z खरीदारी ऑनलाइन कर रहे है।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

UNION BUDGET 2026-27

Gen Z निवेशक

शेयर बाजार में 39% Gen Z निवेशक, नए निवेशको में 56% Gen Z इनवेस्टर।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

हेल्थ बजट पहली बार एक लाख करोड़ के पार, सस्ते इलाज पर ज़ोर

बायोफार्मा शक्ति से बूस्ट होगी सेहत

Hemwati.Rajaura1
@timesofindia.com

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने हेल्थ सेक्टर का बजट पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 1,06,530.42 करोड़ रुपये (कुल बजट का करीब 2%) का प्रावधान किया गया है। इसमें से 1,01,709.21 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और 4,821.21 करोड़ रुपये रिसर्च के लिए है। पिछले साल हेल्थ बजट 99,858 करोड़ रुपये था। इस बार 6.68 फीसदी का इजाफा है। सस्ती दवाओं, बेहतर सुविधाएं और रिसर्च पर फोकस किया है।

विदेश पर निर्भरता घटेगी

बजट की सबसे अहम घोषणा बायोफार्मा शक्ति योजना है। इसके तहत पांच साल में दस हजार करोड़ रुपये खर्च कर आधुनिक दवाओं का मजबूत घरेलू इकोसिस्टम तैयार होगा, ताकि कैंसर, डायबिटीज, ऑटोइम्यून जैसी गंभीर बीमारियों की महंगी दवाएं देश में ही बनें। अभी ये विदेश से आती हैं।

कैंसर की 17 दवाएं सस्ती

कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए भी अच्छी खबर है। सरकार ने कैंसर की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह माफ कर दी है। इसके अलावा 7 अन्य गंभीर बीमारियों की दवाओं के निजी आयात पर भी शुल्क से छूट दी गई है।

50% बढ़ेंगी जिला अस्पतालों में इमरजेंसी

देशभर के जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सुविधाओं को 50 फीसदी तक बढ़ाने का ऐलान किया है। मतलब, सड़क हादसों, दिल के दौरे या अन्य आपात स्थितियों में मरीजों को बेहतर और तेजी से इलाज मिलेगा।

फार्मा शिक्षा, रिसर्च को मजबूती

बायोफार्मा मिशन के तहत देश में तीन नए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (NIPER) खोले जाएंगे। मकसद है कि छात्र और वैज्ञानिक नई दवाओं की खोज में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकें।

आयुर्वेद : 3 बड़े संस्थान खुलेंगे

सरकार ने आयुष सेक्टर को भी मजबूत करने का फैसला किया है। देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे। इससे पारंपरिक इलाज पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और आयुर्वेद से जुड़े शोध व शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।

मेंटल हेल्थ के लिए निमहंस का विस्तार होगा

मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तर भारत में निम्हंस 2.0 खुलेगा। इससे देश के बड़े हिस्से को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। अभी सिर्फ बेंगलुरु में यह संस्थान है। एक हजार क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का नेटवर्क बनेगा।

'सिंदूर' के बाद 15% बढ़ा डिफेंस बजट

मॉडर्न होंगी सेनाएं, रिसर्च-डिवेलपमेंट पर फोकस

Poonam.Pandey@timesofindia.com

नई दिल्ली: ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश पहले बजट में भले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस का अलग से जिक्र नहीं किया, लेकिन इस बार डिफेंस बजट में पिछले साल के मुकाबले करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल खर्च करीब 22% बढ़ा है। कैपिटल खर्च का मतलब वह रकम, जो सैन्य उपकरणों की खरीद, मॉडर्नाइजेशन और इससे जुड़ी चीजों पर खर्च होती है। इस बार भी बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। डिफेंस बजट GDP का 1.99% और कुल बजट का 14.67% है। 2026-27 के लिए डिफेंस बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल 6.81 लाख करोड़ रुपये था। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। रिसर्च और डिवेलपमेंट के लिए 17,250 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह बजट 'जनभावनाओं और जनअपेक्षाओं पर खरा उतरता है। उन्होंने बताया कि 7.85 लाख करोड़ रुपये का यह आवंटन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन के लिए 1.55 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले बार की तुलना में 24 % अधिक है। इससे हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी।

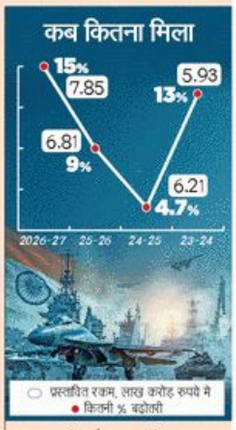

क्या संदेश है बजट में?

दो तरफा खतरों को देखते हुए सैन्य तैयारी और मॉडर्नाइजेशन पर सरकार का फोकस आगे भी बना रहेगा। जो नई चुनौतियों से निपटने की तैयारी को दिखाता है।

निर्मला सीतारमण का यह सबसे कम exciting बजट !

नज़रिया

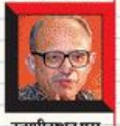

स्वामीनाथन एस. अंकलेसरिया अय्यर

वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि पीएम मोदी की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' सही रास्ते पर है, लेकिन बड़े सुधार का ऐलान नहीं किया।

साधारण! इस बार का बजट ऐसा ही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुल 9 बजट पेश किए हैं। इस बार के बजट को सबसे कम exciting कहा जा सकता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' सही रास्ते पर है, लेकिन किसी बड़े सुधार का ऐलान नहीं किया। उदाहरण के तौर पर वह यूरिया पर दी जा रही भारी सब्सिडी में कमी की घोषणा कर सकती थीं। मगर उनका जोर निरंतरता पर रहा। यूं भी वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में ग्रोथ 8% रही है। अगर वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच ग्रोथ मजबूत बनी हुई है, फिर इसे छेड़ा ही क्यों जाए!

बजट के बाद निफ्टी 2% से अधिक फिसला। वजह फ्यूचर्स ऐंड ऑप्शंस पर STT में भारी बढ़ोतरी रही। असल में, सरकार चाहती है कि छोटे निवेशक वायदा बाजार से दूर रहें, जिसमें हाल के वर्षों में काफी तेजी आई है। लेकिन इनमें से 93% को नुकसान हुआ है। मगर दुनिया का तजुर्बा यही सिखाता है कि टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर सट्टेबाजी पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। टैक्स दरों में बढ़ोतरी से ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ती है और इससे छोटे निवेशकों को और नुकसान होता है। STT में बढ़ोतरी के बजाय अगर ऐसे ट्रेड के लिए डिपॉजिट की रकम में इजाफा किया जाता तो छोटे निवेशकों को वायदा बाजार से बाहर रखना कहीं आसान होता।

इस बार के बजट में भी फिस्कल कंसॉलिडेशन यानी राजकोषीय घाटे में कमी का सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसकी रफ्तार बहुत धीमी है। वित्त वर्ष 2026 में इसके कुछ कम होकर GDP के 4.4% और अगले साल 4.3% रहने का अनुमान है। केंद्र के debt-GDP रेशो के भी 56.1% से घटकर 55.6% रहने का अनुमान वित्त मंत्री ने लगाया है। अगर यही स्पीड रही तो इसे एन. के. सिंह समिति के सुझाव के मुताबिक 40% तक लाने में लंबा वक्त लग सकता है। इसके बावजूद यह मानना होगा कि फिस्कल डेफिसिट की गुणवत्ता बेहतर हो रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026 में कैपेक्स 11 लाख करोड़ रखा था, जिसे अगले साल 12.2 लाख करोड़ करने की घोषणा की है। इसकी तारीफ की जानी चाहिए। अक्सर, जब कोई सरकार पांच साल के कार्यकाल में पहला बजट पेश करती है, तो उसमें वोटरों को खुश करने की कोशिश होती है। वहीं, कार्यकाल के आखिरी बजट में वोटरों के लिए लोकलुभावन वादे किए जाते हैं। कार्यकाल का तीसरा बजट सख्त सुधारों के लिए मुफीद होता है। इस साल केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में चुनाव हैं और इनमें से कहीं भी मुकाबला करीबी नहीं होगा। इसलिए सख्त उपाय किए भी गए होते तो चुनाव के नतीजों पर उसका बहुत असर नहीं होता।

इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जरूरत से ज्यादा सब्सिडी के कारण यूरिया की खपत फॉस्फोरिक और पोटैशियम उर्वरकों के मुकाबले अधिक है। बुरी बात यह है कि यूरिया से भूमि की गुणवत्ता बिगड़ती है। भारी सब्सिडी की वजह से यूरिया का उत्पादन केमिकल इंडस्ट्रीज की ओर होता है या इसे पड़ोसी देशों में स्मगल भी किया जाता है। हालांकि, पहले जब भी यूरिया सब्सिडी में कमी की कोशिश की गई तो किसानों के विरोध के कारण वह नाकाम हो गई। हालांकि, कांग्रेस के वित्त मंत्री के रूप में पी चिदंबरम नीम्ल पर सब्सिडी कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी कर खत्म करने में सफल रहे। निर्मला सीतारमण को भी फर्टिलाइजर सब्सिडी खत्म करने के लिए यही रास्ता अपनाना चाहिए था। बजट में अगले साल 10% नॉमिनल (महंगाई दर को जोड़कर) GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। इसमें रियल ग्रोथ 7% और महंगाई दर 3% रहने का अनुमान शामिल है। डॉनल्ड ट्रंप ने दुनिया में जो खलबली मचा रखी है, उसमें यह बहुत मजबूत ग्रोथ कही जाएगी। आज दुनिया की जो स्थिति है, उसमें भारत किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए रक्षा पर खर्च बढ़ाना मजबूरी है। रक्षा पर खर्च 15.3% बढ़ाया गया है। इसे आगे भी इसी रफ्तार से बढ़ाना होगा, तभी सैन्य क्षमता में भारत किसी तरह चीन के करीब पहुंच पाएगा।

वित्त मंत्री ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) डिवेलपमेंट में भारत को वैश्विक ठिकाना बनाने की पहल की है। इसलिए उन्होंने भारतीय डेटा सेंटर में हर तरह के विदेशी निवेश पर 2047 तक टैक्स छूट का ऐलान किया। यानी, वैश्विक इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी निवेशक भारतीय डेटा सेंटर में निवेश करेंगे, उन्हें इस टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। लेकिन क्या इसकी जरूरत थी, जब माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में डेटा सेंटर और उसके लिए आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर में 67.5 अरब डॉलर लगाने का ऐलान कर चुकी थीं? पश्चिमी देशों में AI डिवेलपमेंट के लिए साइंस, टेक्नोलजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में शिक्षित लोगों की कमी है। इस क्षेत्र में भारत को बढ़त हासिल है। वह हर साल इन विषयों में 1 करोड़ ग्रेजुएट्स तैयार करता है। इसलिए भारत को इन विषयों में गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है।

कंपनियां इधर डिविडेंड के बजाय बायबैक का इनेमल शेयरधारकों को रिवॉर्ड करने के लिए कर रही हैं। इसलिए अल्पमत निवेशकों की खातिर बायबैक पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर 12.5.4% और शॉर्ट टर्म पर 20%। इसके साथ टैक्स आर्बिट्राज खत्म करने के लिए कॉरपोरेट प्रोमोटर्स पर 22% और नॉन-कॉरपोरेट पर 30% टैक्स लगाने की घोषणा की गई है।

वित्त मंत्री ने मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स (MAT) को 15% से घटाकर 14% करने की बात कही है। उन्होंने कैरी-फॉरवर्ड प्रोविजन्स को खत्म कर दिया है। जानकारों का कहना है कि इससे 22% कॉरपोरेट टैक्स का आकर्षण बढ़ जाएगा। प्रवासी भारतीयों को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स से छूट दी गई है। अगले वित्त वर्ष में सरकारी कंपनियों की बिक्री से 80 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में इससे सरकारी खजाने में 33,837 करोड़ रुपये आए हैं। वित्त मंत्री का कहना है कि रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का प्रयोग सफल रहा है। और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास जो अतिरिक्त जमीनें हैं, उनमें इसी रास्ते से डिनिवेश किया जा सकता है। इस पैसे को नए प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा।

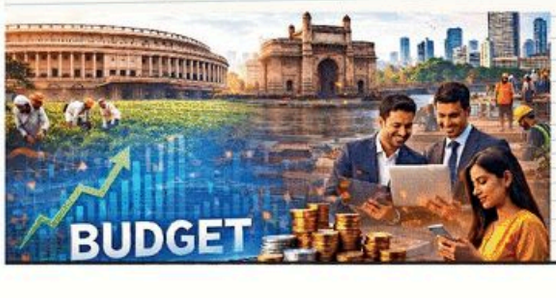

LOVE BOMBING
लव बॉम्बिंग

ये तो मिलते ही पीछे पड़ गया

जेन-जी के लिए Love Bombing का स्वरूप पूरी तरह डिजिटल है। 'प्यार' में ग्राइवेंसी और मेंटल हेल्थ महत्वपूर्ण है।

- **डिजिटल ओवरलोड** : किसी के इनबॉक्स को मीम्स, रील्स, मेसेज से भर देना 'डिजिटल लव बॉम्बिंग' है।
- नई पीढ़ी इसे रोमांस नहीं, एक Red Flag मानती है। उनके लिए Too much, too soon (बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी) खतरे की घंटी है।

Gen-Z की भाषा

पैसे वाली Love Bombing

अर्थशास्त्र और व्यापार में Love Bombing को Aggressive Market Acquisition के रूप में देखा जा सकता है।

- **स्टार्टअप, कैशबैक इकॉनमी** : कई स्टार्टअप्स पहले फ्रीबीज से ग्राहकों को Love Bomb करते हैं। आदत लगने पर कीमतें बढ़ा देते हैं
- **स्टॉक मार्केट और Pump and Dump** : बेकार स्टॉक्स या क्रिप्टो कॉइन को बढ़ाचढ़ाकर पेश करते हैं और ज्यादा पैसे लगते ही अपना हिस्सा बेचकर निकल जाते हैं।

RIZZ रिज़

इस बंदे में गज़ब का चार्म है...

Oxford Word of the Year बनने के बाद Rizz शब्द चर्चा में है। यह Charisma (करिश्मा) का छोटा रूप है। Rizz का मतलब सिर्फ सुंदर होना नहीं, यह आपकी Vibe और Confidence से जुड़ा है।

- **W Rizz** : आसानी से इम्प्रेस कर लेना। (Win)
- **L Rizz** : इम्प्रेस की कोशिश में फेल। (Loss)
- **Unspoken Rizz**: बिना कुछ कहे बस आपकी मौजूदगी ही काफी हो।

इकॉनमी के बारे में मतलब

Rizz को आर्थिक अवधारणा में Market Value और Branding के तौर पर समझा जा सकता है:

- **ब्रैंड इक्विटी** : किसी कंपनी का Rizz उसका ब्रैंड नेम है। Apple के पास Tech Rizz है, वह कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे, लोग खरीदने के लिए लाइन लगा देते हैं। यह ग्राहकों को बिना भारी डिस्काउंट के अपनी ओर खींचने की ताकत है
- **Soft Power (सॉफ्ट पावर)** : इकॉनमी में देशों के पास भी Rizz होता है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया का K-Pop Rizz या भारत का Cultural Rizz। यह बिना किसी सैन्य या आर्थिक दबाव के, अपनी संस्कृति के जरिये दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता है। अगर कंपनी का नाम सुनकर निवेशक बिना सवाल किए पैसा लगा रहे है, तो वह कंपनी का Economic Rizz है।

गाढ़े वक्त में MSME की ओर मित्रता का हाथ

10 हज़ार करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड, नियमों में मदद करेंगे कॉरपोरेट मित्र

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैरिफ और जियोपॉलिटिकल टकरावों से बने हालात से जूझ रहे छोटे और मझोले उद्योगों (MSME) को मजबूत बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के SME ग्रोथ फंड का प्रस्ताव रखा। उन्होंने MSME चैंपियन बनाने की बात करते हुए कहा कि सरकार का जोर रोजगार, उत्पादकता और आर्थिक वृद्धि बढ़ाने पर है। उन्होंने कॉरपोरेट मित्र बनाने का प्रस्ताव भी दिया। सीतारमण ने MSME को ग्रोथ का इंजन बताते हुए इनकी मदद के लिए तीन रणनीतियों का प्रस्ताव दिया। SME ग्रोथ फंड से MSME चैंपियन बनाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इसके तहत इनक्यूबेटिंग दी जाएगी। उन्होंने 2021 में बनाए गए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 2000 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा, ताकि छोटे उद्योगों को रिस्क कैपिटल मिलती रहे। वित्त मंत्री ने लिक्विडिटी

सपोर्ट की बात की और कहा कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के जरिये MSME को 7 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसका पूरा फायदा उठाने के लिए TReDS को MSME से केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की होने वाली सभी खरीदारियों के लिए ट्रांजैक्शन सेटलमेंट प्लैटफॉर्म बनाने की बात की। इस तरह यह दूसरे कॉरपोरेट्स के लिए भी पैमाना बन जाएगा। TReDS प्लैटफॉर्म पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म की बात की गई। MSME से सरकारी खरीद के बारे में फाइनैंसर्स के साथ जानकारी साझा करने के लिए TReDS को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस से जोड़ा जाएगा।

कॉरपोरेट मित्र

ICAI, ICSI, ICMAI जैसे प्रफेशनल इंस्टिट्यूट्स को सरकार सुविधाएं देगी, जिससे वे शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्सेज और प्रैक्टिकल टूल्स डिजाइन कर सकें। इनकी मदद से 'कॉरपोरेट मित्र' बनाए जाएंगे। ये छोटे शहरों में होंगे। सस्ती दरों पर ये MSME को सरकारी नियमों के अनुपालन में दिक्कतों से बचाएंगे।

इनसे भी मदद

रिफाइन्ड और अपडेटेड रिटर्न भरने की टाइमलाइन बढ़ाने से भी MSME को आसानी होगी। मैनपावर सप्लाई के लिए TDS के प्रावधानों को सरल करने से मदद मिलेगी। प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए पेनल्टी को फीस में बदलने से मुकदमेबाजी घटेगी। लेदर, सिथेटिक फुटवियर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट का प्रस्ताव है।

क्या है अहमियत?

MSME सेक्टर का GDP में करीब 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 35% और निर्यात में 45% योगदान है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग MSME में काम कर रहे है। कृषि के बाद रोजगार देने वाला सबसे बड़ा सेगमेंट है।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP1 User: cci Time: 02-01-2026 23:16 Color:

महानगर > मुंबई > सोमवार, 2 फरवरी 2026 > माघ 13 शक संवत 1947 फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2082

WATCH GOD WATCHDOG

NBT नवभारत टाइम्स

वर्ष 77, संख्या 27 > मूल्य ₹5.00 > पेज 14 > आर. एन. आई. पंजीयन नंबर 1613/57

www.nbt.in

UNION BUDGET 2026-27

सीतारमण का रेकॉर्ड

निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश किया। ये अपने आप में रेकॉर्ड है। पहला बजट 2019 में पेश किया था। तब स्पीच 2 घंटे 8 मिनट की थी। ये भी उनका एक रेकॉर्ड था।

ये बजट गरीब, अन्नदाता, युवाशक्ति और नारीशक्ति को और सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट गांव को मजबूत करने का बजट है।

-नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पीएम मोदी बोले

राहुल बोले- संकट पर आखें बंद वित्त मंत्री ने कहा- फैक्ट दें

बजट का हाई वोल्टेज

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि बजट समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है। सीतारमण ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे (राहुल गांधी) किन चीजों को दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था और उसकी बुनियाद मजबूत है। वैश्विक अनिश्चितता हमारी कई सेक्टर्स प्रभावित कर रही है, जिनके लिए हमने लघु-मध्यम उद्यमों, कपड़ा और चमड़ा उद्योग... किसानों और महिला उद्यमियों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर लिखा, ये ऐसा बजट है, जिसमें चीजों को दुरुस्त करने के बजाय वास्तविक मंकटों से आंखें मूंद ली गई है। वित्त मंत्री ने कहा, हम आम छोटे लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बाहर से आने वाली किसी भी कोलैटिलिटी से जिंदगी में बड़े बदलावों का सामना न करना पड़े।

राहुल गांधी के सवाल पर वित्त मंत्री का पलटवार

पॉलिटिकली आप बुराई करना चाहते है, प्लीज करें। अगर आप वे फैक्ट्स देना चाहते है जिन पर आप अपनी बात रख रहे है तो मै सुनने और जवाब देने को तैयार हूं। -निर्मला सीतारमण

युवाओ के पास जॉब नही है, मैन्यूफैक्चर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे है। घरेलू बचत घट रही, किसान संकट में। अर्थव्यवस्था को जो वैश्विक झटका लगा, उसे अनदेखा किया। -राहुल गांधी

निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट, दिखे कई रंग

निर्मला सीतारमण ने 31 मई 2019 को वित्त मंत्रालय संभाला। उनकी बजट स्पीच की लंबाई से लेकर साड़ी तक की भी हर बार चर्चा होती रही है। पिछले 8 बजट की ये तस्वीरें है।

'रिफॉर्म एक्सप्रेस में भारत, बनने जा रहा तीसरी बड़ी इकॉनमी'

बजट को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। इस बजट से युवा की उड़ान के लिए असमान खुल गया है। भारत तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। बजट से भारत की ग्लोबल पोजिशन मजबूत होगी। ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। उन्होंने कहा कि भविष्य को ध्यान में रखकर इस बजट को पेश किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। ये विकसित भारत की गति को तेज करने वाला बजट है। ये बजट अनंत अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी कांची उड़ान का मजबूत आधार है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है।

यूथ की उड़ान के लिए आसमान खुला: PM

ट्रेन से मुंबई टु पुणे केवल 48 मिनट में

बजट में हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान

AI Image

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : मुंबई से पुणे के बीच रेलयात्रा अब केवल 48 मिनट में पूरी हो सकेगी। ऐसा इसलिए कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने नित्न हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है, उनमें मुंबई-पुणे कॉरिडोर भी है। यानी इन दोनों शहरों के बीच बुलेट जैसी ट्रेनें चलेंगी। अभी दोनों शहरों की रेल से दूरी 4 घंटे है। बड़ी संख्या में लोग हर दिन मुंबई-पुणे आना-जाना करते हैं। हाई स्पीड ट्रेन से उन्हें राहत मिलेगी। इसकी संभावित रफ्तार 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कॉरिडोर शुरू होने से आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। ▸▸ विस्तृत खबर पेज 2

आप इस तरह होंगे प्रभावित

महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब
डेटा सेंटर लगाने के लिए विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की तैयारी। इसमें निवेश लाने में महाराष्ट्र पहले से आगे। नयी मुंबई और आसपास कई डेटा सेंटर।

हाउसिंग सेक्टर पर असर
अटके प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के रुकावटी फंड-2 की घोषणा से मुंबई-MMR के अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे करने संभव होंगे।

प्रफेशनल कोर्सों से लाभ
प्रफेशनल सस्थानों को साथ लेकर शॉर्ट-टर्म, मॉड्यूलर और प्रैक्टिकल कोर्स डिजाइन करने का प्रस्ताव। सबसे बड़े MSME राज्य को होगा फायदा।

शहरी महिलाओं को फायदा
महिला उद्यम, स्वयं सहायता समूह (SHG), SHE मार्ट और STEM से शिक्षा और रिकल डिवेलपमेंट को प्राथमिकता से शहरी महिलाओं के लिए नए अवसर।

सहकारी संघों को बूस्ट
राष्ट्रीय सहकारी संघों को कंपनियों में किए निवेश से मिलने वाली डिविडेंड आय पर तीन वर्षों तक कर-छूट देने के प्रस्ताव से सहकारी समितियों को बूस्ट मिलेगा।

गेमिंग और कॉमिक का हब
ABGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब की घोषणा से मुंबई को इनका हब बनने में मदद मिलेगी।

महाराष्ट्र को 1 लाख करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा किया कि केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र को करीब एक लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। केंद्रीय करों में महाराष्ट्र का हिस्सा 98,306 करोड़ रुपये के करीब होगा। वैसे, बजट के प्रारंभिक आकलन के अनुसार विभिन्न परियोजनाओं के लिए 12,355 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस तरह से राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। शोध हब के लिए अगले 5 वर्षों में 5-5 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर), पुणे और नागपुर शोध हब को लाभ होगा। 1,702 करोड़ रुपये मुंबई मेट्रो के लिए प्रावधान किया गया है। ▸▸ विस्तृत खबर पेज 5

1,702 करोड़ रुपये मुंबई मेट्रो के लिए

फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के घर के बाहर की फायरिंग, 5 लोग गिरफ्तार

Manish.Jha@Timesofindia.com

■ **मुंबई: मुंबई के** हाई प्रोफाइल इलाके जुहू में फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर शनिवार रात गोलीबारी हुई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार, CCTV फुटेज में ऑटो ड्राइवर से एक संदिग्ध बात करते हुए दिखाई दिया। ऑटो ड्राइवर ने बताया कि संदिग्ध युवक ने उससे पूछा था, क्या तुम कल्याण जाओगे? ड्राइवर ने दूर होने की बात कही तो वह झल्लाकर चला गया। पुलिस ने इसी बयान के आधार पर जाल बिछाकर गिरफ्तारियां की हैं। ▸▸ पेज 8

बिल्डिंग पर 5 गोलियां चलाई गईं।

क्या लॉरेंस गैंग ने की फायरिंग, जांच जारी

एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने बताया कि पुलिस पिछले डेढ़ से दो वर्षों में मुंबई में घटी फायरिंग की घटनाओं के एंगल से इस केस को देख रही है जिनमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया था। क्या ये लोग उसी गैंग से हैं, इसकी जांच जारी है।

ईरान नहीं, वेनेजुएला से तेल लेगा भारत: ट्रंप

■ **एजी, न्यू यॉर्क:** अमेरिका के राष्ट्रपति **डॉनल्ड ट्रंप** ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय अपने विमान 'एयर फोर्स वन' में यह कमेंट किया। ट्रंप की इस टिप्पणी पर भारत की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ▸▸ पेज 10

खबरों के अंदर की बात

NBT Lens

देखें पेज 9

अंतर्ज्ञान

सबका अपना-अपना गतिक्रम होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। कोई एक साल में खिलता है, कोई दस साल में। अपनी गति का सम्मान करना आत्म-प्रेम का हिस्सा है। जब हम दूसरों की गति से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी यात्रा के बीज को कुचल देते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी पेड़ एक जैसी गति से नहीं बढ़ता, फिर हम क्यों दूसरों की टाइमलाइन पर खुद को तौलते हैं? जो अपनी गति को पहचान लेता है, वह बिना हड़बड़ी के खिलता है। धैर्य वह मिट्टी है, जिसमें आत्मा का विकास सबसे सुंदर रूप लेता है। अपनी गति को अपनाना स्वयं को अपनाना है। जब आप अपनी लय में चलते हैं, तभी जीवन का संगीत सुनाई देता है।

सर्राफा

सोना स्टैंडर्ड (99.5 शुद्धता) प्रति 10 ग्राम

मुंबई	148102	(-17,029)

चांदी .999 टच प्रति किलो

मुंबई	265751	(-73,599)

अर्थसार

सेंसेक्स	80,722.94	(-1546)
निफ्टी	24,825.45	(-495.25)
रुपया/डॉलर	91.96	(+0.020)
रुपया/यूरो	109.5417	(-0.401)

मौसम

कोलाबा	29.0	21.4
सांताक्रुज	29.5	21.0
सूर्यास्त सोमवार	6:32 बजे	
सूर्योदय मंगलवार	7:12 बजे	

NBT कार्टून — सड़क व रेल पर्यटन तीन गुना 100 रुपए मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिले के बाहर।

जिला परिषद चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे फडणवीस

■ **NBT रिपोर्ट, मुंबई :** पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के कारण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिला परिषद और पंचायत समितियों में चुनाव प्रचार नहीं करने का निर्णय लिया है। शनिवार को फडणवीस ने इस फैसले की जानकारी देते हुए स्थानीय नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को प्रचार करने का निर्देश दिया और कहा कि वह खुद किसी चुनाव कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। राज्य की 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के लिए 7 फरवरी को मतदान होगा और प्रचार 5 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। पहले सीएम फडणवीस को सात दिनों में 22 चुनावी सभाओं को संबोधित करना था। पुणे जिले के बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान हादसे में पवार के निधन के बाद घोषित तीन दिवसीय राजकीय शोक को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम में संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 5 फरवरी को होने वाला मतदान अब 7 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 9 फरवरी को होगी। ▸▸ पेज 8

विलय से पहले NCP (अजित) चर्चा करे

■ **NBT रिपोर्ट , मुंबई :** मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें विलय के मामले में अजित दादा और शरद पवार के बीच हुई बातचीत की कोई जानकारी नहीं है। भविष्य में यदि दोनों एनसीपी विलय का निर्णय लेती हैं, तो अजित गुट को बीजेपी से चर्चा करनी होगी। फडणवीस ने आगे कहा कि अगर एनसीपी के विलय की चर्चाएं अंतिम चरण में होती, तो अजित पवार ने इसके बारे में जरूर बताया होता। एनसीपी (SP) के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा था कि अजित ने दोनों गुटों के विलय की घोषणा के लिए 12 फरवरी की तारीख तय कर ली थी, लेकिन अब विलय की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।

डॉग बाइट के शिकार 12 वर्षीय लड़के की मौत

■ **NBT न्यूज, भिवंडी :** डॉग बाइट के शिकार भिवंडी निवासी लड़के की रविवार को मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में मौत हो गई। 10 जनवरी की सुबह भिवंडी के इंदिरा मोहल्ले में हाशिम सद्दाम खान (12) को स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था। आईजीएम हॉस्पिटल में उन्हें रेबीज वैक्सीन व टिटनेस इंजेक्शन भी दिए गए। हालत बिगड़ने पर मुंबई रेफर किया गया था। ▸▸ पेज 7

ऐंटि रेबीज वैक्सीन देकर भी नहीं बची जान

वर्ल्ड कप: भारत-पाक मैच नहीं

■ **भाषा, लाहौर:** पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगी। टूर्नामेंट के बाकी मैचों में पाकिस्तान टीम खेलेगी। इधर, रविवार को बुलावायो में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से हराकर सेमीफाइनल में एंट्री की, जहां उसे अफगानिस्तान से भिड़ना है। ▸▸ पेज 9

मेलबर्न में कार्लोस अल्काराज का 'राज'

Agency

■ स्पेन के टेनिस खिलाड़ी अल्काराज ने 24 बार के ग्लैंडस्लैम चैंपियन जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता।

■ अल्काराज ने पहला सेट गंवाया, लेकिन बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। मैच 3 घंटे से ज्यादा चला।

■ मेलबर्न में फाइनल को जीतकर अल्काराज करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बने।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP2 User: cci Time: 02-01-2026 23:19 Color:

क्या है बड़ी फिक्र...

भारत में Gen Z का करीब 50% हिस्सा मानता है कि बेहतर फाइनैंशल फ्यूचर सबसे बड़ी फिक्र है।

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

UNION BUDGET 2026-27

बजट विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। यह बजट प्रगतिशील और भविष्योन्मुखी वाला है। देश के विकास की गति तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इससे विकसित भारत का विजन वास्तविकता बनेगा। - नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27 • BUDGET 2026-27

बोरीवली से चर्चगेट=मुंबई से पुणे

मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद सहित 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

Priya.Pandey@Timesofindia.com

■ **मुंबई:** मुंबई से पुणे के बीच का यात्रा समय अब केवल 48 मिनट का हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय बजट 2025-26 में इन दोनों शहरों के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का ऐलान किया गया है। बता दें कि इस रूट पर यात्रा करने वालों की संख्या हमेशा से ही ज्यादा रही है। विभिन्न यात्रा के साधन से लोग इस मार्ग पर आना-जाना करते हैं। गौरतलब है कि ऐसे कई लोग है जो हर दिन मुंबई-पुणे आना-जाना करते हैं। ऐसे में बुलेट ट्रेन शुरू होने पर उन्हें काफी राहत मिलेगी। जितने समय में लोग बोरीवली से चर्चगेट पहुंचते हैं, उतने समय में ही लोग मुंबई से पुणे पहुंच जाएंगे। बताया जा रहा है कि बुलेट ट्रेन की संभावित रफ्तार 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।।

All AI Images

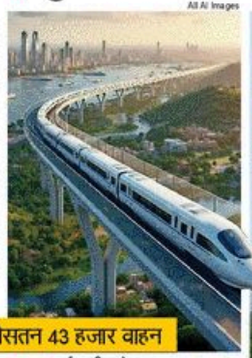

5 यातायात खास बातें

- मुंबई से पुणे एक घंटे से भी कम समय में पहुंचेंगे। यह बड़ी राहत है।
- ट्रैफिक जाम से भी निजात मिलेगी। हाइवे पर जाम आम है।
- कॉरिडोर की वजह से खुलेंगे रोजगार के नए अवसर।
- आईटी, उद्योग, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा।
- मौजूदा रेल और रोड का भार होगा कम।

उद्योग, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र को लाभ

इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू होने से न सिर्फ यात्रा का समय काफी कम होगा, बल्कि दोनों मार्गों पर आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। मुंबई-पुणे-हैदराबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से आईटी, उद्योग, व्यापार और शिक्षा क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। तीनों शहर देश के प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्र हैं, ऐसे में तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही सड़क और हवाई यातायात पर बढ़ते दबाव में भी कमी आएगी।

मुंबई और पुणे के बीच हाई स्पीड ट्रेन शुरू होने के बाद दोनों शहर की दूरी महज 48 मिनट की हो जाएगी, जिसमें आज के समय ट्रेन और सड़क मार्ग से करीब 4 घंटे का वक्त लगता है। इसी तरह पुणे से हैदराबाद की दूरी भी काफी हद तक कम हो जाएगी। दोनों शहरों के बीच आज 8 से 10 घंटे की दूरी है। यह भी 1 घंटे 55 मिनट रह जाएगी।
- अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री

रोज गुजरते हैं औसतन 43 हजार वाहन

हर दिन मध्य रेलवे की तरफ से सुबह 5 स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं, जिसमें वंदे भारत भी शामिल हैं। लेकिन फिर भी ट्रेन की टिकट कन्फर्म होना संभव नहीं हो पाता। इसी के साथ लोग सड़क मार्ग मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे से भी यात्रा करते हैं। कुछ प्राइवेट वाहन से तो कुछ बस और शेयरिंग कैब से इस रूट पर यात्रा करते हैं। गौरतलब है कि मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन औसतन 43 हजार वाहनों का आवागमन होता है।

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

- मुंबई-पुणे
- चेन्नई-बेंगलुरु
- हैदराबाद-बेंगलुरु
- पुणे-हैदराबाद
- हैदराबाद-चेन्नई
- दिल्ली-वाराणसी
- वाराणसी-सिलीगुड़ी

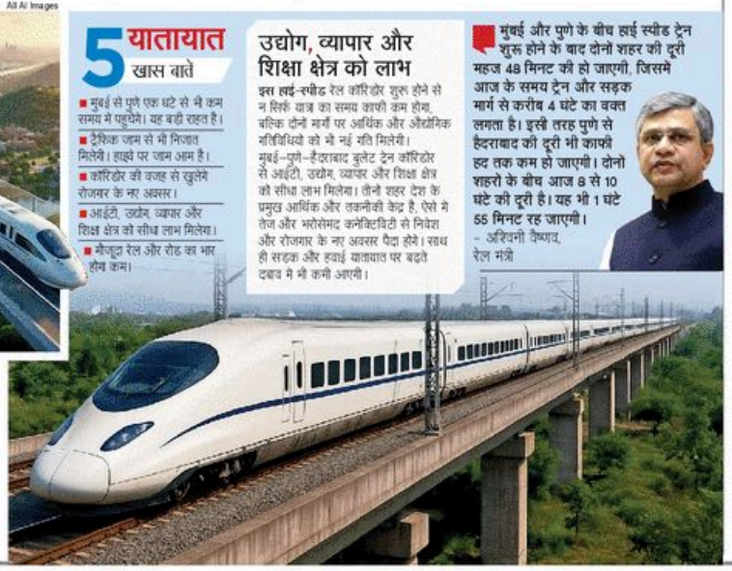

मुंबई में बनेगा कंटेंट क्रिएटर लैब

एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग का हब बनेगी मुंबई

Brijesh.Tripathi@Timesofindia.com

■ **मुंबई :** केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के वर्ष 2026-27 के बजट में मुंबई में ABGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) के लिए एक कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने की घोषणा की गई है। इससे मुंबई को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक का हब बनने में मदद मिलेगी। ये लैब्स मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी में बनाई जाएंगी। इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह लैब 1500 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में बनाई जाएंगी। इन लैब्स में छात्रों को गेम डिजाइन, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई में पहले से ही एनीमेशन फिल्म, गेम, वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है। डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए नेशनल डिजाइन स्कूल भी खोले जाएंगे।

सरकार की योजना के तहत गेमिंग और संबंधित क्रिएटिव इंडस्ट्री में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है। इसके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा जिससे युवाओं को इंडस्ट्री-रेडी स्किल मिले। सरकार की शिक्षा से जुड़ी ये पहल मुंबई में एनीमेशन, वीएफएक्स और ई स्पोर्ट्स जैसे उभरते क्षेत्रों में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए की गई है।

5 एनिमेशन खास बातें

- फिल्म, एनिमेशन, वीएफएक्स, ऑनलाइन गेम जैसे सेक्टर में फायदा
- 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार के अवसर
- युवाओं में इस सेक्टर के प्रति रुझान बढ़ेगा
- फिल्म, रील्स और शॉर्ट फिल्म को बढ़ावा मिलेगा
- युवाओं की क्रिएटिविटी और प्रफेशनल स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा

राज्य बनेगा डेटा सेंटर का हब, बढ़ेगा रोजगार, कई ग्लोबल कंपनियों के आने की बढ़ी उम्मीद

Vijay.Pandey1@Timesofindia.com

■ **मुंबई:** डेटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सबसे बड़ा ऐलान किया। सीतारमण के मुताबिक, भारत में डेटा सेंटर बनाकर ग्लोबल ग्राहकों को क्लाउड सर्विस देने वाली कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे मिलेगा। यह डेटा सेंटर इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें एक शर्त यह भी है कि उस कंपनी को भारत के ग्राहकों को सर्विस देने के लिए किसी भारतीय रिसेलर को जरिया बनाना होगा। अभी भारत का डेटा सेंटर मार्केट करीब 10 अरब डॉलर का है। भारत में डेटा सेंटर की क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है।

चुनौतियां और मौके: नवी मुंबई के अलावा ज्यादा मुख्य केंद्रों पर डेटा सेंटर स्थापित हो चुके हैं। डेटा सेंटर को और ग्रोथ देने के लिए नई जगहों की तलाश करनी होगी। डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर बिजली की खपत करता है। इसीलिए, बड़ते डेटा सेंटर की डिमांड को पूरा करने के लिए बिजली के नए स्रोत उपलब्ध कराने होंगे। सोलर एनर्जी में महाराष्ट्र काफी तेजी से काम कर रहा है। इसका फायदा भी इस इंडस्ट्री को होगा। इसके अलावा, डेटा सेंटर को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन की जरूरत होती है। इस नेटवर्क को बढ़ाकर ग्रामीण इलाकों तक भी डेटा सेंटर की ग्रोथ को पहुंचाया जा सकता है। BSDS के एमडी पीयूष सोमानी का कहना है कि डेटा सेंटर में निवेश को टैक्स हॉलिडे, टेकर सिंगापुर, आयरलैंड और मिडिल ईस्ट के साथ भारत ने भी निवेश को आकर्षित करने लिए यह बड़ा फैसला किया है।

5 डेटा सेंटर खास बातें

- डेटा सेंटर बनाने विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने की तैयारी।
- इसमें बड़े पैमाने पर निवेश भी होगा और रोजगार के मौके भी।
- महाराष्ट्र पहले से ही डेटा सेंटर्स को आकर्षित करते रहा है।
- बिजली की खपत और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से और विस्तार होगा।
- छोटे शहर में जमीन की आसान उपलब्धता भी इसके लिए बड़ा मौका।

निवेश आकर्षित करने की क्षमता

डेटा सेंटर के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने में महाराष्ट्र पहले से ही आगे है। नवी मुंबई और आसपास के इलाकों में कई डेटा सेंटर स्थापित हो चुके हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में कई समझौते भी किए। विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर स्थापित करने पर मिलने वाली टैक्स छूट का महाराष्ट्र की ग्रोथ में बड़ा असर होगा। इस टैक्स छूट से कई ग्लोबल कंपनियां यहां अपना डेटा सेंटर बनाएंगी। महाराष्ट्र में फिलहाल आधे से ज्यादा डेटा सेंटर कार्यरत हैं। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने पॉलिसी भी जारी की है।

प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को सरकार ने दी राहत

रिट्स और स्वामी फंड से बढ़ेगी मुंबई के अटके प्रॉजेक्ट्स की रफ्तार

Pankaj.Pandey@Timesofindia.com

■ **मुंबई :** अटके प्रॉजेक्ट को पूरा करने के लिए सीतारमण ने 15 हजार करोड़ रुपये के स्वामी फंड-2 की घोषणा की है। इस फंड के माध्यम से मुंबई समेत एमएमआर के अटके हाउसिंग प्रॉजेक्ट को पूरा करना संभव होगा। साथ ही रियल इस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) का गठन करने का फैसला लिया है।

जस्टो रियलफिनटेक के चेयरमैन पुष्पमित्र दास के अनुसार, स्वामी फंड के माध्यम से रेरा रजिस्टर्ड प्रॉजेक्ट को सरकार के माध्यम से फंड उपलब्ध कराया जाता है। फंड मिलने से लोगों को घरों का सपना पूरा होने के साथ ही हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। क्रेडाई-एमसीएचआई के पूर्व अध्यक्ष टॉमिनिक रेबेल के अनुसार, रिट्स से सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। रिस्क गारंटी की वजह से बैंकों से लोन की कठिनाई कम होगी।

5 इंफ्रास्ट्रक्चर खास बातें

- प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत।
- रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (रिट्स) का गठन किया जाएगा।
- बैंकों को रियल इस्टेट प्रॉजेक्ट को कर्ज देना आसान होगा।
- 45 लाख तक की कीमत वाले को किफायती घरों की श्रेणी में है।
- घरों का सपना पूरा होने के साथ ही हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ेगा।

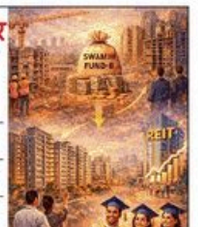

प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने दूसरा घर खरीदने वाले को कैपिटल गेन देने की घोषणा की है। अब तक लोगों को एक घर पर ही कैपिटल गेन का लाभ मिलता था। बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेजिडेंट आनंद मुहा के अनुसार, दूसरे घर पर कैपिटल गेन का लाभ मिलने से लोगों की सालाना 1 लाख रुपये की बचत होगी।

यूनिवर्सिटी-टाउनशिप से बदलेगी सूरत

शिक्षा से रोजगार तक मुंबई होगी प्रोफेशनल सपोर्ट सिस्टम का केंद्र

5 एजुकेशन खास बातें

- एमएसएमई को सस्ता और भरोसेमंद प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा
- युवाओं के लिए रोजगार-उन्मुख स्किल डेवलपमेंट का मौका
- महिला उद्यम और रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा
- शिक्षा और सेवा क्षेत्र के बीच मजबूत सेतु बनेगा
- शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम स्थायी समिति का गठन होगा

Navin.Pandey@Timesofindia.com

■ **मुंबई:** यूनियन बजट में यह साफ किया गया है कि पढ़ाई सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका सीधा जुड़ाव रोजगार और स्वरोजगार से होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मुंबई और महाराष्ट्र को मिलने की उम्मीद है। बजट में प्रोफेशनल सपोर्ट, एआई-आधारित स्किल असेसमेंट, शिक्षा-से-रोजगार नीति और उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी गई है। राज्यों को समर्थन देकर पांच यूनिवर्सिटी-टाउनशिप विकसित करने की घोषणा की गई है।

MSME को मिलेगा 'कॉरपोरेट मित्र' का सहारा

बजट की अहम घोषणाओं में सरकार द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमआई) जैसे प्रोफेशनल संस्थानों को साथ लेकर शॉर्ट-टर्म, मॉड्यूलर और प्रैक्टिकल कोर्स डिजाइन करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके तहत 'कॉरपोरेट मित्र' नाम से प्रशिक्षित पैरा-प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएंगे। यह MSME को कंप्लायंस, अकाउंटिंग, टैक्स और कॉरपोरेट नियमों में कम लागत पर मदद करेंगे। अंतरराष्ट्रीय एजुकेशनल फाउंडेशन के अध्यक्ष सीए सुनील गोयल का मानना है कि कॉरपोरेट मित्र मॉडल से इन इकाइयों पर अनुपालन का बोझ कम होगा और स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।

संदीप यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉ. संदीप झा ने कहा कि बजट में एआई मिशन, नैशनल क्वांटम मिशन, अनुसंधान नैशनल रिसर्च फंड और रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड के के जरिए नई तकनीकों को बढ़ावा देने की बात करी गई है। इसका असर मुंबई-पुणे बेल्ट में मौजूद आईटी, फिनटेक, रिसर्च और स्टार्टअप सेक्टर पर साफ दिखेगा।

पीड़ा पर लगेगी मरहम, आश्रितों तक पहुंचेगी रकम

ब्याज में टैक्स छूट से ऐक्सिडेंट मामलों में राहत

Krishna.Shukla@timesofindia.com

■ **मुंबई:** रोड एक्सीडेंट विक्टिम के परिजन के लिए बजट में बड़ी राहत की घोषणा हुई है। सरकार अब विक्टिम के परिजन को मिलने वाले मुआवजे के ब्याज पर टैक्स नहीं लेगी। यह छूट विक्टिम के आश्रितों को बड़ी राहत देगी। एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करने वाले ऐडवोकेट बालासाहब देशमुख का कहना है कि कई विक्टिम की आमदनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए उन्हें ज्यादा मुआवजा नहीं मिल पाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस फतुल पर चिंता जाहिर की थी। ऐसे में सरकार का फैसला विक्टिम के आश्रितों के लिए बड़ी राहत देने वाला है। टैक्स केस जानकार ऐडवोकेट नितेंद्र मिश्रा ने बताया कि ब्याज को आय के रूप में देखा जाता है। इसलिए इस पर टैक्स का प्रावधान है, मगर एक्सीडेंट के मामले में ट्रिब्यूनल की ओर से मुआवजे पर मिला ब्याज एक तरह की नुकसान भरपाई है।

लोकल बॉडीज को बॉन्ड से मिलेगा फंड, लोकल बॉडीज खुद अपना फंड इकट्ठा कर पाएंगी

Vijay.Pandey1@Timesofindia.com

■ **मुंबई:** बजट में लोकल बॉडीज को बॉन्ड के जरिए पैसे इकट्ठा करने के प्रेरित करने वाले कदम उठाए हैं। इससे राज्य सरकार पर लोकल बॉडीज को दिए जाने वाले फंड से राहत मिलेगी। लोकल बॉडीज खुद फंड इकट्ठा कर पाएंगी और उसकी जिम्मेदारी से उसे खर्च करने की योजना भी बनाएंगी। लोकल बॉडीज को मार्केट से पैसा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बजट में 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा बॉन्ड के जरिए इकट्ठा करने पर 100 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। नबकि 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के बॉन्ड पर मिलने वाला प्रोत्साहन पहले की तरह जारी रहेगा। पुणे, नासिक समेत कई मनपा बॉन्ड के जरिए पैसे जुटा चुकी हैं।

5 मनपा बॉन्ड खास बातें

- मनपाओं को कम आय होने की वजह से तमाम प्रॉजेक्ट्स के लिए सरकार पर निर्भर होना पड़ता है।
- बॉन्ड के जरिए मनपाओं को पैसे का नया स्रोत मिलेगा।
- बॉन्ड जारी करने से पहले रेग्युलेशन से जुड़ी हुई तमाम गाइडलाइंस पूरी करनी होंगी।
- पैसा वापस करने की शर्त के चलते मनपाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।
- जिस प्रॉजेक्ट के लिए पैसे लिए जाएंगे, उसका उपयोग उसी में होगा।

बॉन्ड के जरिए पैसे लेने का एक फायदा यह भी है कि सिस्टम की अकाउंटिंग सही ढंग से होती है और पारदर्शिता बढ़ जाती है। वित्त मंत्री का यह कदम महानगरपालिकाओं के लिए निर्णायक कदम है।
- मनीषा खत्री, कमिश्नर, नासिक मनपा

मनपाओं को फंड के लिए नया विकल्प मिलेगा। जनता को पैसे वापस करने की जिम्मेदारी से वित्तीय अनुशासन भी बढ़ेगा।
- सुनील गोयल, फाउंडर, लेडर अप वैल्थ मैनेजमेंट

शी मार्ट और स्किल से खुलेगा महिलाओं के रोजगार का रास्ता

मुंबई और MMR की महिलाओं को SHG, स्टार्टअप और स्किल डिवेलपमेंट से मिलेगा सीधा फायदा

Manish.Jha@timesofindia.com

■ **मुंबई:** केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तीय रूप से महिला उद्यमिता पर जोर दिया गया है। इसका असर मुंबई और एमएमआर में देखने को मिलेगा। यहां रहने वाली महिलाएं सीधे तौर स्किल के टम पर स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं, जिसके लिए बजट में कई घोषणाएं वित्त मंत्री ने की।

FICCI की एक सीनियर डायरेक्टर डॉ.विजयंती पंडित ने बताया कि बजट में महिला उद्यम, स्वयं सहायता समूह (SHG), SHE मार्ट और STEM के जरिए शिक्षा और स्किल डिवेलपमेंट को प्राथमिकता दी गई है। इससे शहरी महिलाओं के लिए नए अवसर खुलने की उम्मीद है। इसके लिए बजट में 53.4 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

5 रोजगार खास बातें

- महिला उद्यम, स्वयं सहायता समूह, स्किल डेवलपमेंट को 53.4 लाख मिले
- महिलाएं डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म से जुड़ सकेंगी।
- रिटेल आउटलेट शी मार्ट मॉडल से खुले बाजार तक पहुंच मिलेगी।
- कम्युनिटी एरिया में शी रिटेल आउटलेट चलाने का मौका मिलेगा।
- 'युवा शक्ति' योजना के तहत आसान ब्याज दर पर 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा।

SHG और माइक्रो बिजनेस को बूस्ट

इंडिया SME फोरम के प्रेजिडेंट विनोद कुमार ने बताया कि मुंबई व एमएमआर में सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह इस योजना के जरिए डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिजिटल बिजनेस ऐप और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगी। फूड प्रोसेसिंग, होम-बेस्ड प्रोडक्ट, फिशरिंग, डिजाइन, एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, गेमिंग, हस्तकला, सोलर, ब्यूटी फार्मा, डेयरी जैसे लोकल सर्विस सेक्टर से जुड़ी महिलाओं को क्लस्टर आधारित रिटेल आउटलेट शी मार्ट मॉडल से खुले बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। इससे माइक्रो बिजनेस को भी बूस्ट मिलेगा।

स्टार्टअप लोन और पहचान पर जोर

इस बजट में महिलाओं से संबंधित प्रमुख सरकारी सहायता योजनाओं पर खास ध्यान दिया गया है। खासतौर से स्टार्टअप लोन की सुविधा की घोषणा की गई है। कुमार के अनुसार, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 'युवा शक्ति' योजना के तहत आसान ब्याज दर पर 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिलेगा, जिससे महिलाएं कारोबारी पहचान स्थापित करेंगी। पहले मुद्रा योजना, फिर लखपति दीदी योजना और अब शी मार्ट योजना से महिलाओं की वित्तीय उद्यमिता को नई पहचान मिलेगी। ब्रांड वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का प्रशिक्षण मिलेगा।

यह रिफॉर्म्स एक्सप्रेस बजट है। STEM कोर्स और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर महिलाओं के उद्यम और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मैं इस बजट को 10 में से 7 अंक देती हूं।
-डॉ.विजयंती पंडित, पूर्व वरिष्ठ निदेशक, FICCI

महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले मुद्रा, फिर लखपति दीदी और अब शी मार्ट योजना से जोड़कर वित्तीय रूप से उद्यमी बनाने का प्रयास किया गया है।-विनोद कुमार, प्रेजिडेंट, इंडिया SME फोरम

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP3 User: tushar.darekar@timesofindia.co Time: 02-01-2026 21:12 Color:

श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण

श्रद्धांजलि

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।।

भावपूर्ण श्रद्धा एवं हृदयंगम कृतज्ञता के साथ हम उनके गौरवमय जीवन का स्मरण करते है

श्री बजरंगलाल सूरजमल तापड़िया (दादाजी)

अध्यक्ष, द सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

25 नवंबर 1934 - 30 जनवरी 2026

"उन्होंने उद्देश्यपूर्ण, मजबूत सिद्धांतों और अटल मूल्यों द्वारा मार्गदर्शित जीवन जिया।
परिवार और समाज के प्रति उनका कर्तव्य सर्वोपरि रहा।
वे अपनी जड़ों से सदा जुड़े रहे।
उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा बना रहेगा
जिन्हें उन्हें जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।"

उनके जीवन को सम्मान अर्पित करने हेतु प्रार्थना और स्मरण सभा

दिनांक: 3 फ़रवरी, मंगलवार
स्थान: सोफ़िया भाभा ऑडिटोरियम
समय: 5:00 से 7:00 बजे

स्नेहपूर्वक स्मरण करने वाले,
तापड़िया एवं सुप्रीम परिवार

महावीर प्रसाद - रानी	(भाई एवं भाभी)
शिवरतन - कुसुम	(भतीजे एवं पुत्रवधू)
विजय - उर्वशी	(पुत्र एवं पुत्रवधू)
विवेक - प्रियंका	(पौत्र एवं पौत्रवधू)
विरेन, अनिका एवं अक्षय तापड़िया	(परपौत्र एवं परपौत्री)
नीलम - अजय पेरीवाल	(पुत्री एवं दामाद)
निशा - अजय राठी	(पुत्री एवं दामाद)
वृंदा-रजत जैन	(पौत्री एवं नातिदामाद)

द सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड **सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड**

श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण

बजटः मुंबई और MMR में सप्लाई चेन–लॉजिस्टिक्स को मिलेगी रफ्तार

कस्टम क्लियरेंस और वाटरवेज से घटेगी एक्सपोर्ट की लागत

Neeraj.Tiwari@timesofindia.com

■ **मुंबई:** केंद्र सरकार के बजट 2026–27 ने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सेक्टर को लेकर लंबे समय से चली आ रही इंडस्ट्री की मांगों को काफी हद तक मान्य किया है। इस बजट का सीधा असर मुंबई, मुंबई मेट्रोपॉलिटिन रीजन (MMR), पुणे, नागपुर और नासिक जैसे औद्योगिक व पोर्ट आधारित शहरों पर पड़ेगा। सरकार ने ग्रीन ग्रेट रूट्स, तेज कस्टम क्लियरेंस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम पर फोकस कर संकेत दिया है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की दिशा में आगे बढ़ेगा।

अब क्या बदला: अब तक सरकार का जोर मुख्य रूप से सड़क और रेल नेटवर्क के विस्तार पर था। अब सरकार ने ट्रान्सहुनी (पूर्व) से सुपर (पश्चिम) को जोड़ने वाले नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, जिससे मुंबई–नवी मुंबई बेल्ट को सीधे उत्तर और पूर्वी भारत के औद्योगिक क्षेत्रों से तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

शिपिंग को नई ताकत: पहले इनलैंड वॉटरवेज का इनलेमल सीमित था, लेकिन अब अगले पांच साल में 20 नए नेशनल वॉटरवेज की योजना है। फोसल कार्गो प्रमोशन स्कीम के तहत जलमार्ग और समुद्री रास्तों से कार्गो ट्रांसपोर्ट का हिस्सा 2047 तक 6 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है।

इंडस्ट्री ने किया स्वागत: हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन और ग्रीनफेस इंडस्ट्रियल रैंट लॉजिस्टिक पार्क के चेयरमैन सिंघल हीरानंदानी ने कहा कि वेयरहाउसिंग, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स में निवेश से सप्लाई चेन की लागत घटेगी। कोस्टल कार्गो इकोनॉमी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और कस्टम्स में सेफ हार्बर जैसे सुधार एक्सपोर्ट को नई गति देंगे। वहीं, बावला के फाउंडर और सीईओ राम अय्यर ने कहा कि बजट में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) तकनीक के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देगा। इससे वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कम-कार्बन समाधान अपनाने में मदद मिलेगी।

यूनियन बजट से कॉपरेटिव सेक्टर को है बूस्ट मिलने की उम्मीद

सहकारिता के लिए गेम चेंजर, किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा पैसा और रोजगार

■ NBT रिपोर्ट , मुंबई

सहकारिता क्षेत्र में महाराष्ट्र देश में नंबर वन है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध व्यवसाय से लेकर अन्य सहकारी समितियों को इस बजट से बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। बजट 2026-27 में सरकार ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय सहकारी संघों को कंपनियों में किए गए निवेश से मिलने वाली लाभांश आय पर तीन वर्षों तक कर-छूट देने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। इससे सहकारिता क्षेत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। टैक्स छूट, निवेश प्रोत्साहन और प्राथमिक सहकारी समितियों को नई राहत से किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को सीधा लाभ मिलेगा। सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि इस व्यवस्था से सहकारी ढांचे में मध्यस्थता कम होगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। जब अतिरिक्त आय वाले सदस्य समितियों तक पहुंचेगी, तो वे अपने सदस्यों को बेहतर सेवाएं, अधिक अवसर और आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकेंगी। इससे किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण समुदायों को सीधा लाभ मिलेगा।महाराष्ट्र में 2.22 लाख से अधिक सहकारी समितियां हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। इनमें मुख्य रूप से आवास, लोन और मार्केटिंग, दुग्ध, चीनी मिल समितियां शामिल हैं। इनमें से 2,14,851 से अधिक समितियां वर्तमान में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं।

इन समितियों में 5.5 करोड़ से अधिक सदस्य शामिल हैं। साथ ही राज्य में 155 से अधिक चीनी मिल सहकारी समितियां हैं। इन समितियों का संचालन महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम 1960 के तहत किया जाता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र को सहकारी समितियों से जोड़ा गया है। बजट में सहकारी समितियों को कर राहत देते हुए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र से जुड़े सदस्यों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले प्रावधानों की घोषणा की गई है। ये कदम डेयरी सहकारिताओं को मजबूत, पशुपालकों को आय में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बजट में प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु-चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को भी शामिल किया जाएगा। इससे पशुपालकों और बीज उत्पादक किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र देश में दूसरे स्थान पर है। बजट के प्रावधानों से महाराष्ट्र के कपास उत्पादक किसानों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे सहकारी संघों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और पूरा सहकारी तंत्र मजबूत होगा।

All Image

ये है फायदे

- दुग्ध व्यवसाय से लेकर अन्य सहकारी समितियों को फायदा
- इसका फायदा उन समितियों को भी मिलेगा जो पशु-आहार आपूर्ति करती है
- पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा
- निवेश से मिलने वाली लाभांश आय पर तीन वर्षों तक कर-छूट
- कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद

TIMES interact
Connecting People, Connecting Needs
To book your ad Logon to: ads.timesofindia.com or Call: 18001205474 (Toll Free)
Scan QR Code

ऑटो | भर्ती | टेंडर और नोटिस
हैवी व्हीकल्स | भर्ती-रिक्त पदों की स्थिति | निविदाएं (टेंडर्स)
ट्रक्स | तकनीकी | इंजीनियर्स
बिजनेस | अन्य रिक्तियां
बिजनेस प्रस्ताव | एकाधिक रिक्तियां

TATA Ultra 1918/60 सिंगल एक्सल, (GJ19)32 फोर्ट JCBL, कंटेनर, स्लीपर केबिन, फ्रन्ट ओपन, (AMC), AIP, Feb20 No Urea, कीमत रु.15 लाख। संपर्क: 9509772455

REQUIRED Exp. Site Engineer / Supervisor for Repair Works at Byculla. Send your CV : 9967353887/ 9967010208

PREMIUM EUROPEAN COATING RESINS/ ADDITIVES
We can offer a diverse range of high-performance materials regularly at low prices, including:
• Waterborne Polyurethane Dispersions
• Acrylic Polyols
• Alkyds & Epoxies
• Functional Monomers & Crosslinkers
Please contact:
Euro Exim Limited
Manchester (UK)
Email: eurooexim@limited.co.uk
WA No: +447930990094

ipsit
WE ARE HIRING
SALES EXECUTIVE & ENGINEER
(REAL ESTATE)
LOCATION:
Palghar West (Site Office)
For more details, contact us on
+918424024432

IDBI BANK
बीकायाद : LB5190MH2004GO144838
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
वेबसाइट : www.idbibank.in
मुंबई ज़ोन-2026 के लिए नई बैंक शाखाओं के पुनर्विकास कार्य और शाखाओं और अन्य बिज़नेस सेंटरों के रिनोवेशन और रीलोकेशन के लिए आर्किटेक्ट्स का प्री-क्वालिफिकेशन और एम्पैनलमेंट
मुंबई ज़ोन के लिए आर्किटेक्ट्स के प्री-क्वालिफिकेशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर जाएं या 022-6678-8600 या 022-6127-9218 पर संपर्क करें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी, 2026 दोपहर 3:00 बजे तक है।
नोट: - उपरोक्त के संबंध में कोई भी अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण/विवरण केवल बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा और समाचार पत्रों में कोई अलग से सूचना जारी नहीं की जाएगी।
मुंबई, 2 फरवरी, 2026
हस्ताक्षर/-
(ज़ोनल हेड (MZO)

ई नीलामी सूचना
आज से बाधित लगभग 1,126.86 MT स्टाम्पवाल स्टील और लगभग 1,232.33 MT रीहैण्डलेबिल स्टील / टॉर स्टील
इच्छुक खरीदारों को "प्रति किलोग्राम" के आधार पर "आज से बाधित लगभग 1,126.86 M T स्टाम्पवाल स्टील और लगभग 1,232.33 MT रीहैण्डलेबिल स्टील/ टॉर स्टील" के निपटान के लिए के आधार पर बेचने के लिए ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। विभागगत अवशेष "जैसा है, जहाँ है", जो कुछ भी है" और "कोई शिकायत नहीं" के आधार पर बेचा जाएगा और वेस्टर्न जेडीएफएल विभाग प्राइवेट लिमिटेड का है। विभागगत सामग्रियों का निरीक्षण गांव मुढेगांव, तालुका - इगतपुरी, नासिक, महाराष्ट्र - 422001 में केवल कार्य दिवसों पर 02-02-26 से 16-02-26 के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। कृपया निरीक्षण के लिए श्री सुदीप मंडल से 8347526866 पर संपर्क करें।
ई-नीलामी 17-02-26 को होगा।
ई-नीलामी के नियम और शर्तों वाला फॉर्म प्राप्त करने के लिए कृपया श्री. विभू झा से 8369652088 पर संपर्क करें। या वेबसाइट से डाउनलोड करें: https://www.sealthedeal.co.in/
नीलामीकर्ता : सील द डील
रजिस्टर कार्यालय : प्रॉमी मंज़िल, ऑफिस नं. 2, किंग्स गेट, रोहिणी सेक्टर 10, दिल्ली - 110085
फॉर्म और इंस्ट्रक्शन डिलीवरी इमेल जमा करने की अंतिम तिथि 16-02-26 है।

NEW INDIA ASSURANCE
दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
The New India Assurance Co. Ltd
प्रयुक्त स्टाफ कारों की विक्री
कंपनी की प्रयुक्त स्टाफ कार की खरीद के लिए "as is where is" के आधार पर इच्छुक पार्टी/पार्टियों से मुहरबंद प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन करें और निविदा सूचना अनुभाग पर जाएं!
https://www.newindia.co.in/tender-notice
प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा दस्तावेज उपरोक्त वेबसाइट से डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है। निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथी 13.02.2026 शाम 15:00 बजे तक है।
वाहन निरीक्षण/प्रदर्शन के लिए मेकेअर गाईन, लिटिल गिब्स रोड, मुंबई, महाराष्ट्र ४००००६ पर उपलब्ध है।
द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड संपत्ति एवं संयंत्रा विभाग, छठी मंजिल, न्यू इंडिया बिल्डिंग, 68, एम जी रोड, आला चौक, किला, मुंबई- 400001
आई.आर.डी.ए. पंजीयन संख्या - 190
सीआइएन नं. U99999MH1919GOI000526

सेवाएं
ज्योतिष
विवाह बाधाएं जहां सभी समस्याओं का हल प्रेमविवाह, विदेशयात्रा, गृहक्लेश, उच्चारी बाधा का गारंटेड समाधान लोक कहते हैं हम करके दिखाते. 9867234766 / 8828954766
TIFFIN SERVICES
टोकन 800 टिफिन जाते है पूरे मुंबई में, 65 या उससे अधिक की उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को दोपहर का नि:शुल्क टिफिन पहोंचाया जायेगा, सीमती कुसुम हिरेश भुगोलाल पोपटलाल गुटका एमार्पोसी 8828004404 केवल व्हॉट्सएपि (कॉल नहीं)

MMR में CER से विकास को रफ्तार

विकसित होंगे डहाणू, पालघर और आसपास के इलाके

Neeraj.Tiwari@timesofindia.com

■ **मुंबई:** वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा रविवार को की गई। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 12.20 लाख करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है। इसके तहत महाराष्ट्र में वॉटरवेज को बढ़ाने और सस्ते नैशनल जलमार्गों से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। जिन इलाकों की संख्या 5 लाख से अधिक है, उन्हें सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) के तहत विकसित करने का प्लान बनाया गया है। इसके तहत पांच वर्षों के लिए 5000 करोड़ की निधि आवंटित की गई है। इससे महाराष्ट्र के छोटे शहर जिनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, ठाणे, पालघर, पिंपरी-चिंचवड़, नासिक, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), नवी मुंबई, सोलापुर, मीरा-भायंदर, भिवंडी-निजामपुर, अमरावती, नांदेड़-वाघाला, कोल्हापुर, उल्हासनगर और सांगली-मिराज-कुपवाड़ के नाम शामिल हैं, उन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं देने में मदद मिलेगी।

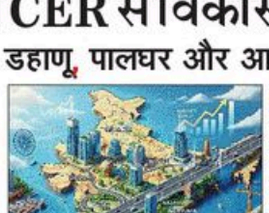

> किसी भी इलाके में लोगों को बसाने के लिए वहां यातायात, स्कूल, अस्पताल का निर्माण करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इलाकों के लिए 5000 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रो लेवल पर बेहतर होगा।
>
> सुखराज नाहर, अध्यक्ष क्रेडाई-एमसीएचआई

बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के निर्माण को मिलेगी रफ्तार

मुंबई और एमएमआर में राज्य सरकार और एमएमआरडीए कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। इनमें मेट्रो, नवी मुंबई एयरपोर्ट और नैना सिटी प्रोजेक्ट शामिल हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने 5000 करोड़ रुपये की निधि की घोषणा इन्हें रफ्तार देगी। इसके अलावा एमएमआरडीए बुलेट ट्रेन के रूट पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के निर्माण पर काम कर रहा है। केंद्र सरकार के सीईआर का सबसे अधिक फायदा इस योजना को मिलने की बात कही जा रही है। इन इलाकों में मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन के साथ वेयरहाउसिंग और लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी काम किया जा रहा है। एमएमआरडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन इलाकों में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए पैसे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इन इलाकों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए छोटी-छोटी परियोजनाएं प्लान की जाती हैं। इनके लिए कई बार पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपये की घोषणा इन इलाकों के विकास में तेजी लाएगी।

सार्वजनिक सूचना
जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल, फ्लैट विक्रेता, एकमात्र प्रोपराइटर: श्री सुरेश जी. चव्हाण, जिनका कार्यालय 429, ओरिया बॉर्ड, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई में स्थित है, ने श्रीमती संजना सुकेश बिष्ट, श्री आकाश सुकेश बिष्ट और सुश्री गुंजन सुकेश बिष्ट ("पूर्व खरीदार") के अनुकूल में ठाणेस्थित संपत्ति का एक निर्माण अभिव्यक्ति दिनांक 16/10/2025 के एक विक्रय विलेख के तहत अधिकार, स्वामित्व है, जिसे मेरे मुवक्किल और पूर्व खरीदारों के बीच निष्पादित किया गया था और उप-पंजीकृत अधिक एसबीसी, मुंबई-31 के पास पंजीयन संख्या MUMBAI-31-25237-2025 के तहत पंजीकृत किया गया है। इसलिए, मेरे मुवक्किल अनुकूल में ठाणेस्थित संपत्ति के एक निर्माण अभिव्यक्ति बिक्री के एकमात्र, पूर्ण और वैध मालिक हैं और उस पर उनका कब्जा है। इसलिए, जनसाधारण को आगाह किया जाता है कि वे अनुकूल में ठाणेस्थित संपत्ति में किसी भी अधिकार, शीर्षक और हित का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ कोई लेनदेन, बातचीत, व्यवहार या किसी भी व्यवहार में प्रवेश न करें और ऐसा करने वाला कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति मेरे मुवक्किल या अधोहस्ताक्षरी का जोखिम और परिणाम होगा और मुवक्किल किसी किस ऐसे अपने जोखिम पर करेंगे, जिसके लिए उनसे लागतों और परिणाम उत्तरदायी होंगे।
कब्जा संपत्तियां अनुसूची
वह सभी प्रोपोजल भूमि जिसका माप लगभग 2039.28 वर्ग मीटर है, जिसका सी.टी.एस. संख्या 433/उप है, जो देवकरण गांव, तालुका कुर्ला, सायन पनवेल रोड, मुंबई के पंजीकरण जिले, कुर्ला के उप-जिले, मुंबई उपनगरीय में स्थित है और जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं:
उत्तर की ओर: - सायन-ट्रॉम्बे रोड द्वारा
दक्षिण की ओर: - सदर बाग सी.एस.एस., सेट नं. 2 के स्वामित्व वाली भूमि द्वारा
पूर्व की ओर: - सी.टी.एस. संख्या 433/2 वाली प्लॉट द्वारा
दिनांक 2 फरवरी, 2026
के. श्रीनिवास वरदराजन
अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, बम्बई
505, "ए मोटूना" प्रेस कॉलोनी रोड, चेम्बूर, मुंबई – 400 071

WR पर बढ़ाई गईं चार लोकल सेवाएं, इस महीने के आखिर तक चार और बढ़ेंगी

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: पश्चिम रेलवे पर कांदिवली और बोरीवली के बीच छठी लाइन का काम पूरा हो गया है। इसी के चलते 1 फरवरी से 12 कोच वाली 4 नॉन एसी लोकल सेवाओं का इजाफा किया गया है। हालांकि अब ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि फरवरी के अंत तक और 4 सर्विस बढ़ाई जाएंगी। इससे यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। 1 फरवरी से 4 सर्विस बढ़ने के बाद कुल सर्विस 1410 हो गई है, जो पहले 1406 हुआ करती थी। फरवरी अंत तक 4 और लोकल सेवाएं बढ़ जाएंगी। इसका आंकड़ा 1414 हो जाएगा। बता दें कि बोरीवली और बांद्रा टर्मिनस के बीच छठी लाइन के कमीशन होने की वजह से बांद्रा टर्मिनस की ओर आने/जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों को पांचवीं एवं छठी लाइन पर स्थानांतरित किया गया है, जिससे लोकल ट्रेनों के संचालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

SBI
आईटी-सहायक संबंध विभाग, भारतीय स्टेट बैंक, परोक्ष आईटी सेन्टर, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई – 400614
निविदा आमंत्रण सूचना
आवश्यकी नं.: SBI/GITC/IT-Partner Relationship/2025-26/1042/III
दिनांक: 02.02.2026
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक के कॉलसाधार विभिन्न अनुप्रयोगों और आईटी पहलों के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान करने के लिए आईटी कंपनियों के पैनल के लिए पात्र बोलीदाताओं से बोलियां आमंत्रित की जाती हैं. विस्तृत जानकारी के लिए कृपया https://sbi.bank.in पर 'प्रोक्यूरमेंट न्यूज' एवं ई-प्रोक्योरमेंट एजेन्सी पोर्टल https://etender.sbi/SBI/ पर देखें.
आवश्यकी के डाउनलोड का आरंभ : 02.02.2026 से
बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 23.02.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक.
स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 02.02.2026
उप महाप्रबंधक
आईटी-सहायक संबंध विभाग

सवारी डिब्बा कारखाना
निविदा सूचना संख्या 202523212048 दि.: 23.01.2026
निम्नलिखित ई-निविदा IREPS वेबसाइट पर उपलब्ध की गई है। फर्मों से अनुरोध है कि वे www.ireps.gov.in पर लॉगइन करें और निविदा के लिए आवश्यक कोटेशन प्रस्तुत करें। इस निविदा के लिए निर्धारित कोटेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

क्र. सं.	खुली निविदा संख्या	मदों का संक्षिप्त विवरण	निविदा मूल्य (₹)	निविदा फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि / खुलने की तिथि
1.	202523 5212048	सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई में उपकरणों की टेस्टिंग और इंस्टलेशन सहित ईएचयूएचईएमयू ईएमयू (ईसीएचएचएमयूटी और कोचकमता मेट्रो कोच में कार्यरत का कार्य पूरा करना	₹ 25,74,39,996/-	16.02.2026 को 15.00 बजे तक

उप मुख्य वित्तीय इंजीनियर/फर-1

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण
बाजार व परवाना विभाग
"दैनिक बैठक क्सुलीसाठी इच्छुक अभिकर्त्यांची नेमणूक करणेकामी"
- : जाहीर निविदा सूचना : -
निविदा क्र. १ (२०२६-२७)
दि. ०१/०४/२०२६ ते दि. ३१/०३/२०२९ या ३ वर्षांच्या कालावधीकरीता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका परिक्षेत्रात रस्त्यावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून/विक्रेत्यांकडून दररोज दैनिक बैठक फी महानगरपालिकेने निश्चित केलेल्या दरानुसार वसुली करुन निविदेमध्ये देकारानुसार महापालिका फंडात जमा करणेकामी सन २०२६-२७ ते २०२८-२०२९ या ३ वर्षाच्या कालावधीकरीता इच्छुक अभिकर्त्यांकडून देकार ई-टेंडरींग निविदा पध्दतीने मोहरबंद निविदा मागविण्यात येत आहे.
इच्छुक अभिकर्त्यांना, खाजगी व्यक्तीना शासकीय/निमशासकीय संस्थाना निविदेच्या अटी शर्तीचा तपशिल निविदा सच रु.२८५००/- + १८% वस्तू व सेवा करसहीत जमा करुन दि. ०२/०२/२०२६ ते दि. १८/०२/२०२६ रोजी दुपारी २.०० वाजेपर्यंत mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध होतील.
विहित नमुन्यातील निविदा mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-टेंडरींग पध्दतीने दि. ०२/०२/२०२६ ते दि. १८/०२/२०२६ दुपारी ३.०० वाजेपर्यंतच सादर करावयाच्या आहेत. प्राप्त झालेल्या निविदा शक्य झाल्यास दि. १८/०२/२०२६ सायं. ५.०० वाजता उपस्थित निविदाकाराच्या समोर महापालिकेच्या निविदा कक्ष (Tender cell) येथे उघडण्यात येतील.
सदर निविदा उघडण्याच्या वेळी एक अथवा सर्व निविदा राखून ठेवण्याचा अथवा कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा अधिकार "आयुक्त, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण" यांनी राखून ठेवला आहे.
ठिकाण :- कल्याण.
दि. ०२/०२/२०२६
स्वाक्षरी/-
(रामदास कोकरे)
उप-आयुक्त (बाजार व परवाना)
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण.

पैकर्स ऐंड मूवर्स बनकर की ठगी

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई: कुरार पुलिस ने पैकर्स एंड मूवर्स बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, अंधेरी निवासी अभिनेत्री नेहा मलिक (27) ने शिकायत दर्ज कराई थी। नेहा का आरोप है कि 4 जनवरी को इन्फिनिट लॉजिस्टिक पैकर्स एंड मूवर्स के नाम से आए वैभव सिंह ने शिफ्टिंग के बहाने करीब 5 लाख रुपये का सामान लेकर ठगी की। मामले में 10 जनवरी को केस दर्ज किया गया था। तकनीकी जांच के आधार पर सह आरोपी विजय पाल (40) को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ठगी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है।

शरद पवार से मिले गौतम अदाणी

■ NBT रिपोर्ट, मुंबई : एनसीपी प्रमुख शरद पवार से रविवार को उद्योगपति गौतम अदाणी ने मुलाकात की। यह भेंट पवार के निवास सिल्वर ओक पर हुई। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की प्लेन क्रैश में असमय मौत के बाद यह दोनों की पहली मुलाकात मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, गौतम अदाणी ने शरद पवार से मिलकर अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया। अदाणी करीब 45 मिनट तक सिल्वर ओक में मौजूद रहे। बता दें कि अदाणी और पवार परिवार के बीच लंबे समय से पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं।

SOCIAL EVENT
श्री ब्रजमंडल के स्वर्णिम वर्ष के उपलक्ष में आयोजित
श्रीमद् ब्रजभागवत कथा
परमाराध्य पूज्य श्री मन्महा मंडलेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामीजी महाराज की अमृतवाणी से
आज 2 फरवरी की कथा समय सुबह 10 से दोप.1 बजे | कथा स्थल-आज़ाद मैदान, मुंबई
आज की कथा : सुदामा चरित्र, नवयोगेश्वर संवाद, अवधूतो उपाख्यान, कलियुग का वर्णन, शुकदेव जी विदाई, परिक्षित मोक्ष, पुष्प होली हवन यज्ञ पूर्णाहुति एवं भण्डारा
मुख्य यजमान : श्री सुरेशचन्द्र श्यामलाल अग्रवाल
श्री योगेश एवं श्रीमती मीना अग्रवाल
दैनिक यजमान : श्रीमती सुमनलता प्रदीप बंसल श्री प्रदीप बंसल श्री अभिषेक प्रदीप बंसल
पूर्णाहुति भंडारा यजमान : श्री गोविंद दाऊदयाल अग्रवाल
श्रीमती प्रीति विकास अग्रवाल श्रीमती सुनयना पंकज अग्रवाल
सभी कथाप्रेमी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। प्रवेश पास द्वारा
अध्यक्ष एवं ट्रस्टी: सुरेशचन्द्र अग्रवाल मान्य मंत्री: प्रदीप आर.लाढ़ीवाल कोषाध्यक्ष: अनिल आर. अग्रवाल
महिला समिति: संरक्षिका-नीता योगेश अग्रवाल, सुमन प्रदीप बंसल अध्यक्षा-आशा सुनिल अग्रवाल मानद् मंत्री-रुपाली योगेश गुप्ता उपाध्यक्षा - अनिता अनिल अग्रवाल, रेनू ओमप्रकाश अग्रवाल कोषाध्यक्षा - मधु सत्यप्रकाश अग्रवाल
महिला समिति सदस्या - नीलम कृष्णकुमार अग्रवाल, विनिता अनिल अग्रवाल, अंजली पवन अग्रवाल
कांता भुवनेश अग्रवाल, रितु हरिओम अग्रवाल, हेमलता दिनेश अग्रवाल, पूजा उमेश मित्तल
संयोजक: श्री राजीव श्यामसुंदरजी अग्रवाल, थाना
सारथी रियल्टर्स - एसोसिएट्स थाना, मुंबई

REMEMBRANCE SHARING MEMORIES
॥ जय जिनेन्द्र ॥
इक्कीस्वी पुण्यतिथी
स्वतंत्रता सेनानी
श्री पद्मप्रसादजी शिवदयालजी जैन (अग्रवाल)
(1920-2005)
पूजनीय पिताजी की स्मृति में
पुत्र: सुभाषचंद, कुलदीपचंद, बालकृष्ण, मनोज,
पौत्र: निखिल, सुमित, अनंत, निखिल, राज, वीर एवं समस्त जैन परिवार.

BOOK OBITUARY ADS
To book an Obituary Ad Please contact:
Jitendra Baricha 9820 137 295 | Jitesh Dominic 9867 487 521
Asif Faridi 9594 343 468
TO BOOK ONLINE LOG ON TO
Ads.timesofindia.com
EXCLUSIVE OFFERS AND ASSISTANCE
SCAN TO BOOK

TO PLACE A PERSONAL ANNOUNCEMENT IN THIS SECTION CALL: 9887505472

THE TIMES OF INDIA
Readers are recommended to make appropriate enquiries and seek appropriate advice before sending any money, incurring any expenses, acting on medical recommendations or entering into any commitment in relation to any advertisement published in this publication. All creatives marked as Advertorial, Spotlight and Promotional Features are to be treated as Advertisements. The Times of India Group doesn't vouch for any claims made by the Advertisers of the products and services. The Printer, Publisher, Editor, and the owners of The Times of India Group publications shall not be held liable for any consequences, in the event such claims are not honoured by the Advertisers.

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 02-02-2026 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP5 User: cci Time: 02-01-2026 23:44 Color:

भविष्य पर किसका असर

एक सर्वे मे 80% से ज्यादा Gen Z मानते है कि जलवायु परिवर्तन का उनके भविष्य पर असर होगा।

UNION BUDGET 2026-27

मैं मानता हूं कि बजट केवल वार्षिक राजस्व और व्यय का बयान भर नहीं होता। मौजूदा परिस्थितियों में बजट भाषण को उन प्रमुख चुनौतियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण पेश करना चाहिए, जिनका जिक्र कुछ दिन पहले जारी किए गए आर्थिक सर्वे में किया गया था।- पी. चिदंबरम, कांग्रेस

रेयर बीमारियों की महंगी दवाएं होंगी सस्ती

बड़ी संख्या में मरीज होंगे लाभान्वित, जीवनरक्षक दवाओं की कीमतें घटने से इलाज होगा आसान

हेल्थ सेक्टर
खास बातें

- आनुवंशिक बीमारियों मे लगने वाली कुछ दवाओं से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है
- सरकार द्वारा ड्यूटी मे राहत की घोषणा से इलाज का आर्थिक बोझ कम होगा
- रेयर डिजीज के क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा देने की घोषणा भी काफी अहम

Suraj.Pandey@timesofindia.com

मुंबई : केंद्र सरकार के नए बजट मे रेयर और जेनेटिक बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। डॉक्टरों ने कहा, क्रीएमके कैंडीएम अस्पताल मे आने वाले सैकड़ों मरीजों को इस घोषणा लाभ मिलेगा। ऐसे कई जीवनरक्षक ड्रग्स जिन पर अब तक भारी कस्टम ड्यूटी लगती थी, उन्हें पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी और मरीज आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे।

नैशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज के अंतर्गत दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के 12 सरकारी अस्पतालों में सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर रेयर डिजीज की शुरुआत की। उक्त अस्पतालों को सालाना 50 लाख रुपये की वित्तीय राशि दी जाती है, ताकि वे बीमारी का निदान कर सकें। हालांकि, बीमारियों का इलाज काफी महंगा होता है और फंड कम है। इस बजट में आनुवांशिक बीमारियों मे लगने वाली कुछ दवाओं से ड्यूटी हटा दी गई है। कैंडीएम अस्पताल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज की डॉ. ममता मुरंजन ने बताया, रेयर डिजीज का इलाज बेहद महंगा है और इसका असर हर वर्ग के मरीजों पर पड़ता है। अगर एक महीने की दवा एक लाख रुपये की है और उसकी कीमत घटी, तो वह डेढ़ से 2 महीने तक चल सकती है।

AI image

ड्यूटी न लेने की घोषणा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण

- देशभर मे दुर्लभ बीमारी का बोझ बढ़ रहा है।
- 12 सेंटर्स मे कुल 4,559 मरीज इलाज के लिए रजिस्टर्ड है।
- डॉक्टरों के अनुसार, दवाएं इतनी महंगी है कि अधिकतर मरीजों की पहुच के बाहर हैं।
- सरकार ने कुछ दवाओं पर ड्यूटी नही लेने का निर्णय लिया है, जिससे सभी को इलाज मिल सके।

मरीजो को मिलेगा इसका लाभ

सरकार द्वारा ड्यूटी मे राहत की घोषणा से इलाज का वित्तीय बोझ कम होगा और मरीजो को लाभ मिलेगा। कैंडीएम अस्पताल मे हर साल करीब 400 से 450 नए रेयर डिजीज के मरीज रेफर होते है। यह फैसला सभी मरीजो के लिए फायदेमद साबित होगा और रेयर डिजीज के इलाज मे एक अहम कदम है। बजट मे क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा देने की घोषणा भी अहम है। डॉ. ममता के अनुसार, कैंडीएम मे पहले से ही रेयर डिजीज के क्लीनिकल ट्रायल्स चल रहे है और पात्र मरीजों को न सिर्फ ट्रायल के दौरान बल्कि उसके बाद भी दवाओं का लाभ मिलता है। इस घोषणा से भारत मे ट्रायल का माहौल और अनुकूल होगा, जिससे मरीजों की नई और इनोवेटिव दवाओं तक पहुच बढ़ेगी।

दवाओं में ड्यूटी की छूट पर क्या बोले मुंबई के डॉक्टर

NBT रिपोर्ट, मुंबई : केंद्रीय बजट मे ग्रावबिटीज से जुड़ी दवाओं पर ड्यूटी मे छूट देने की घोषणा को स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मरीजों के लिए राहत भरा कदम बताया है। महाराष्ट्र सरकार के आंकड़ो के अनुसार, राज्य मे करीब 29 लाख लोग ग्रावबिटीज से पीड़ित है। ऐसे मे दवाओं की कीमतों मे कमी सीधे तौर पर मरीजों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ घटा सकती है।

लीलावती अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और पद्मश्री डॉ. शशांक जोशी ने बताया, ग्रावबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारी मे दवाइयों की कीमतें सबसे बड़ा फैक्टर होती है। बजट मे ग्रावबिटीज की दवा सस्ती होने की घोषणा एक बेहद अहम और समय पर लिया गया कदम है। सरकार का यह फैसला खास तौर पर गरीब व मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए राहत देने वाला है। नायर अस्पताल के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग प्रमुख डॉ. गिरिजा भारवा ने बताया, भारत मे अधिकतर मरीज दवाओं का खर्च अपनी जेब से उठाते है। अगर दवाओं पर ड्यूटी कम होती है, तो यह मरीजों के लिए बड़ी राहत है। कुछ नई ग्रावबिटीज दवाएं फिलहाल 15 से 17 हजार रुपये महीने तक की है, लेकिन पेटेंट समाप्त होने के बाद भारतीय कंपनियों के आने से यही दवाएं 3-4 हजार रुपये मे मिल सकती है। इससे मरीजों के लिए इलाज जारी रखना आसान होगा।

मुंबई मे मरीजो का इलाज होगा और अधिक सुलभ

कैंसर की महंगी दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह हटाने से मरीजों को मिलेगी राहत

Suraj.Pandey@timesofindia.com

मुंबई : केंद्र सरकार के बजट मे कैंसर की कई महंगी दवाओं पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह हटाए जाने से टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी आधुनिक इलाज पद्धतियां अब ज्यादा मरीजों तक पहुंचने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से खासतौर पर मुंबई के मिडिल क्लास कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

टाटा मेमोरियल सेंटर के निदेशक डॉ. सुदीप गुप्ता ने बताया, लंग्स, ब्रेस्ट और किडनी कैंसर जैसी कॉमन बीमारियों मे इस्तेमाल होने वाली टारगेटेड थेरेपी बेहद महंगी होती है। इन दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटने एक बहुत अच्छा कदम है। इससे ज्यादा मरीज इन इलाज विकल्पों तक पहुंच पाएंगे। एपल्स रिलायंस अस्पताल के क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की निदेशक वरिष्ठ ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. सेवंती लिमए ने बताया, देशभर में फिलहाल केवल 1 से 3% मरीज ही टिश्यूज ड्रग्स ओसोर्ट कर पाते है। अगर टैक्स में छूट से इसमें 1% की भी बढ़ोतरी होती है, तो भारत जैसे देश में यह संख्या काफी मायने रखती है।

हमारे अस्पताल मे इलाज के लिए आने वाले करीब 60-70% प्रतिशत मरीज किसी न किसी तरह इन दवाओं का खर्च उठा पाते है, जबकि शेष मरीजों के लिए लागत अब भी बड़ी चुनौती है। गरीब जो वंचित रह जाते है, लेकिन मिडिल क्लास के लिए भी अफोर्डेबिलिटी एक चुनौती है। ड्यूटी मे राहत से मिडिल क्लास को राहत मिलने की आशा है।

कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत राज्य मे 2020 से 2024 तक 12,7512 कैंसर मरीज मिले थे।

इनमे से कई मरीजो को टार्गेटेड थेरेपी की जरूरत थी, लेकिन दवाओ पर ड्यूटी अधिक थी।

AI image

क्लिनिकल ट्रायल की घोषणा अहम

डॉ. सुदीप गुप्ता ने बजट मे क्लिनिकल ट्रायल्स को बढ़ावा देने की घोषणा को भी अहम बताया। उन्होंने कहा, क्लीनिकल ट्रायल्स से न सिर्फ रिसर्च इकोसिस्टम मजबूत होगा, बल्कि उन मरीजों को भी नए और बेहतर इलाज विकल्प मिलेंगे, जिनके लिए स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट खत्म हो चुके है। विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे मुंबई समेत देशभर के मरीजों को नई कैंसर दवाए ट्रायल के तहत मुफ्त मे मिलने की सम्भावना बढ़ेगी। डॉ. सेवंती ने बताया, सरकार द्वारा देशभर मे 1000 क्लिनिकल ट्रायल सेंटर्स खोलने की घोषणा भी ऑन्कोलॉजी क्षेत्र मे गेम चेंजर हो सकती है।

> कैंसर की दवाओं पर ड्यूटी मे छूट से इन दवाओं तक मरीजों की पहुंच निश्चित रूप से बढ़ेगी। इलाज की लागत कुछ हद तक कम होगी, लेकिन इन दवाओं की मूल कीमतें दवा कंपनियों द्वारा काफी ऊंची रखी जाती है, जिससे इनका लाभ पाने वाले अधिकांश मरीजों के लिए अब भी आर्थिक बाधाएं बनी रहती है।
> - डॉ. सौरिश्च प्रमोश, निदेशक, टाटा मेमोरियल अस्पताल

मुंबई से निकलेंगे कई MSME 'चैंपियन'

NBT रिपोर्ट, मुंबई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा, सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSME) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है, जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित फंड भी शामिल है। बिरला सोलर प्रोजेक्ट कंपनी के फाउंडर योगेश बिरला के अनुसार, रिन्यूएबल सेक्टर को सोलर पावर ग्रिड नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए एलेक्ट्रोकेशन पिछले बजट एलेक्ट्रोकेशन से 18% ज्यादा है। यह भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूसर बनाएगा और कई MSME 'चैंपियन इस सेक्टर मे आएंगे।

जेम्स व जूलरी इंडस्ट्री के लिए

GJEPC के चेयरमैन किरित भंसाली ने कहा, 'बजट भारत के रत्न और आभूषण सेक्टर को नई गति देता है। यह लिक्विडिटी मे सुधार करता है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है।' वहीं गीपनका जेम्स के प्रमुख मनमोहन गोयनका ने बताया कि बजट वैल्यू चेन मे एक्सपोर्ट को मजबूत करने वाला है और SEZ से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में रियायती ड्यूटी पर सीमित बिक्री की भी अच्छा कदम है।' GJC के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने कहा, बजट रत्न और आभूषण उद्योग के प्रति एक स्थिर और संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये व्यापार को भरोसा देते है।'

ट्रेडिंग जोन की भूमिका से निकल सप्लाई चेन में चमकेगी मुंबई

मुंबई फिर बन सकती टेक्सटाइल सेक्टर की शान!

Sudha.Shrimali@timesofindia.com

मुंबई : सरकार ने रविवार को लेबर इंटेंसिव सेक्टर में ग्रोथ को गति देने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्रम की घोषणा की और 'मेगा टेक्सटाइल पार्क' स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक्सटाइल सेक्टर में दिए गए बजट मे प्रस्तावित नैशनल फाइबर स्कीम से लेकर तमाम अनरजेमेंट से ट्रेडिंग जोन भर रह गई मुंबई लॉन्ग टर्म में फिर से टेक्सटाइल सेक्टर की शान बन सकती है।

क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI) के चीफ मेंटोर राहुल मेहता का कहना है कि मुंबई ट्रेडिंग जोन पहले से है और मेगा टेक्सटाइल पार्क, नैशनल फाइबर स्कीम, टेक्स-इको इनिसिएटिव जैसी अनाउंसमेंट से यहां मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने से भविष्य मे सप्लाई की वैल्यू चैन में मुंबई अहम रोल अदा कर सकती है।

- **FTAs की वजह से खुलने वाले बड़े मौको का फायदा:** ICC नेशनल टेक्सटाइल के चेयरमैन संजय जैन का कहना है कि टेक्सटाइल और कपड़े की इंडस्ट्री से जुड़े ऐलान क्लस्टर बढ़ाने के लिए है, ताकि इंडस्ट्री साल ही मे साइन किए गए FTAs की वजह से खुलने वाले बड़े मौकों का फायदा उठाने के लिए तैयार हो सके। पारंपरिक टेक्सटाइल क्लस्टर के आधुनिकीकरण के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रोजगार सृजन योजना का विस्तार भी अहम साबित होगा। मफतलाल इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रियव्रत मफतलाल का कहना है कि विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ कपड़ा एवं परिधानों को बढ़ावा देने के लिए एक 'टेक्स-इको इनिशिएटिव' शुरू होगा।
- **फाइबर से फैशन की चेन मे अहम रोल:** भारत मर्चेंट चैंबर के ट्रस्टी राजीव सिंघल का कहना है कि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के 5 ज्ञ-खंड के तहत रेशम, ऊन और नए जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर मे आत्मनिर्भरता के लिए 'नेशनल फाइबर स्कीम' (राष्ट्रीय धागा योजना) की घोषणा का लाभ मुंबई व महाराष्ट्र के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स लेकर चैंपियन की भूमिका निभा सकते है। वहीं, हिन्दुस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट सुशील गांडिया का मानना है कि सरकार ने मशीनरी के लिए पूंजी सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य जांच और प्रमाणीकरण केंद्र के साथ पारंपरिक क्लस्टर को आधुनिक बनाने के लिए 'टेक्सटाइल विस्तार एवं रोजगार योजना' का प्रस्ताव दिया।

पॉलिटिकल रिएक्शन्स

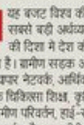

देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

यह बजट विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा मे देश की प्रगति का प्रतिबिंब है। ग्रामीण सड़क अवसंरचना, कृषि व्यापार नेटवर्क, आर्थिक क्लस्टर, तृतीयक चिकित्सा शिक्षा, कृषि व्यापार और ग्रामीण परिवर्तन, हाई-स्पीड ट्रेन, मेट्रो नेटवर्क और एमएटीपी-3 के लिए राज्य को पर्याप्त धनराशि दी गई है। इससे अगले महीने राज्य के बजट को बेहतर बनाने मे मदद मिलेगी।

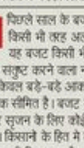

हर्षवर्धन सपकाल
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस

पिछले साल के बजट से किसी भी तरह अलग नही है। यह बजट किसी भी समाज वर्ग को संतुष्ट करने वाला नही है, बल्कि केवल बड़े-बड़े आंकड़ो और दावों तक सीमित है। बजट मे नए रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस नीति नही है। किसानों के हित मे कोई ठोस प्रावधान नही किया गया है। महंगाई पर काबू पाने के लिए भी कोई ठोस कदम नही उठाया गया है।

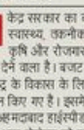

सुनेत्रा पवार
DCM, महाराष्ट्र

केंद्र सरकार का बजट स्वास्थ्य, तकनीक, उद्योग, कृषि और रोजगार को बढ़ावा देने वाला है। बजट मे महाराष्ट्र के विकास के लिए कई प्रावधान किए गए है। इसमे मेट्रो, मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड रेलवे सहित अन्य प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इससे महाराष्ट्र मे विकास को गति मिलेगी और निवेश बढ़ेगा।

एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

यह बजट विकास इंजन के रूप मे काम करेगा। मुंबई एस राज्य के शेष हिस्सों को भी महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करेगा। बजट मे छोटे शहरो के विकास मे पर ध्यान दिया गया है। नवर निगम बांड पर 100 करोड़ रुपये की छूट राज्य के नगर निगमो को मजबूत करने वाला कदम है। मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा से राज्य को काफी बढ़ावा मिलेगा।

मंगल प्रभात लोढ़ा
मंत्री, पर्यटन विकास विकास

विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने मे यह बजट मील का पत्थर साबित होगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 मे 7.4% विकास दर के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया है। मध्यम वर्ग, गरीबी, किसानों को समृद्ध बनाने वाला बजट है। 'बायो-फार्म मिशन' से न केवल दवाओं की कीमतें कम होगी, बल्कि भारत दवा निर्माण का ग्लोबल हब बनने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

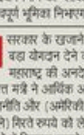

आदित्य ठाकरे
विधायक, शिवसेना उद्धव सेना

सरकार के खजाने मे सबसे बड़ा योगदान देने वाले महाराष्ट्र की अनदेखी की गई। वित्त मंत्री ने आर्थिक अस्थिरता, भू-राजनीति और (अमेरिकी डॉलर के मुकाबले) गिरते रुपये को लेकर नागरिकों में विश्वास जगाने से जानबूझकर परहेज किया है। कभी गिरते रुपये के कारण उनकी पार्टी (BJP) ने बहुत हो-हल्ला मचाया था।

एक्सपर्ट रिएक्शन्स

मनोज जालान, अध्यक्ष, भारत मर्चेंट्स चेंबर

नैशनल फाइबर स्कीम कच्चे माल की आपूर्ति बनाए रखने व दामों मे स्थिरता के लिए ऐतिहासिक कदम है। मेगा टेक्सटाइल पार्क, समर्थ 2.0 स्कीम को ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट पर नजर रखते हुए लाया जा रहा है। 10 हजार करोड़ MSME ग्रोथ फंड के निर्माण से वैंचियर MSME को मध्यम कॉर्पोरेट्स में बदलने मे मदद मिलेगी। 4.3% के राजकोषीय घाटे को बनाए रखने से भारतीय व्यापार के लिए अगले 10 वर्ष के लिए यह बजट ठोस नींव रखता है।

सुशील गांडिया, प्रेसिडेंट, हिन्दुस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स

बजट भले ही शेयर बाजार को पसंद नही आया हो, लेकिन वित्त मंत्री ने विकास को स्थिरता देने के उपाय किए है। घरेलू उत्पादन एवं सेवाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए व्यवसाय मे सरलता लाने के प्रयास किए है। बहुत सारे टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के जरिए कपड़ा उद्योग को गति प्रदान करने की कोशिश की गई है। आयकर कानून मे तर्कसंगत बदलाव अच्छी शुरुआत है।

नटराज डागा, निवेश सलाहकार

बजट मे STT बढ़ाने से शेयर बाजार कारोबारी ठगा हुआ महसूस कर रहे है। STT की दरों मे बढ़ोतरी निवेशकों का मनोबल तोड़ने का काम कर सकती है। हालांकि, LTCG यथावत और STT बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि सरकार लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करना चाहती है और सट्टा प्रवृत्ति पर लगाम लगाना चाहती है, जो कुछ हद तक जरूरी भी है।

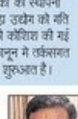

मनोज भंडारी, अध्यक्ष, विजेयर्स मार्बल डीलर असोसिएशन

बजट 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने की ओर एक सकारात्मक कदम है। बजट का सबसे प्रभाव यह है कि यह 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने के लिए मजबूत और भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। इसमे रेलवे से लेकर डिजिटल बुनियादी ढांचे तक हर क्षेत्र मे रिकॉर्ड-तोड़ निवेश किया जा रहा है।

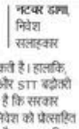

अभिषेक तिवारी, CA, पूर्व चेयरमैन वेस्टर्न ब्रांच ICAI

क्लाउड डेटा सर्विसेज और डेटा सेंटर को बढ़ावा देकर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी गई है। भारत मे डेटा सेंटर स्थापित कर क्लाउड सेवाएं देने वाली कंपनियों को दीर्घकालिक टैक्स हॉलिडे दिया जाएगा। इससे विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा मिलेगा। क्लाउड सर्विसेज पर टैक्स प्रोत्साहन भारतीय अर्थव्यवस्था मे निवेश, रोजगार और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा मे मजबूत आधार देगा।

विकास को देंगे रफ्तार: केंद्रीय बजट से महाराष्ट्र को मिलेंगे करीब 1 लाख करोड़

NBT रिपोर्ट, मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट से महाराष्ट्र को करीब एक लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा, केंद्रीय करों में महाराष्ट्र का हिस्सा 98,306 करोड़ रुपये के करीब होगा। वैसे, बजट के प्रारंभिक आकलन के अनुसार कई प्रोजेक्ट के लिए 12,355 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस तरह से राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे।

> मुख्यमंत्री का दावा, केंद्रीय करों में महाराष्ट्र का हिस्सा 98,306 करोड़ रुपये

रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा, बजट में योजनाबद्ध शहरीकरण, उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहन, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए ठोस कदम उठाए गए है। सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया है, जबकि पहले यह राशि केवल 1 लाख करोड़ रुपये तक ही सीमित थी। मुख्यमंत्री ने कहा, 5 लाख की आबादी वाले शहरों को ध्यान में रखकर शहरी विकास की एकीकृत योजना बनाई गई है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों को दिशा, गति और पर्याप्त निधि मिलेगी। इसका बड़ा लाभ महाराष्ट्र को होगा। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी योजना की सफलता के बाद महिलाओं के लिए अलग मॉल और उद्योगों के मौके उपलब्ध कराने की योजना उपयोगी है।

मराठवाड़ा व पश्चिम महाराष्ट्र को फ़ायदा

सीएम फडणवीस ने कहा, बजट मे वित्त मंत्री ने प्रत्येक जिले मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र मे जिला अस्पतालों मे आपात चिकित्सा व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। मुंबई-पुणे और पुणे-हैदराबाद हाई-स्पीड कॉरिडोर से जीडीपी मे बढ़ोत्तरी होगी। पुणे-हैदराबाद कॉरिडोर से मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र को विशेष लाभ मिलेगा। शोध हब के लिए अगले 5 वर्षों मे 5-5 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे, जिससे MMR, पुणे, नागपुर शोध हब को लाभ होगा।

NBT Facebook LIVE

बजट का संकेत साफ़, इकोनॉमी मज़बूत तो निवेश की राह भी सुरक्षित

आम बजट मे भले ही बाजार को चौंकाने वाले ऐलान न हो, लेकिन निवेशकों के लिए इसमे संदेश साफ है। शॉर्ट टर्म उतार-चढ़ाव से घबराने के बजाय अनुशासन व लंबी अवधि की रणनीति पर टिके रहना जरूरी है। नवभारत टाइम्स (NBT) के साथ फेसबुक लाइव बातचीत मे सुधा श्रीमाली व भविन पंड्या ने निवेश विशेषज्ञों से आम निवेशको के लिए सही रणनीति पर विस्तार से बात की। एक्सपर्ट्स के अनुसार, यह बजट लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फिस्कल अनुशासन और सस्टेनेबल निवेश को मजबूत करता है।

निवेशकों के लिए संदेश, घबराने की ज़रूरत नहीं

इस बार का केंद्रीय बजट किसी बड़े सरप्राइज के साथ नहीं आया। सरकार ने शॉर्ट टर्म लोकलुभावन फैसलों से दूरी रखते हुए नीति की निरंतरता, फिस्कल अनुशासन और इंफ्रास्ट्रक्चर-मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस बनाए रखा है। ऐसे मे सवाल यह नहीं है कि बाजार आज कैसे रिएक्ट कर रहा है, बल्कि यह है कि आम निवेशक को इस बजट के बाद क्या करना चाहिए।

- **चाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया से घबराएं नहीं :** बजट के दिन बाजार में कमजोरी दिखी, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे शॉर्ट टर्म रिएक्शन मानते है। सिम्बोरिटी ट्रेनिंग टैक्स (STT) बढ़ने से खासकर फ्यूचर्स-ऑप्शंस सेगमेंट में नेगेटिव सेंटिमेंट बना। यह गिरावट घबराने की वजह नहीं है, क्योंकि बजट के दिन बाजार का गिरेटिव रहना कोई नई बात नहीं है।
- **डेरिवेटिव नहीं, लॉन्ग टर्म निवेश को चढ़ावा:** STT बढ़ाने का सीधा संदेश यह है कि सरकार और रेगुलेटर्स रिटेल निवेशकों को अत्यधिक सट्टेबाजी से दूर रखना चाहते है। एक्सपर्ट्स साफ कहते है कि आम निवेशक के लिए डेरिवेटिव नहीं, बैस्केट में लॉन्ग टर्म निवेश ही सही रणनीति है।
- **एसेट एलोकेशन सबसे अहम फैसला:** निवेशकों के लिए सबसे जरूरी सलाह यह है कि वे अपने लक्ष्य और जोखिम क्षमता के अनुसार एसेट एलोकेशन तय करें। सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट मे रहना सही नहीं है।
- **म्यूचुअल फंड अहम निवेशक के लिए बेहतर साधन:** जिन निवेशकों के पास समय और विशेषज्ञता नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर विकल्प है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि पेटेंबेलिनो मे फ्लेक्सी-कैप, लार्ज-एंड-मिडकैप और मल्टी-कैप फंड्स का संतुलित मिश्रण रखा जाए। साल मे एक बार रिब्यू पर्याप्त है, बार-बार बदलाव नुकसानदेह हो सकता है।
- **गोल्ड-सिल्वर मे फोमो से बचे:** हाल के महीनों में गोल्ड और सिल्वर की तेजी ने कई निवेशकों को आकर्षित किया, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे 'रिसेंसी बायस' मानते है। गोल्ड को पेटेंबेलिनो मे हेज के तौर पर रखना ठीक है, लेकिन इक्विटी से पैसा निकालकर गोल्ड मे जाना सही रणनीति नहीं है। लंबी अवधि मे इक्विटी का रिटर्न गोल्ड से बेहतर रहता है।

श्वेता रजानी, हेड, म्युचुअल फंड, आनंद राठी वेल्थ

बजट में सरप्राइज़ नहीं, लेकिन निवेशकों के लिए साफ़ दिशा

इस बार का केंद्रीय बजट भले ही किसी बड़े सरप्राइज के साथ न आया हो, लेकिन यह भारत की अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में मजबूत करने की साफ रणनीति पेश करता है। सरकार ने शॉर्ट टर्म लोकलुभावन फैसलों से बचते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और न्यू-एज इंडस्ट्री पर फोकस रखा है। इक्विटी निवेशकों के लिए आगे राह अच्छी है।

- **सेकुलेशन नहीं, सस्टेनेबल निवेश का संकेत:** बजट का बड़ा मैसेज यह है कि सरकार अब फ्यूचर्स-ऑप्शंस जैसी सट्टा गतिविधियों को हतोत्साहित करना चाहती है। STT बढ़ने का असर सफारीज पर रिटेल निवेशकों पर पड़ेगा। बड़ी संख्या में छोटे निवेशकों ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पैसा गंवाया है। ऐसे मे यह कदम लॉन्ग टर्म निवेश को बढ़ावा देने वाला माना जा सकता है।
- **गिरते या सहड्रावेज बाजार मे घबराने की जरूरत नहीं:** पिछले 12-15 महीनों में बाजार मे तेजी नहीं दिखी और कई सेक्टरों में करेक्शन आया है, लेकिन यही समय स्टैगर्ड निवेश का है। एक्सपर्ट्स पिछले लगने के बजाय 6-5 महीनों में चरणबद्ध निवेश करने से जोखिम कम होता है और औसत लागत बेहतर बनती है।
- **म्युचुअल फंड मे डायवर्सिफिकेशन सबसे अहम:** आम निवेशक के लिए डायरेक्ट शेयर चुनना मुश्किल होता है। ऐसे मे सलाह है कि पेटेंबेलिनो का मुख्य हिस्सा डाइवर्सिफाइड म्युचुअल फंड्स में हो। इस समय मैन्युफैक्चरिंग व कंजेप्शन लेड ज्यादा है, तो स्पेसिफिक म्युचुअल फंड स्कीम अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
- **कंजम्प्शन सेक्टर पर लॉन्ग टर्म दांव:** जैसे-जैसे भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यही वजह है कि कंजम्प्शन एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म थीम बनती दिख रही है। अच्छी गुणवत्ता वाली कंजम्प्शन कंपनियां आने वाले वर्षों मे बेहतर रिटर्न दे सकती है।
- **गोल्ड-सिल्वर : फोमो से बचे, संतुलन रखे:** गोल्ड को रिटर्न के बजाय पेटेंबेलिनो के रिस्क हेज के रूप मे देखना चाहिए। वहीं, सिल्वर मे हालिया तेजी के बाद फोमो के आधार पर निवेश से बचने की सलाह है। कीमतों में ठोस करेक्शन के बाद ही इसमे एंट्री समझदारी मानी जाएगी।

अनूप भैया, फाउंडर, मनी हनी फाइनेंशियल सर्विसेज

NOTE : -

[: राजस्थान पत्रिका , दैनिक जागरण delhi, नवभारत टाइम्स delhi, अमर उजाला delhi, हिन्दुस्तान delhi, Pioneer hindi delhi, जनसत्ता delhi,]

English NEWSPAPERS
[Times Of India delhi, Indian Express delhi, The Hindu delhi, Financial Express delhi, economic times delhi , the Pioneer english delhi , the tribune delhi] ETC.

We are providing all news paper pdf hindi and English want to read daily newspapers by pdf please msg me on telegram

2. आकाशवाणी (AUDIO)

whatsapp Group ka link pane ke liye Newspaper_pdf_bot par jaye.

Click here to contact:-https://t.me/Newspaper_pdf_bot
Or type in Search box of Telegram
@Newspaper_pdf_bot And you will find a channel
BACKUP GROUP LINK
https://t.me/joinchat/5P9EL1JaqoYzNTI1

Hindi-English News Paper
Website:- onlineftp.in